IASBABA'S MONTHLY MAGAZINE

June 2021

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर

चीन की बाल नीति

G-7 और भारत

क्रिप्टोकरेंसी और RBI

मॉडल करियेदारी अधिनियम

WWW.IASBABA.COM

प्रस्तावना

UPSC सिविल सेवा परीक्षा के परीक्षा प्रारूप में वर्तमान बदलाव के साथ, सामान्य अध्ययन-II और सामान्य अध्ययन III को साधारणतः समसामसयकी से प्रतिस्थापित कर दिया गया है। इसके अलावा, यूपीएससी की हालिया प्रवृत्ति के अनुसार, लगभग सभी प्रश्न समाचार-आधारित होने के बजाय मुद्दों पर आधारित हैं। इसलिए, तैयारी के लिए सही दृष्टिकोण केवल समाचार पढ़ने के बजाय मुद्दों को तयैार करना है।

इसे ध्यान में रखते हुए, हमारी वेबसाइट **www.iasbaba.com** दैनिक आधार पर मुद्दों पर अधिक ध्यान केंद्रित करते हुए वर्तमान मामलों को कवर करती है। यह आपको विभिन्न राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्रों जैसे हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, बिजनेस स्टैंडर्ड, लाइवमिंट, बिजनेस लाइन और अन्य महत्वपूर्ण ऑनलाइन स्रोतों से दिन के प्रासंगिक समाचार प्राप्त करने में मदद करेगा। समय के साथ, इनमें से कुछ समाचार प्रसंग महत्वपूर्ण मुद्दे बन जाएंगे।

UPSC ऐसे मुद्दों से सम्बंधित प्रश्न और इन पर सामान्य राय पर आधारित प्रश्न पूछती है। ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए सामान्य जागरूकता और मुद्दे की समग्र समझ की आवश्यकता होती है। इसलिए, हम उम्मीदवारों के बीच सही समझ पैदा करना चाहते हैं – 'इन मुद्दों को कैसे कवर किया जाए ?

यह IASbaba की मासिक पत्रिका का 66 वां संस्करण है। यह संस्करण उन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करता है जो JUNE-2021 के महीने में खबरों में थे, जिन्हें**https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/**से भी एक्सेस किया जा सकता है।

IASBABA से VALUE ADDITIONS

- **Think और Connectng the dots अवश्य पढ़ें और कनेक्ट करें।**
- **इसके अलावा, हमने Prelim और mains पर ध्यान केंद्रित करने के लिए snippets और टेस्ट योर नॉलेज (दैनिक करंट अफेयर्स पर आधारितPrelims MCQs) प्रस्तुत किया हैं जो आपको बेहतर revisionके लिए मार्गदर्शन करेंगे।**
- '**Must Read' section,**आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से पढ़ने के लिए महत्वपूर्ण लिंक प्रदान करता है। यह सुनिश्चित करेगा कि, आप दैनिक आधार पर विभिन्न समाचार पत्रों से किसी भी महत्वपूर्ण समाचार / संपादकीय को याद नहीं करेंगे।
- प्रत्येक समाचार लेख के तहत, **Connectng the dots** एक मुद्दे के विभिन्न पहलुओं पर जुड़ने और विचार करने की आपकी सोच को सुविधाजनक बनाता है। मूल रूप से, यह आपको बहु-आयामी दृश्य-बिंदु से एक मुद्दे को समझने में मदद करता है। आप मेन्स या इंटरव्यू देते समय इसके महत्व को समझेंगे।

'**Must Read' section**: हमने उन्हें पत्रिका में शामिल नहीं किया है। दैनिक आधार पर DNA का अनसुरण करने वाले इसका अनुसरण कर सकते हैं-

https://iasbaba.com/current-affairs-for-ias-upsc-exams/

"Tell my mistakes to me not to others, because these are to be corrected by me, not by them."

विषय वस्तु

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

- नासिक के त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में खोजी गईं तीन नई गुफाएं
- वर्ष जून-सितंबर तक देश में लंबी अवधि के औसत (एलपीए) में करीब 101 फीसदी बारिश होगी
- स्वदेशी रूप से विकसित 'एंटी-हेल गन' (ANTI-HAIL GUN)
- नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने 'दक्षिणी महासागर' को दुनिया का पांचवा महासागर घोषित किया
- गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: लोथल

राजनीति / शासन

- मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत लाया गया
- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष नियुक्त
- आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर
- तुलु भाषा बोलने वालों ने मांगा आधिकारिक भाषा का दर्जा
- UAPA का दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं को दी जमानत
- न्यायपालिका और AI
- लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका
- जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आरंभ
- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)
- न्यायाधीशों का बहिष्कार
- रैंक च्वाइस वोटिंग
- न्यायालयों को खोलना

सामाजिक मुद्दे / वेलफ़ेयर

- प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक
- स्कूल न जाने वाले बच्चों के डेटा के संकलन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल
- अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20
- सीखने का आकलन
- युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार
- बाल श्रम और महामारी
- शिक्षा में अंग्रेजी भाषा
- दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट
- राशन कार्ड सुधार
- लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता: बाल स्वराज पोर्टल

स्वास्थय समस्या

- संशोधित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का शुभारंभ
- क्षतिपूर्ति और वैक्सीन मूल्य निर्धारण
- UNGA का संकल्प 75/260
- तीसरी लहर की तैयारी
- भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी
- सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन कई गुना बढ़ा
- WHO ने गिनी में इबोला के प्रकोप की घोषणा की

सरकारी योजनाएँ

- बच्चों के लिए PM-CARES योजना
- सेज (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल का शुभारंभ
- स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II
- उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक माप तौल मशीनें
- मिशन कर्मयोगी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन
- परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 वर्ष

अंतरराष्ट्रीय

- चीन की बाल नीति
- कैबिनेट ने मास मीडिया सहयोग पर SCO समझौते को कार्योत्तर मंजूरी दी
- विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस
- आई-फैमिलिया (I-Familia) : लापता व्यक्तियों की पहचान के लिये वैश्विक डेटाबेस
- USA और UK के बीच न्यू अटलांटिक चार्टर
- यूरोपीय संघ ने श्रीलंका को दिए गए अपने GSP+दर्जे पर विचार करने का आग्रह किया
- FAO सम्मेलन का 42वां सत्र
- अदन की खाड़ी में पहला भारतीय नौसेना-यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) अभ्यास
- यूएस-रूस : बाइडेन-पुतिन मुलाकात
- अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) की 60 वीं वर्षगांठ
- G-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक
- अभ्यास 'सी ब्रीज 2021'

भारत और विश्व

- ब्रिक्स : शक्तिशाली पांच का एक साथ आना
- G-7 और भारत

- गलवान के एक साल बाद भारत-चीन संबंध
- भारत ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया

अर्थव्यवस्था

- भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संकुचन 7.3%
- विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया
- 'सतत' पहल को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शुरू की गई
- SDO घोषित होने वाला पहला संस्थान बना RDSO
- भारत की जीडीपी में गिरावट
- भारतीय आर्थिक चुनौतियां
- क्रिप्टोकरेंसी और RBI
- आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 4.0
- एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर केरल, बिहार का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर
- केंद्र ने राज्यों से मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा
- तेल की कीमतों में वृद्धि
- विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट
- 2020-21 के लिए भारत का कृषि व्यापार सारांश
- विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021
- FDI अंतर्वाह
- फेडरल रिजर्व सिग्नल और भारतीय बाजार
- नए वित्तीय प्रोत्साहन की मांग
- ई-कॉमर्स साइटों पर 'फ्लैश बिक्री' पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव
- ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए ड्राफ्ट नियम
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि
- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त के विनियमन पर एक परामर्शदायी दस्तावेज
- प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति हस्तांतरित की
- लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

कृषि

- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP)
- बीज मिनीकिट कार्यक्रम का शुभारंभ
- मॉडल किरायेदारी अधिनियम
- क्या 'लाभदायक' MSPs ग्रामीण मांग को बढ़ा रहे हैं?
- धान, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि
- गेहूं और चावल में पोषक तत्वों की हानि: ICAR अध्ययन

- उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए बायोटेक-किसान कार्यक्रम
- नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल का ई-लॉन्च किया जाएगा

पर्यावरण/ प्रदूषण

- 'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट
- भारतीय शहरों के लिए हरित भविष्य
- हिंदू कुश हिमालय पर्वत पर UNDP रिपोर्ट
- जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन (NMBHWB)
- मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता
- विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट 'चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट'
- अवैध एचटी बीटी (HTBt) कपास के बीज की बिक्री दोगुनी
- ग्रेट बैरियर रीफ को 'खतरे में' विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई

समाचारों में जंतु / राष्ट्रीय उद्यान

- समाचार में प्रजातियां: लिटोरिया मीरा
- देहिंग पटकाई (Dehing Patkai) बना असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान
- खबरों में प्रजातियां: घड़ियाल
- ओलिव रिडले कछुओं के लिये ऑपरेशन ओलिविया
- बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य: असम

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

- देविका नदी राष्ट्रीय परियोजना: जम्मू और कश्मीर
- भारतीय रेलवे को मिला 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम
- भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: नीति आयोग
- भारत का इथेनॉल रोडमैप
- फेम-2 योजना में संशोधन
- डगमारा जलविद्युत परियोजना: बिहार
- भारत में सीप्लेन सेवाओं के लिये समझौता ज्ञापन
- तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा
- डीप ओशन मिशन
- अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021
- पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी
- सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य
- विद्युत क्षेत्र: डिस्कॉम (DISCOMS) के साथ मुद्दे

विज्ञान और तकनीक

- एंबीटैग (AmbiTAG)
- लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तकनीक
- प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST): चीन का कृत्रिम सूर्य
- फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRBs) कैटलॉग का सबसे बड़ा संग्रह
- पैसिफाइ (PASIPHAE) : अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना
- सिंथेटिक बायोलॉजी और जैव सुरक्षा
- मानव जीनोम का 100% अनुक्रमित
- महाराष्ट्र में नए डॉपलर रडार: IMD
- रोबो सेपियन्स: काम का भविष्य
- अन्य सेवा प्रदाताओं (OSPs) के लिए दिशानिर्देश
- 2020 में अक्षय विद्युत उत्पादन लागत: IRENA
- विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़: असम

आपदाप्रबंधन

- ग्लोबल वार्मिंग के कारण लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास समुद्र जल स्तर में वृद्धि
- यूएस हीट वेव

रक्षा / आंतरिक सुरक्षा / सुरक्षा

- परियोजना P 75 (I) के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण स्वीकृत
- रक्षा क्षेत्र में हालिया सुधार
- रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार
- परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट
- युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण संबंधी नीति
- OFB निगमीकरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी
- साइबर धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन शुरू
- क्रिवाक स्टील्थ फ्रिगेट्स
- सेना ने 1,750 फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री लड़ाकू वाहनों के लिए निविदा जारी की
- इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स

विविध

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

जून 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तर कुंजी

इतिहास / संस्कृति / भूगोल

नासिक के त्रिरश्मी बौद्ध गुफा परिसर में खोजी गईं तीन नई गुफाएं

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I- संस्कृति

सुर्खियों में-

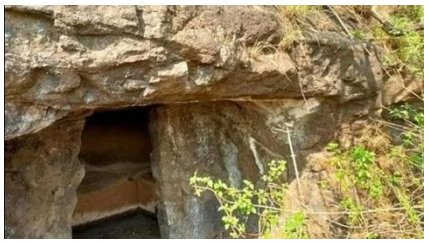

- भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) को महाराष्ट्र के नासिक में त्रिरश्मी पहाड़ी में तीन गुफाओं की खोज की है।
- त्रिरश्मी बौद्ध गुफाएं, जिन्हें पांडव लेनी के नाम से भी जाना जाता है, ये इसी स्थान पर स्थित हैं।

गुफाओं के बारे में अधिक जानकारी

- नई पाई गई गुफाओं को त्रिरश्मी गुफाओं से भी पुराना माना जाता है।
- इन्हें बौद्ध भिक्षुओं का आवास माना जाता है।
- सभी गुफाओं में बरामदे और भिक्षुओं के लिए विशिष्ट वर्गाकार पत्थर का मंच है।
- कान्हेरी और वाई गुफाओं के समान ही भिक्षुओं के ध्यान करने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

त्रिरश्मी गुफाएं

- त्रिरश्मी या पांडव लेनी गुफाएं 25 गुफाओं का समूह हैं।
- जो दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व और छठी शताब्दी ईस्वी के बीच त्रि-रश्मी पहाड़ी से उकेरी गई हैं।
- यह एक ASI संरक्षित स्थल और एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है।
- नासिक में बौद्ध मूर्तियां और गुफाएं बौद्ध धर्म की हीनयान परंपरा का प्रतिनिधित्व करने वाली भारतीय रॉक-कट वास्तुकला के प्रारंभिक उदाहरण हैं।

महायान बौद्ध धर्म	हीनयान बौद्ध धर्म
• यह गौतम बुद्ध को एक दिव्य प्राणी मानता है जो अपने अनुयायियों को निर्वाण प्राप्त करने में मदद करेगा। • इसके अनुयायी चीन, (दक्षिण) कोरिया, जापान और तिब्बत में पाए जाते हैं। • शास्त्र संस्कृत में लिखे गए थे। • यह 500 ईसा पूर्व के आसपास फलने-फूलने लगा।	• यह गौतम बुद्ध को निर्वाण प्राप्त करने वाले एक साधारण मनुष्य के रूप में मानता है। • इसके अनुयायी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया और लाओस में पाए जाते हैं। • पालि में शास्त्र लिखे गए थे। • यह लगभग 250 ईसा पूर्व में फलने-फूलने लगा।

संबंधित आलेख

धर्मचक्र दिवस पर बौद्ध दर्शन

वर्ष जून-सितंबर तक देश में लंबी अवधि के औसत (एलपीए) में करीब 101 फीसदी बारिश होगी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I-भूगोल

सुर्खियों में-

- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, जून-सितंबर में मानसून की बारिश 88 सेमी की लंबी अवधि के औसत (LPA) का 101% होगी।
- यह अभी भी 'सामान्य' वर्षा की ओर इंगित करता है, जो लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के 96-104 फीसदी के दायरे में रहने की संभावना है।

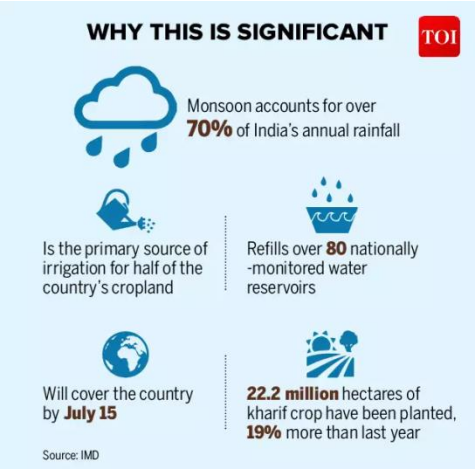

लंबी अवधि के औसत (एलपीए) के बारे में

- यह 1951 और 2001 के बीच 50 वर्षों की अवधि में प्राप्त वर्षा का औसत है, जो लगभग 89 सेमी वर्षा है।
- हर साल मानसून के मौसम के लिए मात्रात्मक वर्षा की भविष्यवाणी करते समय इसे एक बेंचमार्क के रूप में रखा जाता है।

वर्षा की श्रेणियाँ

- IMD अखिल भारतीय पैमाने पर पांच वर्षा वितरण श्रेणियों का रखरखाव करता है:
  - **अधिक:** यदि वर्षा इस एलपीए के 110% से अधिक है।
  - **सामान्य से अधिक:** यदि वर्षा इस LPA के 104 से 110% के बीच है।
  - **सामान्य:** यदि वर्षा इस LPA के 96 से 104 % के बीच है।
  - **सामान्य से कम:** यदि वर्षा इस LPA के 90 से 96% के बीच है।
  - **कमी:** यदि वर्षा इस LPA के 90% से कम है।

स्वदेशी रूप से विकसित 'एंटी-हेल गन' (ANTI-HAIL GUN)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I- भूगोल और जीएस-II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- हिमाचल प्रदेश सरकार, ओलावृष्टि के कारण फ़सल को होने वाले नुकसान का सामना कर रहे बागवानों की मदद के लिये स्वदेशी रूप से विकसित 'एंटी-हेल गन' के उपयोग का परीक्षण करेगी।
- स्वदेशी बंदूकें आईआईटी बॉम्बे द्वारा नौनी (सोलन) में डॉ वाई एस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय के साथ विकसित की गई।

एंटी-हेल गन के बारे में

- एंटी-हेल गन (Anti-Hail Gun), बादलों में ओलों के विकास को बाधित करने के लिए 'आघात तरंगें' अर्थात शॉक वेव्स (Shock Waves) उत्पन्न करने वाली एक मशीन है।
- यह एक उल्टे टावर से मिलता-जुलता कई मीटर ऊँचा एक स्थिर ढांचा होता है और इसमें आकाश की ओर खुलने वाली एक लंबी और संकीर्ण शंक्वाकार नली लगी होती है।
- बंदूक के निचले हिस्से में एसिटिलीन गैस और हवा का विस्फोटक मिश्रण भरकर, इसे दागा जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 'शॉक वेव्स' निकलती हैं।
  - इन 'शॉक वेव्स' की गति सुपरसोनिक विमान से निकलने वाली तरंगों की भांति ध्वनि की गति से तेज होती है।

- माना जाता है कि ये शॉक वेव्स बादलों में पानी की बूंदों को ओलों में बदलने से रोकती हैं, ताकि वे बारिश की बूंदों के रूप में गिरें।

अन्य संबंधित तथ्य

ओला

- ओले गेंदों या बर्फ की अनियमित गांठों से बनी ठोस वर्षा होती है, जिनमें से प्रत्येक को ओला पत्थर कहा जाता है।
- ओलावृष्टि में ज्यादातर पानी की बर्फ होती है और इसका व्यास 5 मिमी और 15 सेमी के बीच होता है।
- कोई भी गरज, जो ओले उत्पन्न करती है और जमीन पर पहुँचती है, ओलावृष्टि कहलाती है।
- 1981 और 2015 के बीच देश भर में ओलावृष्टि के आईएमडी विश्लेषण के अनुसार, महाराष्ट्र भारत का सबसे अधिक ओलावृष्टि प्रवण राज्य है।

नेशनल जियोग्राफिक पत्रिका ने 'दक्षिणी महासागर' को घोषित किया दुनिया का पांचवा महासागर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II-भूगोल

सुर्खियों में-

- हाल ही में विश्व महासागर दिवस (8 जून) के अवसर पर नेशनल ज्योग्राफिक पत्रिका ने 'दक्षिणी महासागर' को दुनिया के पांचवें महासागर के रूप में मान्यता दी है।
- अन्य चार महासागर हैं: अटलांटिक, प्रशांत, हिंद और आर्कटिक महासागर।

दक्षिणी महासागर के बारे में

- दक्षिणी महासागर एकमात्र ऐसा महासागर है जो तीन अन्य महासागरों (प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर) को छूता है।
- यह एकमात्र महासागर है जो किसी महाद्वीप को पूरी तरह से घिरे होने के बजाय उसे घेरता है।
- इसे इसके अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट द्वारा भी परिभाषित किया गया है जो 34 मिलियन वर्ष पहले बना था।
- इसके अंटार्कटिक सर्कम्पोलर करंट द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया है जिसका विकास 34 मिलियन वर्ष पहले हुआ था।
    - अंटार्कटिका के चारों ओर पश्चिम से पूर्व की ओर मझासागरीय धाराएँ प्रवाहित होती है।

मान्यता का महत्व

- विश्व के महासागरों के संरक्षण की दिशा में कदम उठाना, विशेष रूप से एक संरक्षण स्पॉटलाइट की आवश्यकता वाले क्षेत्र पर जन जागरूकता पर ध्यान केंद्रित करना।
    - ग्लोबल वार्मिंग के कारण दक्षिणी महासागर के तेज़ी से गर्म होने के अलावा, क्रिल और पेटागोनियन टूथफिश जैसी मछलियों की कमी दशकों से चिंता का विषय रहा है।

गुजरात में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर: लोथल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I-संस्कृति

सुर्खियों में-

- संस्कृति मंत्रालय (MoC) और बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) ने गुजरात के लोथल में 'राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (NMHC) के विकास में सहयोग' के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

लोथल के बारे में

- यह 2400 ईसा पूर्व की प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख शहरों में से एक था।

- यहाँ एक डॉकयार्ड मिला है जहाँ समुद्र से और नदी के रास्ते नावें और जहाज आते थे।

राजनीति / शासन

मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत लाया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- महाराष्ट्र में मराठा समुदाय को आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कोटे के तहत लाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इससे पहले, सुप्रीम कोर्ट ने नौकरियों और शिक्षा में SEBC आरक्षण को समाप्त कर दिया था।
- इससे राज्य सरकार के लिए मराठों को ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ देना संभव हुआ।
- सरकार के प्रस्ताव के अनुसार, अल्पसंख्यक संस्थानों को छोड़कर, ईडब्ल्यूएस के मानदंडों को पूरा करने वाला व्यक्ति शैक्षणिक संस्थानों में 10% आरक्षण के लिए पात्र होगा।
- यह राज्य सरकार की भर्ती के लिए भी लागू होगा।
- यह आरक्षण मौजूदा आरक्षण से ऊपर होगा।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के नए अध्यक्ष नियुक्त

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II- वैधानिक निकाय; भारतीय राजव्यवस्था

सुर्खियों में-

- न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया।

यह समाचार क्यों महत्वपूर्ण रखती है?

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारत के सांविधिक निकायों में से एक है।
- **अन्य सांविधिक निकाय:**
    - राष्ट्रीय महिला आयोग
    - राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग
    - राष्ट्रीय हरित अधिकरण
    - राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग
    - सशस्त्र बल न्यायाधिकरण

अन्य सम्बंधित तथ्य

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

- NHRC की स्थापना 1993 में हुई थी।
- यह 1991 में पेरिस में आयोजित मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों पर पहली अंतरराष्ट्रीय कार्यशाला में अपनाए गए पेरिस सिद्धांतों के अनुरूप है।
- **स्थिति:** यह मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम (PHRA), 1993 के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली।
- **कार्य:**
    - मानव अधिकारों के उल्लंघन/राज्यों/अन्य की विफलताओं की जांच करने के लिए मानव अधिकारों के उल्लंघन को रोकने के लिए

    - आयोग मानवाधिकारों के बारे में शोध भी कर सकता है, विभिन्न माध्यमों से जागरूकता अभियान चला सकता है और गैर सरकारी संगठनों के काम को प्रोत्साहित कर सकता है।
- **संरचना:**
    - अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य और चार मानित सदस्य।
    - एक अध्यक्ष, भारत का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश होना चाहिए।
- **नियुक्ति:** NHRC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें शामिल हैं:
    - प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
    - गृह मंत्री
    - लोकसभा में विपक्ष के नेता
    - राज्यसभा में विपक्ष के नेता
    - लोकसभा अध्यक्ष
    - राज्य सभा के उपसभापति
- राष्ट्रपति विशिष्ट परिस्थितियों में उन्हें पद से हटा सकते हैं।

आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- पंचायती राज

सुर्खियों में-

- हाल ही में एक मॉडल पंचायत नागरिक चार्टर जारी किया गया।
- **मंत्रालय:** पंचायती राज मंत्रालय
- **तैयार किया गया :** राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRDPR) के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय (MoPR) द्वारा।

आदर्श पंचायत नागरिक चार्टर के बारे में

- यह 29 क्षेत्रों में सेवाओं के वितरण के लिए एक ढांचा है, जो स्थानीय सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) के साथ कार्यों को संरेखित करता है।
- इसका उद्देश्य क्या है?
    - लोगों को समयबद्ध तरीके से सेवाएं प्रदान करना
    - उनकी शिकायतों का निवारण
    - उनके जीवन में सुधार।
- पंचायतें इस ढांचे का उपयोग नागरिक चार्टर तैयार करने और 15 अगस्त, 2021 तक ग्राम सभा के एक प्रस्ताव के माध्यम से इसे अपनाने के लिए करेंगी।

अन्य संबंधित तथ्य

- राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD & PR)
- यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।
- इसका संस्थान हैदराबाद, तेलंगाना में स्थित है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गुवाहाटी, असम में इसका पूर्वोत्तर क्षेत्रीय केंद्र (NERC) भी है।

तुलु भाषा बोलने वालों ने मांगा आधिकारिक भाषा का दर्जा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - संविधान; आठवीं अनुसूची

सुर्खियों में-

- मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में तुलू भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्ज़ा देने और संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है।
    - तुलु (Tulu) एक द्रविड़ भाषा है जो मुख्य रूप से कर्नाटक के तटीय जिलों दक्षिण कन्नड़ तथा उडुपी और केरल के कासरगोड में बोली जाती है।

संघ की राजभाषा

- अनुच्छेद 343(1) में कहा गया है कि देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी संघ की राजभाषा होगी।
- राजभाषा अधिनियम, 1963 संघ के सभी आधिकारिक उद्देश्यों और संसद में व्यावसायिक लेनदेन के लिए हिंदी के अलावा अंग्रेजी के उपयोग का प्रावधान करता है।
- संविधान विभिन्न राज्यों की राजभाषा को निर्दिष्ट नहीं करता है।
- प्रत्येक राज्य का विधानमंडल राज्य में प्रयोग की जाने वाली किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को राज्य की राजभाषा के रूप में अपना सकता है।
- जब तक ऐसा नहीं हो जाता, तब तक अंग्रेजी राज्य की राजभाषा के रूप में प्रयोग की जाएगी।
- अधिकांश राज्यों ने राजभाषा के रूप में प्रमुख क्षेत्रीय भाषा को अपनाया है।

आठवीं अनुसूची में शामिल करना

- वर्तमान में, 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल करने के लिए ऐसा कोई मानदंड नहीं है।
- पाहवा (1996) और सीताकांत महापात्र (2003) समितियाँ भी कोई मानदंड विकसित करने में विफल रहीं।

8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं की सूची

(1) असमिया (2) बांग्ला (3) गुजराती (4) हिंदी (5) कन्नड़ (6) कश्मीरी (7) कोंकणी (8) मलयालम (9) मणिपुरी (10) मराठी (11) नेपाली (12) उड़िया (13) पंजाबी (14) संस्कृत (15) सिंधी (16) तमिल (17) तेलुगु (18) उर्दू (19) बोडो (20) संथाली (21) मैथिली और (22) डोगरी।

8वीं अनुसूची के तहत शामिल करने का महत्व

- राष्ट्र की राजभाषा के रूप में मान्यता।
- साहित्य अकादमी भाषा को पहचानने लगेगी।
- पुस्तकों का अन्य मान्यता प्राप्त भारतीय भाषाओं में अनुवाद किया जाएगा।
- संसद और राज्य विधानसभाओं में सांसद और विधायक इस भाषा में बोल सकते हैं।
- उम्मीदवार अखिल भारतीय प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे सिविल सेवा परीक्षा एक अनुसूचित भाषा में लिख सकते हैं।

UAPA का दुरुपयोग: दिल्ली हाईकोर्ट ने छात्र कार्यकर्ताओं को दी जमानत

संदर्भ: हाल ही में दिल्ली उच्च न्यायालय ने तीन छात्र कार्यकर्ताओं - आसिफ इकबाल तन्हा, नताशा नरवाल और देवांगना कलिता को जमानत देने का आदेश दिया। दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए एक साल से अधिक की जेल हुई।

क्या आपको पता है?

- संसद में गृह मंत्रालय द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार, 2019 में यूएपीए के तहत कुल 1126 मामले दर्ज किए गए, जो 2015 में 897 मामले से तेज वृद्धि है।

- UAPA, राज्य को चार्जशीट दाखिल करने की समय-सीमा में ढील देता है और जमानत के लिए उसकी कड़ी शर्तों में, राज्य को भारतीय दंड संहिता की तुलना में ज्यादा अधिकार देता है।
- छात्र कार्यकर्ताओं को क्यों गिरफ्तार किया गया और एक साल से अधिक समय तक जेल में रखा गया?
- तीनों छात्रों ने नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सीएए) के अधिनियमन का विरोध किया था।
- दिल्ली पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने दंगों को भी भड़काया और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू किया।
- UAPA के साथ बड़ी समस्या इसकी धारा 43 (D) (5) में निहित है। यदि पुलिस किसी व्यक्ति के लिये UAPA के अंतर्गत आरोप पत्र दायर करती है एवं यह मानने के लिये उचित आधार हैं कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य है तो व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता है जबकि, जमानत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार की सुरक्षा और गारंटी है।
- उन्हें जमानत भी नहीं मिली क्योंकि कानून के प्रावधान अभियुक्तों के खिलाफ हैं
    - आरोपी को अदालत को दिखाना होगा कि आरोप असत्य है।
    - 2019 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जमानत के चरण में सबूतों के विस्तृत विश्लेषण पर रोक लगाई गई है और मामले की "व्यापक संभावनाओं" पर जमानत से इनकार किया जा सकता है। इससे जेल में बंद छात्र कार्यकर्ताओं पर बोझ और बढ़ गया।

दिल्ली हाई कोर्ट का जमानत आदेश फैसला

- यह पाया गया है कि तीन छात्र कार्यकर्ताओं में से कोई भी विशेष रूप से किसी भी 'आतंकवादी कृत्य' का आरोप नहीं लगाया गया था। एक बार जब यूएपीए के आरोपों को सच नहीं देखा गया, तो अदालत उन्हें नियमित जमानत के लिए स्वीकार कर उन्हें जमानत दे सकती थी।
- **जमानत देने का नया तरीका:** उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि जमानत अदालत मामले की प्रथम दृष्टया सच्चाई के बारे में खुद को संतुष्ट करने के लिए उपलब्ध सबूतों को देख सकती है। दूसरे शब्दों में, केवल यूएपीए लागू होने के कारण अभियोजन पक्ष के मामले में कोई वैधानिक अजेयता नहीं है।
- **आतंकी कानून के दुरुपयोग का आह्वान:** अदालत ने देखा कि राज्य ने, असंतोष को दबाने की अपनी चिंता में, संवैधानिक रूप से गारंटीकृत विरोध के अधिकार और "आतंकवादी गतिविधि" के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया है। यदि इस तरह के धुंधलेपन से कर्षण प्राप्त होता है, तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा,
    - जमानत के आदेश इस बात का भी उल्लेख करते हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट ने 1994 में करतार सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में, एक अन्य आतंकवाद विरोधी कानून, आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1987 के दुरुपयोग के खिलाफ इसी तरह की चिंताओं को हरी झंडी दिखाई।
- **आतंकवाद सार्वजनिक अव्यवस्था से परे है:** दिल्ली HC ने कहा कि आतंकवादी गतिविधि की सीमा और पहुंच एक सामान्य अपराध के प्रभाव से परे होनी चाहिए और केवल कानून और व्यवस्था या यहां तक कि सार्वजनिक व्यवस्था में गड़बड़ी पैदा करने से उत्पन्न नहीं होनी चाहिए; और ऐसा होना चाहिए कि यह सामान्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की कानून द्वारा इससे निपटने की क्षमता से परे यात्रा करे।
- **पवित्र विरोध का अधिकार:** यह देखते हुए कि सरकारी और संसदीय कार्यों के खिलाफ विरोध वैध था, उच्च न्यायालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार गैरकानूनी नहीं है। इसने कहा कि छात्र कार्यकर्ताओं के विरोध को यूएपीए के अर्थ में 'आतंकवादी कृत्य' नहीं कहा जा सकता है।

अन्य असंतुष्टों पर निर्णय का परिणाम

- उच्च न्यायालय ने एक ओर देश की अखंडता और सुरक्षा के विरुद्ध अपराधों के अभियुक्तों और दूसरी ओर 'आतंकवाद' के नाम पर अनुचित रूप से शामिल प्रदर्शनकारियों या असंतुष्टों के बीच स्पष्ट अंतर किया है।

न्यायपालिका और AI

संदर्भ: हाल ही में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने भारतीय न्यायपालिका प्रणाली के लिए AI - संचालित अनुसंधान पोर्टल SUPACE सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट एफिशिएंसी) का शुभारंभ किया।

- उच्चतम न्यायालय के फैसलों का अनुवाद करने के लिये विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर (SUVAS) को मशीन लर्निंग (ML) टूल के रूप में विकसित किया गया है।

सुपेस क्या है?

- यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित उपकरण है जो प्रासंगिक तथ्यों और कानूनों को एकत्र करता है और उन्हें एक न्यायाधीश को उपलब्ध कराता है।
- प्रारंभ में, इसका प्रयोग प्रायोगिक आधार पर बॉम्बे और दिल्ली उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा किया जाएगा जो आपराधिक मामलों से निपटते हैं।

न्यायपालिका में AI के अन्य संभावित अनुप्रयोग

- मशीन लर्निंग के माध्यम से प्रशिक्षित कार्य-विशिष्ट, संकीर्ण रूप से तैयार किए गए एल्गोरिदम, प्रशासनिक कार्यों को स्वचालित करने के लिए तैनात किए जा सकते हैं जैसे सुनवाई का समय निर्धारित करना और वाद सूची बनाना आदि।
- एआई उपकरण निर्णय लेने की प्रक्रियाओं को बढ़ाने में सहायता कर सकते हैं जहां कम्प्यूटेशनल टूल का उपयोग न्याय वितरण में तेजी लाने के लिए किया जा सकता है जैसे ट्रैफिक चालान और मोटर वाहन मुआवजे के दावों के लिए।

न्याय वितरण में AI और ML को एकीकृत करने के लाभ

- **गति बढ़ाता है:** SUPACE जैसे AI संचालित उपकरण न केवल मामलों को व्यवस्थित करने में मदद करेंगे, बल्कि यह अब तक नहीं देखी गई गति से निर्णय में संदर्भ भी लाएगा।
- **न्याय तक पहुंच के अधिकार को मजबूत करता है:** आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) न्याय तक पहुँच के मौलिक अधिकार के लिये अधिक सुव्यवस्थित, लागत प्रभावी और समयबद्ध साधन प्रस्तुत करेगा।

न्याय प्रदान करने के लिए AI का उपयोग करते समय रखी जाने वाली सावधानियां

- दक्षता बढ़ाने के लिए AI और ML के नैतिक और जिम्मेदार उपयोग को कानूनी और न्यायिक प्रक्रियाओं में तेजी से शामिल किया जा सकता है।
- न्याय प्रदान करने में AI की प्रासंगिकता स्पष्ट और अच्छी तरह से लेबल किए गए डेटा सेट की उपलब्धता पर निर्भर करेगी। इस प्रकार मनुष्यों को मजबूत आवश्यक लेबल वाले डेटा सेट बनाने के लिए लूप में रखा जाना है
- चूँकि इसका उद्देश्य उन गतिविधियों को अधिक कुशलतापूर्वक और व्यवस्थित रूप से करना है, जो वर्तमान में मानवों द्वारा की जा रही हैं, ऐसे में बेरोज़गारी में बढ़ोतरी होने की सम्भावना और अधिक बढ़ जाएगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महिला और न्यायपालिका
- न्यायपालिका में भाषा
- न्यायिक प्रशासन सुधार
- जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

लोकतंत्र में सोशल मीडिया की भूमिका

संदर्भ: कोविड -19 महामारी के दौरान हमने देखा कि कैसे सोशल मीडिया के जरिए आम नागरिक एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं एवं संकट से निपटने में आधुनिक सरकारी प्रयासों के पूरक हो सकते हैं।

सोशल मीडिया के सकारात्मक प्रभाव

- **लोकतंत्र को बनाये रखता है:** सोशल मीडिया एक ऐसा उपकरण है जो प्रतीत होने वाली अजेय सरकारों पर सवाल उठा कर उन्हें जवाबदेह बना सकता है और वर्षों में एक वोट से अधिक लोगों द्वारा संचालित निरंतर परिवर्तन ला सकता है।

- **राजनेताओं और नागरिकों के बीच सीधा संपर्क:** सोशल मीडिया राजनीतिक नेताओं को अपने नागरिकों से जुड़ने के लिए बिना मिलावट की पहुंच प्रदान करता है।
- **नागरिक जुड़ाव:** नागरिक जुड़ाव के लिये सोशल मीडिया के निहितार्थ बहुत गहरे हैं क्योंकि बहुत से लोग इन प्लेटफार्मों पर समाचारों पर चर्चा एवं समकालीन मुद्दों पर बहस करते हैं। इस तरह लोग अपने तरह के लोगों से जुड़ते हैं एवं उनमें एक समुदाय की भावना मजबूत होती है।

चुनौतियों

- **राजनीतिक दुरुपयोग:** डेटा से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में ज्यादातर राजनीतिक दलों ने चुनावी विज्ञापन पर लगभग 800 मिलियन डॉलर (5,900 करोड़ रुपये) खर्च किए हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से सूक्ष्म-लक्ष्यीकरण चुनाव के एजेंडे को बदलने के लिए आधी-अधूरी जानकारी को सक्षम कर सकता है और समाज में दोष उत्पन्न करते हैं
- **फेक न्यूज:** सोशल मीडिया लोगों को अपनी बात रखने का पर्याप्त मौका देता है। कभी-कभी जिसका इस्तेमाल किसी के द्वारा अफवाह फैलाने और गलत सूचना फैलाने के लिये भी किया जा सकता है।
- **राजनीतिक ध्रुवीकरण:** सोशल मीडिया की सबसे आम आलोचनाओं में से एक यह है कि यह 'ईको चेंबर' (Echo Chamber) बनाता है जहां लोग केवल उन दृष्टिकोणों से चीजों एवं घटनाओं को देखते हैं, जिनसे वे सहमत होते हैं और जिनसे असहमत होते हैं उन्हें सिरे से खारिज़ कर देते हैं।

निष्कर्ष

- अगर लोकतंत्र पर सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में कोई सच्चाई है तो वह यह है कि यह मानवीय गुणों, सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों गुणों, को बढ़ावा देता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नए आईटी नियम
- सोशल मीडिया चिंताएं
- किसानों के विरोध के दौरान ट्विटर पर विवाद
- बड़ी तकनीक का प्रभुत्व
- ऑस्ट्रेलिया का समाचार मीडिया सौदेबाजी कोड

जम्मू-कश्मीर में परिसीमन आरंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- हाल ही में, जम्मू और कश्मीर (जम्मू और कश्मीर) में परिसीमन अभ्यास शुरू हुआ है।
- परिसीमन अभ्यास का पूरा होना केंद्र शासित प्रदेश (UT) में राजनीतिक प्रक्रिया को चिह्नित करेगा जो जून 2018 से केंद्र के शासन के अधीन है।
- अनुच्छेद 370 के तहत विशेष दर्जा समाप्त करने के बाद, 5 अगस्त, 2019 को, मार्च, 2020 में केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा और संसद की सीटों के निर्धारण के लिए एक विशेष परिसीमन आयोग का गठन किया गया था।

परिसीमन क्या है?

- यह चुनाव आयोग के अनुसार एक विधायी निकाय वाले देश या प्रांत में क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को तय करने या फिर से परिभाषित करने का कार्य है।
- परिसीमन अभ्यास एक स्वतंत्र उच्चाधिकार प्राप्त पैनल द्वारा किया जाता है जिसे परिसीमन आयोग के नाम से जाना जाता है जिसके आदेशों में कानून का बल होता है और किसी भी अदालत द्वारा इस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है।

उद्देश्य:

- भौगोलिक क्षेत्रों का उचित विभाजन सुनिश्चित करने के लिए जनसंख्या के समान वर्गों के लिए समान प्रतिनिधित्व प्राप्त करना।

परिसीमन के लिए संवैधानिक आधार

- अनुच्छेद 82: संसद प्रत्येक जनगणना के बाद एक परिसीमन अधिनियम बनाती है।
- अनुच्छेद 170: परिसीमन अधिनियम के अनुसार राज्यों को भी प्रत्येक जनगणना के बाद प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है।

परिसीमन आयोग:

- परिसीमन आयोग की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
- **संरचना:**
  - सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश
  - मुख्य चुनाव आयुक्त
  - संबंधित राज्य चुनाव आयुक्त

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR)

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस II - नागरिकता

सुर्खियों में-

- केंद्रीय गृह मंत्रालय के मैनुअल के अनुसार, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के छह गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायों के प्रवासी, लंबी अवधि के वीजा (LTVs) के लिए आवेदन करते समय, भारत में अपने प्रवास की अवधि के प्रमाण के रूप में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) नामांकन पर्ची भी प्रस्तुत कर सकते हैं।
- पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदुओं और सिखों के लिए एलटीवी का विशेष प्रावधान पहली बार 2011 में किया गया था।
- यह भी कहा गया कि जागरूकता अभियान नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (CAA) से संबंधित नहीं है, जिसका उद्देश्य उन छह समूहों के अनिर्दिष्ट प्रवासियों को लाभ पहुंचाना है, जिन्होंने 2014 की कट-ऑफ तिथि से पहले भारत में प्रवेश किया था।
  - CAA को अभी लागू किया जाना बाकी है।

NPR के बारे में

- NPR को पहली बार 2010 में दशकीय जनगणना अभ्यास के साथ संकलित किया गया था और बाद में 2015 में अद्यतन किया गया था।
- इसके पास पहले से ही 119 करोड़ निवासियों का डेटाबेस है।
- NPR का अगला चरण, जिसमें माता-पिता के जन्म की तारीख, स्थान और मातृभाषा पर विवादास्पद प्रश्न शामिल होने की उम्मीद थी, साथ ही 2021 में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस के साथ अद्यतन किया जाना था जिसे COVID-19 महामारी के कारण अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया।

न्यायाधीशों का बहिष्कार

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट के दो न्यायाधीशों - न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस ने पश्चिम बंगाल से संबंधित मामलों की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।

रिक्यूसल-किसी न्यायाधीश या अभियोजक को किसी मामले से इस आधार पर वापस लेना कि वे संभावित हितों के टकराव या निष्पक्षता की कमी के कारण कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए अयोग्य हैं।

एक न्यायाधीश मना क्यों करता है?

- **पूर्वाग्रह की धारणा को रोकने के लिए:** जब हितों का टकराव होता है, तो एक न्यायाधीश मामले की सुनवाई से पीछे हट सकता है ताकि यह धारणा पैदा न हो कि उसने मामले का फैसला करते समय पक्षपात किया है।
- **निमो जूडेक्स इन कॉसा सुआ:** यह लैटिन शब्द "किसी को भी अपने मामले में जज नहीं होना चाहिए" का अनुवाद करता है, जो कानून की उचित प्रक्रिया का एक प्रमुख सिद्धांत है।
- **निष्पक्ष और भरोसेमंद प्रणाली:** कोई भी हित या हितों का टकराव किसी मामले से हटने का आधार होना चाहिए क्योंकि निष्पक्ष कार्य करना एक न्यायाधीश का कर्तव्य है। ऐसी स्थिति के दौरान पीछे हटने से विश्वसनीय, भरोसेमंद न्यायिक प्रणाली बनती है।

आमतौर पर किन सभी स्थितियों में हितों का टकराव उत्पन्न होता है?

हितों का टकराव कई तरह से हो सकता है-

- यदि कोई न्यायाधीश किसी ऐसी कंपनी में शेयर धारण कर रहा है जो मामले की सुनवाई में एक वादी है
- यदि किसी न्यायाधीश का मामले में शामिल किसी पक्ष के साथ पूर्व या व्यक्तिगत संबंध है/हैं।
- जब उच्च न्यायालय के एक फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की जाती है जो कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा दिया गया हो सकता है जब वह उच्च न्यायालय में थी।

बहिष्कार की प्रक्रिया क्या है?

- अलग करने का निर्णय आम तौर पर स्वयं न्यायाधीश द्वारा लिया जाता है क्योंकि यह किसी भी संभावित हितों के टकराव का खुलासा करने के लिए न्यायाधीश के विवेक पर निर्भर करता है। कुछ परिस्थितियों में, वकील या पक्ष इसे न्यायाधीश के सामने लाते हैं।
- यदि कोई न्यायाधीश अलग हो जाता है, तो मामले को मुख्य न्यायाधीश के समक्ष एक नई पीठ को आवंटित करने के लिए सूचीबद्ध किया जाता है।
- पुनर्मूल्यांकन को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, हालांकि सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों ने इस मुद्दे से निपटा है (उदा: रंजीत ठाकुर बनाम भारत संघ, 1987)

क्या कोई जज मना कर सकता है?

- एक बार अलग करने का अनुरोध करने के बाद, न्यायाधीश के पास वापस लेने या न करने का निर्णय होता है।
- हालांकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां न्यायाधीशों ने विरोध नहीं किया, भले ही वे खुद को अलग कर लेते हों, लेकिन केवल इसलिए कि ऐसी आशंका पैदा की गई थी, ऐसे कई मामले भी हैं जहां न्यायाधीशों ने किसी मामले से हटने से इनकार कर दिया है।
    - अयोध्या-रामजन्मभूमि मामले में, न्यायमूर्ति यू यू ललित ने खुद को संविधान पीठ से अलग कर लिया जब पार्टियों ने उनके ध्यान में लाया कि वह मामले से संबंधित एक आपराधिक मामले में एक वकील के रूप में पेश हुए थे।
    - 2019 में, न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा ने विवादास्पद रूप से खुद को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून पर दिए गए एक फैसले की फिर से जांच करने के लिए गठित एक संविधान पीठ से खुद को अलग करने से इनकार कर दिया था।

क्या न्यायाधीश अलग होने के कारणों को रिकॉर्ड रखते हैं?

- चूंकि इस प्रक्रिया को नियंत्रित करने वाले कोई औपचारिक नियम नहीं हैं, इसलिए यह अक्सर अलग-अलग न्यायाधीशों पर छोड़ दिया जाता है कि वे अलग होने के कारणों को दर्ज करें।
- कुछ न्यायाधीश खुली अदालत में कारणों का खुलासा करते हैं; कुछ मामलों में, कारण स्पष्ट हैं।
- 2015 में एक ऐतिहासिक फैसले में, जिसमें राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को असंवैधानिक बताते हुए, न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ और न्यायमूर्ति मदन लोकुर ने न्यायाधीशों को पारदर्शिता बनाने और प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिए नियम बनाने में मदद करने के कारण बताने की आवश्यकता का उल्लेख किया।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- न्यायपालिका और एआई
- महिला और न्यायपालिका
- न्यायिक प्रशासन सुधार

रैंक च्वाइस वोटिंग

संदर्भ: रैंक च्वाइस वोटिंग ने न्यूयॉर्क शहर के मेयर चुनावों में अपनी शुरुआत की।

रैंक च्वाइस वोटिंग क्या है?

- **प्रणाली एक सरल आधार पर आधारित है:** लोकतंत्र बेहतर तरीके से काम करता है यदि लोगों को अपने वोट के साथ सभी या कुछ नहीं का चुनाव करने के लिए मजबूर नहीं किया जाता है।
- केवल एक उम्मीदवार को चुनने के बजाय, मतदाता वरीयता के क्रम में कई रैंक प्राप्त करते हैं।
- **विदेशों में लोकप्रिय:** 20वीं सदी की शुरुआत से ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड और माल्टा द्वारा भी इसका इस्तेमाल किया जाता रहा है। उत्तरी आयरलैंड, न्यूजीलैंड और स्कॉटलैंड ने भी इसे अपनाया है।
- ऑस्कर भी 2009 से अपनी सर्वश्रेष्ठ चित्र श्रेणी के लिए इसका उपयोग कर रहा है।

रैंक च्वाइस वोटिंग कैसे काम करती है?

- न्यूयॉर्क सिटी के संस्करण में मतदाताओं को अपने मतपत्र पर पहली से आखिरी तक पांच उम्मीदवारों तक रैंक मिलती है।
- यदि एक उम्मीदवार 50% से अधिक मतदाताओं की पहली पसंद है तो वह व्यक्ति पारंपरिक चुनाव की तरह ही एकमुश्त जीत हासिल करता है।
- लेकिन अगर किसी को 50% जमा एक नहीं मिलता है, तो वह दूसरे दौर में है।
- वोट सारणीकरण राउंड में किया जाता है। प्रत्येक दौर में, अंतिम स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है। वोटों ने रैंकिंग दी कि उम्मीदवार को पहले उन मतदाताओं की दूसरी पसंद में पुनर्वितरित किया जाता है।
- वोटों का यह पुनर्आवंटन तब तक चलता है जब तक कोई व्यक्ति 50% जमा एक तक नहीं पहुंच जाता।

इस प्रणाली के गुण

- **लोगों की आवाज की गिनती:** भले ही किसी मतदाता की शीर्ष पसंद के पास जीतने के लिए पर्याप्त समर्थन न हो, फिर भी अन्य उम्मीदवारों की उनकी रैंकिंग विजेता का निर्धारण करने में एक भूमिका निभाती है।
- **मतदान में वृद्धि की संभावना:** लोग अपना वोट डालने के बारे में अच्छा महसूस कर सकते हैं। उस एक विकल्प के लिए अपनी नाक पकड़ने के बजाय, मतदाता उस व्यक्ति के लिए कम से कम पहली पसंद व्यक्त कर सकते हैं जिसे वे वास्तव में पसंद करते हैं।

नकारात्मक क्या हैं?

- सिस्टम को पकड़ना मुश्किल है। इसके लिए मतदाताओं को बहुत अधिक शोध करने की आवश्यकता है। यह दौड़ को कम अनुमानित भी बनाता है।
- कुछ लोगों का तर्क है कि यह कम लोकतांत्रिक है क्योंकि यह एक व्यक्ति, एक वोट के विचार के खिलाफ है।
- पारदर्शिता और विश्वास भी संभावित समस्याएं हैं। आधुनिक रैंक पसंद प्रणाली के तहत वोटों के पुनर्वितरण की प्रक्रिया कंप्यूटर द्वारा की जाती है। बाहरी समूहों को यह मूल्यांकन करने में कठिन समय होगा कि सॉफ़्टवेयर ने रैंक किए गए वोटों को सही ढंग से क्रमबद्ध किया है या नहीं।
- **बहुत से लोग सभी विकल्पों को नहीं भरते हैं:** अधिकांश लोगों की सही इच्छा जानना मुश्किल है यदि हर कोई सभी विकल्पों को नहीं भर रहा है।

- यह खरीद-फरोख्त को बढ़ावा दे सकता है। रैंक-पसंद मतदान उम्मीदवारों के लिए एक दूसरे के साथ सौदे करने के लिए द्वार खोल सकता है कि उनके मतदाताओं को दूसरी पसंद के रूप में किसके लिए जाना चाहिए।
- **यह आवश्यक रूप से नकारात्मक प्रचार को कम नहीं कर सकता है:** अधिकांश नकारात्मक प्रचार बाहरी समूहों द्वारा किया जाता है, और रैंक पसंद प्रणाली में कुछ भी उन संस्थाओं को ऐसा करने से रोकता नहीं है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राज्यसभा चुनाव में आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली
- रिमोट वोटिंग सुविधा
- एनआरआई वोटिंग

न्यायालयों को खोलना

संदर्भ: हाल ही में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के एक वरिष्ठ न्यायाधीश ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि तुच्छ मामले न्यायालय को निष्क्रिय बना रहे हैं।

- तुच्छ मामले सर्वोच्च न्यायालय के बोझ को बढ़ा रहे हैं और अन्य वादियों को उनके मामलों की सुनवाई में देरी करके नुकसान पहुंचा रहे है।
- तुच्छ मामलों में न्याय प्रदान करने वाली प्रणाली की दक्षता में कमी लाने के कारण न्यायाधीशों और अदालत प्रणाली के समय की बर्बादी भी होती है।

हालांकि तुच्छ मामलों की समस्या पहचानी जाती है, यह निम्नलिखित कारणों से जारी रहती है:

1. एक प्रमुख वादी के रूप में सरकार

- कानून और न्याय मंत्रालय ने सरकारी मुकदमों को कम करने की कार्य योजना (2017) में कहा कि अदालतों के समक्ष लगभग 46 प्रतिशत लंबित मामले सरकार से संबंधित हैं।
- सुप्रीम कोर्ट ने तुच्छ मुकदमे दायर करने के लिए सरकारों और वादियों पर जुर्माना लगाया है। हालांकि, इसने उन्हें इस तरह के मुकदमों में शामिल होने से हतोत्साहित नहीं किया है।

2. राष्ट्रीय मुकदमेबाजी नीति 2010 की अनदेखी

- नीति के प्रावधानों में से एक जो कहता है कि "मुकदमेबाजी के लिए मुकदमेबाजी का सहारा नहीं लिया जाएगा", यह काम नहीं कर रहा है।
- नीति ने सरकारी अधिकारियों को तुच्छ मामले दर्ज करने से नहीं रोका है।
- तुच्छ मामलों के लिए सरकारी प्राधिकारियों पर लागत का आरोपण अंततः सरकारी खजाने से किया जा रहा है, जिससे सार्वजनिक धन का अक्षम उपयोग हो रहा है।

3. न्यायाधीशों की नियुक्ति न होना

- कई उच्च न्यायालयों में कई बार 40 से 50 प्रतिशत रिक्तियां होती हैं।
- अपर्याप्त जजों की संख्या तुच्छ मामलों को लंबी अवधि के लिए लटका देती है क्योंकि मौजूदा ताकत मामलों के भारी बोझ के बीच कम अवधि में उनका निपटारा नहीं कर सकती है।

आगे की राह

- न्यायपालिका को खोलने की जिम्मेदारी केंद्र और राज्य सरकारों की है क्योंकि वे अदालतों में सबसे बड़े वादी हैं।
- "राष्ट्रीय मुकदमा नीति, 2010" का सरकार को आदर्श मुकदमेबाज़ में परिवर्तित करने का उद्देश्य एक दूरस्थ लक्ष्य है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महिला और न्यायपालिका
- न्यायपालिका में भाषा
- न्यायिक प्रशासन सुधार

- जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस

सामाजिक मुद्दे/ वेलफ़ेयर

प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय ने प्रदर्शन ग्रेडिंग इंडेक्स या पीजीआई का नवीनतम संस्करण जारी किया।

शिक्षा मंत्रालय ने संदर्भ वर्ष 2017-18 के लिए 2019 में पहला पीजीआई जारी किया।

PGI कैसे काम करता है?

- **उद्देश्य:** यह अपेक्षाकृत नया सूचकांक स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन को मापता है। इसका उद्देश्य राज्यों को स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप के लिए क्षेत्रों को प्राथमिकता देने में मदद करना है।
- **एकाधिक डेटा स्रोत:** यह शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली प्लस, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण और मध्याह्न भोजन सहित कई स्रोतों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर स्कूली शिक्षा में राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करता है।
- **कार्यप्रणाली :** राज्यों को 70 मापदंडों में कुल 1,000 अंकों पर स्कोर किया गया है, जिन्हें पांच व्यापक श्रेणियों के तहत समूहीकृत किया गया है:
    - पहुंच (जैसे नामांकन अनुपात, संक्रमण दर और प्रतिधारण दर);
    - शासन और प्रबंधन;
    - इंफ्रास्ट्रक्चर
    - इक्विटी (अनुसूचित जाति के छात्रों और सामान्य श्रेणी के छात्रों के बीच प्रदर्शन में अंतर)
    - सीखने के परिणाम (गणित, विज्ञान, भाषा और सामाजिक विज्ञान में औसत अंक)।

- **ग्रेडिंग और रैंकिंग नहीं:** राज्यों को केवल दूसरों की कीमत पर सुधार करने की प्रथा को हतोत्साहित करने के लिए वर्गीकृत करके रैंक नहीं किया जाता है, "जिससे बाद वाले पर खराब प्रदर्शन का धब्बा लगता है"।

ग्रेडिंग सिस्टम क्या दर्शाता है?

PGI ग्रेडिंग सिस्टम में 10 स्तर होते हैं।

- स्तर 1 शीर्ष प्रदर्शन और 951 और 1000 अंकों के बीच के स्कोर को दर्शाता है।
- स्तर II, जिसे ग्रेड 1++ भी कहा जाता है यह 901 और 950 के बीच के स्कोर को दर्शाता है।
- ग्रेड 1+ (या लेवल III) वाले लोगों ने 851 और 900 के बीच स्कोर किया है।
- सबसे कम ग्रेड VII है, इसका अर्थ है 0 और 550 अंकों के बीच का स्कोर।

इस बार राज्यों का प्रदर्शन कैसा रहा?

- **प्रथम स्तर में कोई नहीं:** PGI 2019-20 में, कोई भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश उच्चतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर सका, जो कि स्तर I है। 2017-18 और 2018-19 के संस्करणों में भी, कोई भी राज्य स्तर 1 और ग्रेड 1++ तक नहीं पहुंचा था।
- **सामान्य ऊपर की ओर शिफ्ट:** कुल 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2018-19 की तुलना में 2019-20 में अपने कुल पीजीआई स्कोर में सुधार किया है, जो सामान्य ऊपर की ओर बदलाव का संकेत देता है। कुछ के लिए यह सुधार उनके डेटा रिपोर्टिंग तंत्र में सुधार रहा है जबकि कुछ अन्य के लिए, विशिष्ट डोमेन में सुधार हुआ है
- **सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य:** चंडीगढ़, पंजाब, तमिलनाडु, अंडमान और निकोबार और केरल ने 90% से अधिक स्कोर किया है और ग्रेड 1++ (या स्तर II) प्राप्त किया है, जो उन्हें सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य बनाता है। यह पहला मौका है जब कोई राज्य दूसरे स्तर पर पहुंचा है।
- **सबसे बड़ा सुधार:** इस साल PGI में सबसे बड़ा सुधार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश द्वारा दिखाया गया है। तीनों ने अपने स्कोर में 20% का सुधार किया है।
- **चिंता के क्षेत्र:** हालांकि, अभी भी 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्तर III (ग्रेड 1) या उससे कम में रखा गया है, जो दर्शाता है कि उनके पास अभी भी बहुत कुछ है।
- केवल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख को सबसे निचले ग्रेड में रखा गया है, जो कि ग्रेड VII है, लेकिन ऐसा इसलिए है क्योंकि 2019 में जम्मू और कश्मीर से अलग होने के बाद पहली बार इसका मूल्यांकन किया गया था।

ऐसे कौन से क्षेत्र हैं जहां राज्यों को अभी भी सुधार करना है?

- PGI शासन क्षेत्र को सर्वोच्च महत्व देता है क्योंकि यहां संकेतकों के अनुपालन से महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार होंगे
- रिपोर्ट के अनुसार, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मुख्य रूप से शासन प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है। इस डोमेन में कई पैरामीटर हैं, जिनमें शामिल हैं
    - शिक्षक उपलब्धता: शिक्षकों की उपस्थिति की निगरानी
    - शिक्षक प्रशिक्षण
    - नियमित निरीक्षण
    - वित्तीय उपलब्धता।
- डोमेन गवर्नेंस प्रक्रियाओं में, 24 राज्य/केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्होंने 288 से कम (अधिकतम संभव स्कोर का 80%) स्कोर किया है।
- दूसरा क्षेत्र जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है वह है इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाओं के लिए डोमेन। यह चिंता का विषय है क्योंकि स्कूली शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में सुधार के लिए पर्याप्त सुविधाओं के साथ एक उचित स्कूल भवन आवश्यक है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ASER सर्वेक्षण और कोविड-19 प्रभाव
- ASER 2019 रिपोर्ट: सरकारी स्कूलों में शुरुआती शिक्षा को ठीक करें

- नई शैक्षिक नीति, 2020
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम

स्कूल न जाने वाले बच्चों के डेटा के संकलन के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - शिक्षा; नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- शिक्षा मंत्रालय ने प्रत्येक राज्य / केंद्र शासित प्रदेश द्वारा चिन्हित, स्कूल न जाने वाले बच्चों (कोविड -19 महामारी के कारण) के डेटा को संकलित करने और विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) के साथ उनकी मैपिंग के लिए 'प्रबंध पोर्टल' पर एक ऑनलाइन मॉड्यूल विकसित किया है।

मॉड्यूल के बारे में

- इस मॉड्यूल के माध्यम से, सरकार 6-14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए उम्र के अनुकूल स्कूलों में प्रवेश को सुगम बनाएगा।
- सत्र 2021-22 में 16-18 वर्ष आयु वर्ग के स्कूली बच्चों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

प्रबंध पोर्टल के बारे में

- प्रबंध (परियोजना मूल्यांकन, बजट, उपलब्धियां और डेटा प्रबंधन प्रणाली) दक्षता बढ़ाने और कार्यान्वयन का प्रबंधन करने, प्रौद्योगिकी का उपयोग करने की दिशा में एक कदम है।
- यह पारदर्शिता और सटीकता को सक्षम करेगा।

समग्र शिक्षा

- यह प्री-स्कूल से बारहवीं कक्षा तक फैली स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना है
- **उद्देश्य:** स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना।
- **इसमें तीन योजनाएं शामिल हैं:** सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA) और टीचर एजुकेशन (TE)।
- **मुख्य बिंदु :** दो T's - शिक्षक और प्रौद्योगिकी पर ध्यान केंद्रित करके स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना।

संबंधित आलेख:

- बच्चों के लिए PM-CARES योजना
- लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता: बाल स्वराज पोर्टल

अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) 2019-20

संदर्भ: शिक्षा मंत्रालय ने 10 जून को 2019-20 के लिए अखिल भारतीय उच्च शिक्षा सर्वेक्षण (AISHE) के निष्कर्ष जारी किए।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

कुल नामांकन उच्च शिक्षा में	• 2014-15 में 3.42 करोड़। • 2018-19 में 3.74 करोड़। • 2019-20 में 3.85 करोड़: 11.36 लाख (3.04 प्रतिशत) की वृद्धि इनमें से, लगभग 85% छात्रों (2.85 करोड़) ने छह प्रमुख विषयों जैसे मानविकी, विज्ञान, वाणिज्य, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, चिकित्सा विज्ञान और आईटी और कंप्यूटर में नामांकित किया था।
सकल नामांकन अनुपात (GER)	• 2014-15 में 24.3%

	• 2018-19 में 26.3% • 2019-20 में 27.1% उच्च शिक्षा में GER की गणना 18-23 आयु वर्ग के लिए की जाती है। यह पात्र आयु वर्ग की जनसंख्या में उच्च शिक्षा में नामांकन का अनुपात है।
लैंगिक समानता सूचकांक	जीपीआई 2019-20 में उच्च शिक्षा 1.01 है, जबकि 2018-19 में 1.00 था, जो पुरुषों की तुलना में पात्र आयु वर्ग की महिलाओं के लिए उच्च शिक्षा के सापेक्ष पहुंच में सुधार को दर्शाता है।
PhD करने वाले छात्र	• 2014-15 में 1.17 लाख • 2019-20 में 2.03 लाख
शिक्षकों की कुल संख्या	• 15,03,156 जिसमें 57.5% पुरुष और 42.5% महिलाएं शामिल हैं। • 2019-20 में उच्च शिक्षा में छात्र शिक्षक अनुपात 26 है।

हालाँकि, रिपोर्ट में यह सुझाव देने के लिए पर्याप्त सबूत भी हैं कि भारत का उच्च शिक्षा क्षेत्र लिंग, जाति और क्षेत्रीय अक्ष पर असमानता के गंभीर मुद्दों का सामना करता है।

1. नामांकन संख्या में शीर्षक सुधार व्यावसायिक रूप से पुरस्कृत पाठ्यक्रमों तक पहुंच छुपाता है

- जब व्यावसायिक रूप से लाभकारी शिक्षा प्राप्त करने की बात आती है, तो जाति और लैंगिक प्रमुख निर्धारक प्रतीत होते हैं।
- स्नातक और परास्नातक स्तर पर शीर्ष 10 सबसे अधिक अनुसरण किए जाने वाले कार्यक्रमों में एकमात्र व्यावसायिक पाठ्यक्रम - जहां महिलाएं पुरुषों से बेहतर प्रदर्शन करती हैं, वे हैं बीएड और एमएड, जो आमतौर पर इच्छुक स्कूल-शिक्षकों द्वारा अपनाए जाते हैं

2. उच्च शिक्षा में शिक्षकों के बीच बहुस्तरीय सामाजिक असमानता

- भारत के उच्च शिक्षण संस्थानों में 40% से अधिक शिक्षक गैर-एससी-एसटी-ओबीसी हिंदू हैं। 2015-16 के राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NFHS) के निष्कर्षों के अनुसार, उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी सिर्फ 17.6 फीसदी है।
- राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में भी, जिनमें IITs, NITs, AIIMS, और IIMs जैसे संस्थान शामिल हैं, गैर-एससी-एसटी-ओबीसी हिंदू शिक्षकों की हिस्सेदारी 70% से अधिक है।
- शैक्षिक संस्थानों में प्रदर्शनकारी/शिक्षक के पद पर महिलाओं की हिस्सेदारी 65.5% है, लेकिन एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के स्तर पर यह घटकर 27.5% रह जाती है।

3. भूगोल उतना ही मायने रखता है जितना समाजशास्त्र

- उच्च शिक्षा तक पहुंच सभी राज्यों में काफी भिन्न है।
- बिहार में पुरुषों और महिलाओं के लिए GER 15.8% और 13.1% और दिल्ली में 44.9% और 51.8% है।

4. सरकारी कॉलेजों का क्षेत्रीय वितरण

- 2019-20 में भारत के 39,955 कॉलेजों में से केवल 8,565 या लगभग पांचवां (21.4%) सरकारी कॉलेज थे। लेकिन विभिन्न राज्यों में सरकारी कॉलेजों की हिस्सेदारी में व्यापक क्षेत्रीय भिन्नता है।
- सरकारी कॉलेज दिल्ली के कुल कॉलेजों (55.7%) के लगभग उतने ही बड़े हैं जितने कि वे बिहार (59.8%) में हैं। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि सार्वजनिक क्षेत्र के पदचिह्न शायद ही शिक्षा की गुणवत्ता का संकेतक हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP), 2020 : इसका उद्देश्य 2035 तक उच्च शिक्षा में GER को 50% तक बढ़ाना है।
- प्रधान मंत्री अनुसंधान फैलोशिप (PMRF)

सीखने का आकलन

प्रसंग: बोर्ड परीक्षा रद्द होने के बाद बारहवीं कक्षा के छात्रों का आकलन करने के लिए किसी तरह की प्रतीक्षा ने छात्रों और अभिभावकों में भारी चिंता पैदा कर दी है। इस मुद्दे पर, लघु और दीर्घकालिक मूल्यांकन लक्ष्यों दोनों को देखने की आवश्यकता है।

आकलन क्या है?

- आकलन को सीखने की एक व्यवस्थित समीक्षा, विभिन्न अनुभवों से एकत्रित जानकारी के उपयोग और लगातार प्रतिक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है।
- मूल्यांकन में कई शीर्ष स्थान होने चाहिए। इससे यह पता लगाने में मदद मिलेगी कि शिक्षार्थी क्या जानते हैं, उनकी समझ को मापना, प्रगति को ट्रैक करना जिससे उनकी अगले चरण की योजना बनाने में मदद मिलती हैं, उपचारात्मक कार्य सौंपते हैं और हितधारकों को लगातार प्रतिक्रिया देते हैं।

वर्तमान समय में मूल्यांकन प्रणाली

- उपरोक्त परिभाषा इस बात का खंडन करती है कि हम अपने शिक्षार्थियों का आकलन कैसे करते हैं क्योंकि हम उन्हें विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव नहीं देते हैं।
- हम एक साल के अंत में राष्ट्रीय परीक्षा में तीन घंटे के मानकीकृत परीक्षण के माध्यम से उनका आकलन करते हैं।

हमारी मूल्यांकन प्रणाली में सुधार के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं?

- **आवेदन उन्मुख:** प्रश्न आवेदन आधारित होने चाहिए। बहुत अधिक ज्ञान और स्मृति-आधारित कार्यों के बिना केस स्टडीज के बैंक बनाए जाने चाहिए।
- **नवोन्मेषी परीक्षण विधियां:** दिलचस्प परीक्षण प्रणाली, जैसे कि गामीफइड परीक्षण, आवधिक मध्यावधि, परियोजना-आधारित परीक्षण का प्रयास किया जाना चाहिए।
- **विषय-आधारित मूल्यांकन तकनीक:** अधिक स्वायत्तता से मूल्यांकन करने के लिए एक ढांचा विकसित करना आवश्यक है। विषयों के आधार पर मूल्यांकन उपकरणों को बदलने की जरूरत है। विज्ञान में एक विद्यार्थी का मूल्यांकन उसी तरह नहीं किया जा सकता जैसे वह भाषाओं में करता है।
- **अंत:विषय दृष्टिकोण:** हमें क्षमता-निर्माण के तरीकों को बनाने की जरूरत है जहां हर बच्चा ज्ञान की विविधता से लैस हो और कला, खेल, जीवन कौशल, सामाजिक और भावनात्मक सीखने को एकीकृत करने वाले अनुभवात्मक शिक्षाशास्त्र का उपयोग करके उसकी दक्षताओं, मूल्यों और एक अंत:विषय दृष्टिकोण पर जोर दिया जाए।
- **आकलन के सारांश को बनाए रखना:** आकलन का उद्देश्य सीखने के परिणामों को समझना है। सीखने की पहचान करना, उसे लक्ष्य के साथ संरेखित करना, कौशल का मानचित्रण, प्रामाणिक कार्यों को डिजाइन करना जिसके माध्यम से प्रगति को पकड़ा जा सकता है, यही मूल्यांकन का सार होना चाहिए।
- समग्र रिपोर्ट कार्ड शिक्षार्थी के विविध ज्ञान को दर्शाते हुए समान, समावेशी और आनंदमय होना चाहिए। स्वयं, सहकर्मी, शिक्षक और माता-पिता के मूल्यांकन का एक संयोजन उन छात्रों को बनाने में मदद करेगा जो तनावों को सुलझा कर जिम्मेदारियां ले सकते हैं और बेहतर भविष्य को आकार दे सकते हैं।
- **ऑनलाइन मूल्यांकन का लाभ उठाना:** प्रश्न पत्रों का भौतिक रूप से मूल्यांकन करना एक चुनौती बन जाएगा। मूल्यांकन केंद्रों में कागजी कार्रवाई, जनशक्ति, गोपनीयता और निगरानी शिक्षकों के मुद्दे पैदा करते रहेंगे। ऑनलाइन मूल्यांकन प्लेटफार्मों के निर्माण को क्षेत्रीय केंद्रों और स्कूलों द्वारा खोजा और समर्थित किया जाना है।

निष्कर्ष

- जब तक शिक्षा अधिक समकालीन और बाल-केंद्रित नहीं होगी, हमारे बच्चे भविष्य की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पाएंगे। हमें ऐसी वैकल्पिक शिक्षण प्रणाली की आवश्यकता है जो आनंददायक, समावेशी, प्रगतिशील और समग्र हो। रटने की परंपरा को तोड़ने से बच्चों को अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने में मदद मिलेगी।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राष्ट्रीय शिक्षा नीति योगात्मक से रचनात्मक और योग्यता-आधारित शिक्षण प्रणाली में बदलाव को चिह्नित करती है।
- बोर्ड परीक्षाओं की आलोचना

युवाओं की रोजगार क्षमता में सुधार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस-III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- हाल ही में श्रम और रोज़गार मंत्रालय तथा यूनिसेफ ने भारत में युवाओं के लिये रोज़गार के परिणामों में सुधार हेतु एक आशय पत्र के वक्तव्य पर हस्ताक्षर किये हैं।
- यह चुनिंदा राज्यों में दोनों पक्षों की मौज़ूदा मुख्यधारा की पहलों का लाभ उठाने के लिये मंत्रालय और यूनिसेफ के बीच सहयोग हेतु एक मंच प्रदान करने का इरादा रखता है।

सहयोग के क्षेत्र

- युवाओं को रोजगार के अवसरों से जोड़ना।
- जीवन कौशल, वित्तीय कौशल, डिजिटल कौशल, व्यवसाय कौशल आदि सहित 21वीं सदी में युवाओं के कौशल को ऊपर उठाना।
- राष्ट्रीय कॅरियर सेवा (NCS) को सुदृढ़ बनाना।
- अंतराल की खोज करके नौकरी के पूर्वानुमान में सहायता करना।
- सीधे संवाद का समर्थन करना और युवाओं तथा नीति हितधारकों के बीच एक प्रतिक्रिया तंत्र की स्थापना करना।

अन्य सम्बंधित तथ्य

राष्ट्रीय कैरियर सेवा (NCS)

- इसे वर्ष 2015 में ई-गवर्नेंस योजना की छत्रछाया में लॉन्च किया गया था।
- यह एक वन-स्टॉप समाधान है जो भारत के नागरिकों को रोज़गार और कॅरियर से संबंधित सेवाओं की एक विस्तृत शृंखला प्रदान करता है।
- **नोडल मंत्रालय:** श्रम और रोजगार मंत्रालय।
- **तीन स्तंभ**
    - एक अच्छी तरह से डिज़ाइन किया गया आईसीटी आधारित पोर्टल जो एनसीएस पोर्टल है।
    - देश भर में मॉडल कॅरियर केंद्रों की स्थापना।
    - रोज़गार कार्यालयों के माध्यम से सभी राज्यों के साथ अंतर्संबंध।

भारत द्वारा की गई कुछ अन्य पहल

- प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)
- **प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (PMMY):** इसकी शुरुआत 8 अप्रैल, 2015 को गैर-कॉर्पोरेट, गैर-कृषि लघु/सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख तक का ऋण प्रदान करने के उद्देश्य से की गई है। इसका फोकस स्वरोज़गार पर है।
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना (PMRPY)

बाल श्रम और महामारी

संदर्भ: इस वर्ष को बाल श्रम के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष माना जाता है, जिसके तहत देश और नेटवर्क बाल श्रम के मूल कारणों को दूर करने के लिए खुद को प्रतिबद्ध करने के लिए एक साथ आते हैं।

बाल श्रम के कुछ मूल कारण हैं:

- गरीबी
- सामाजिक उपेक्षा
- माता-पिता के लिए वैकल्पिक या सुरक्षित आजीविका का अभाव
- पर्याप्त बाल संरक्षण तंत्र
- गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अभाव।
- महामारी, शिक्षा और बाल श्रम
- **बच्चों को श्रम में धकेलने वाले स्कूल बंद:** पिछले एक साल या उससे अधिक समय से 15 लाख स्कूल बंद हैं। 2021 में, यूनेस्को का कहना है कि 24 मिलियन बच्चों को महामारी के बाद स्कूलों में वापस जाने का रास्ता नहीं मिल सका है। कोई भी बच्चा जो स्कूल में नहीं है एक संभावित बाल मजदूर है।
- **बाल विवाह:** भारत में 2020 के बाद से बाल विवाहों की संख्या में वृद्धि देखी गई है। लड़कियों को और अधिक जोखिम होता है जब जल्दी शादी दी जाती है, ये बालिकाएं भी अक्सर बाल मजदूर होती हैं। सेव द चिल्ड्रन से पांच लाख और लड़कियों की कम उम्र में शादी होने का खतरा है।
- **दुर्व्यवहार और तस्करी:** स्कूलों के बंद होने और महामारी से ग्रसित गरीबी ने बच्चों, विशेष रूप से लड़कियों के साथ दुर्व्यवहार और तस्करी की चपेट में आने की संभावना को बढ़ा दिया है।
- **शिक्षा बजट कम किया गया :** शिक्षा प्रणाली और इस प्रकार बच्चों के भविष्य पर महामारी के प्रभाव को जानने के बावजूद, केंद्रीय बजट में इस वर्ष बच्चों की शिक्षा पर खर्च करने के लिए 5,000 करोड़ रुपये कम हैं।

आगे की राह

इसके लिए अथक अभियान चलाने होंगे

- शिक्षा के लिए आवंटन में वृद्धि, सकल घरेलू उत्पाद का कम से कम 6%
- मध्याह्न भोजन के साथ नाश्ते को शामिल करना
- सीखने की हानि के लिए उपचारात्मक उपाय
- कमजोर राज्यों और स्थानीय सरकारों को प्राथमिकता के आधार पर धन का हस्तांतरण।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- महिलाओं और बच्चों पर लॉकडाउन का प्रभाव
- महामारी और घरेलू हिंसा

शिक्षा में अंग्रेजी भाषा

संदर्भ: हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार का सभी स्नातक पाठ्यक्रमों के लिए अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय (बेशक, भाषा विषयों को छोड़कर)।

- राज्य सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि स्कूल स्तर पर तेलुगु एक अनिवार्य विषय रहेगा ताकि छात्रों को भाषा सीखने को मिले।

AP सरकार के फैसले के खिलाफ तर्क

- **ग्रामीण छात्रों पर असमान रूप से प्रभाव:** आलोचकों का तर्क है कि इससे कई छात्र, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों से और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के, जिनके अब तक तेलुगु माध्यम के स्कूलों में शिक्षित होने की संभावना है, विचारणीय रूप रूप से वंचित रह जाएंगे।

- **उप-इष्टतम सीखने का डर:** ऐसे छात्रों को अपनी अकादमिक खोज में इतनी देर से अंग्रेजी में स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करना, आलोचकों का डर, छात्रों की वास्तविक क्षमता और योग्यता के मुकाबले उप-इष्टतम सीखने का कारण बन सकता है।
- **संस्कृति पर वार :** विपक्ष ने इस फैसले को तेलुगु संस्कृति पर हमले और तेलुगु भाषा के संरक्षण के बलिदान के रूप में पेश करने की मांग की है।

AP सरकार के फैसले के पक्ष में तर्क

- **पीजी शिक्षा बढ़ाने के लिए आवश्यक:** स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में शिक्षा की भाषा अंग्रेजी है। यूजी स्तर पर तेलुगु को शिक्षा के माध्यम के रूप में जारी रखने से छात्रों के एक समूह के लिए शिफ्ट में और देरी होगी। यह पीजी शिक्षा के अप्रत्यक्ष द्वार-पालन के समान होगा।
- **लोगों की पसंद के अनुरूप:** 2020-21 में यूजी स्तर पर एक ही माध्यम का चयन करने वाले तेलुगु-माध्यम पृष्ठभूमि के छात्रों का समूह डिग्री पाठ्यक्रमों में शामिल होने वाले पूल का केवल एक चौथाई था और राज्य सरकार का कहना है कि बड़ा हिस्सा यूजी पाठ्यक्रमों में प्रवेश करने वाले तेलुगु-माध्यम के छात्रों ने स्वयं अंग्रेजी शिक्षा का विकल्प चुना है।
- **छात्रों की रोजगार क्षमता को बढ़ाता है:** स्नातक स्तर पर अंग्रेजी सीखने से वैश्विक दुनिया में छात्रों की रोजगार क्षमता में वृद्धि होती है। सर्वेक्षण से पता चलता है कि अंग्रेजी प्रवाह के परिणामस्वरूप भारतीय पुरुषों के लिए प्रति घंटा वेतन में 34% तक का अंतर होता है, साथ ही सापेक्ष प्रवाह की डिग्री के साथ लाभ बढ़ता जा रहा है।
- **भविष्य के लिए तैयार होना:** भविष्य में अंग्रेजी कौशल और अधिक महत्वपूर्ण होने की संभावना है; प्रौद्योगिकी क्षेत्र (एआई, मशीन लर्निंग, बिग डेटा एनालिटिक्स) में भविष्य की नौकरियों के लिए, अंग्रेजी दक्षता तकनीकी प्रशिक्षण के रूप में महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए, राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि छात्रों को तेलुगु से अंग्रेजी में संक्रमण के लिए आवश्यक सभी सहायता मिले।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नई शिक्षा नीति 2020
- शिक्षा का अधिकार अधिनियम
- ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड

दिव्यांग व्यक्तियों को पदोन्नति में आरक्षण का अधिकार : सुप्रीम कोर्ट

भाग-जीएस प्रारंभिक और जीएस-II- न्यायपालिका; अधिकार और कर्तव्य

सुर्खियों में-

- SC ने फैसला सुनाया कि एक दिव्यांग व्यक्ति पदोन्नति के लिए आरक्षण का लाभ उठा सकता है, भले ही वह नियमित श्रेणी में भर्ती हुआ हो या रोजगार पाने के बाद विकलांग हो गया हो।
- 1995 का अधिनियम (निःशक्तजन अधिनियम 1995) एक ऐसे व्यक्ति के बीच अंतर नहीं करता है जिसने विकलांगता के कारण सेवा में प्रवेश किया हो और एक व्यक्ति जिसने सेवा में प्रवेश करने के बाद विकलांगता प्राप्त की हो।
- 1995 अधिनियम पदोन्नति में आरक्षण के अधिकार को मान्यता देता है।

पदोन्नति में आरक्षण की पृष्ठभूमि

- इंदिरा साहनी मामले (1992) में, SC ने कहा कि आरक्षण नीति को पदोन्नति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है।
- हालांकि, 77वें संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 16 में खंड 4A को शामिल किया और पदोन्नति में आरक्षण के प्रावधान को बहाल किया।

- नागराज निर्णय (2006) में, न्यायालय ने तीन नियंत्रण शर्तें निर्धारित कीं, जिन्हें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण देने से पहले राज्य को पूरा करना होगा
    - राज्य को वर्ग का पिछड़ापन दिखाना होगा
    - वर्ग को स्थिति या सेवा में अपर्याप्त रूप से दर्शाया गया है
    - आरक्षण प्रशासनिक दक्षता के हित में है
- जरनैल सिंह मामले (2018) में, इसने नागराज फैसले से पिछड़ेपन के प्रावधान के प्रदर्शन को रद्द कर दिया।

संबंधित आलेख:

सुगम्य भारत ऐप का शुभारंभ

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

राशन कार्ड सुधार

संदर्भ: हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड (ONORC) प्रणाली को लागू करने का निर्देश दिया, जो 31 जुलाई तक अंतर-राज्यीय पोर्टेबिलिटी की अनुमति देता है।

क्या आप जानते हो?

- सुवाह्य कल्याण लाभों का अर्थ है कि एक नागरिक को कल्याणकारी लाभों का उपयोग करने में सक्षम होना चाहिए चाहे वह देश में कहीं भी हो।
- खाद्य राशन के मामले में, यह विचार पहली बार 2011 में नंदन नीलेकणि के नेतृत्व वाले टास्क फोर्स द्वारा रखा गया था।
- 45.36 करोड़ लोग या 37% आबादी प्रवासी मजदूरों की है।

वन नेशन, वन राशन कार्ड क्या है?

- यह योजना पूरे देश में खाद्य सुरक्षा लाभों की सुवाह्यता प्रदान करने का प्रयास है।
- जिन परिवारों के पास खाद्य सुरक्षा कार्ड हैं, वे देश में किसी भी राशन की दुकान से रियायती दर पर राशन ले सकते हैं।
- इसे 2019 के मध्य में 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू किया गया था और इसे जून 2020 तक पूरे देश में शुरू किया जाना था, लेकिन महामारी के कारण इसमें देरी हुई।

राज्यों को बोर्ड पर ले जाना

- पुरातन सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) में इस सुधार को बढ़ावा देने के लिए, सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहन प्रदान किया।

ONORC कैसे काम करता है?

- ONORC प्रौद्योगिकी पर आधारित है जिसमें लाभार्थियों के राशन कार्ड, आधार संख्या और बिक्री के इलेक्ट्रॉनिक बिंदु (ePoS) का विवरण शामिल है।
- प्रणाली उचित मूल्य की दुकानों पर ePoS उपकरणों पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से एक लाभार्थी की पहचान करती है।
- सिस्टम दो पोर्टलों के समर्थन से चलता है -
    - **अन्नवितरण पोर्टल-** अंतर-राज्य लेनदेन का रिकॉर्ड रखता है - अंतर-जिला और अंतर-जिला
    - सार्वजनिक वितरण प्रणाली का एकीकृत प्रबंधन (IM-PDS)- अंतर-राज्यीय लेनदेन को रिकॉर्ड करता है।
- जब कोई राशन कार्ड धारक उचित मूल्य की दुकान पर जाता है, तो वह ePoS पर बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से अपनी पहचान करता है, जिसका वास्तविक समय अन्नवितरण पोर्टल पर विवरण के साथ मिलान किया जाता है।

- राशन कार्ड के विवरण सत्यापित होने के बाद, डीलर लाभार्थी के अधिकारों को सौंप देता है।

ONORC के लॉन्च के लिए किन कारकों का नेतृत्व किया?

- इससे पहले, NFSA के लाभार्थी अपने PDS लाभों को उस विशिष्ट उचित मूल्य की दुकान के अधिकार क्षेत्र के बाहर प्राप्त करने में सक्षम नहीं थे जिसे उन्हें सौंपा गया है।
- ONORC को शुरू में एक अंतर-राज्यीय पायलट के रूप में शुरू किया गया था। हालांकि, जब पिछले साल कोविड -19 महामारी ने हजारों प्रवासी श्रमिकों को अपने गांवों में लौटने के लिए मजबूर किया, तो रोलआउट में तेजी लाने की आवश्यकता महसूस की गई।
- कोविड आर्थिक राहत पैकेज के हिस्से के रूप में, सरकार ने मार्च 2021 तक सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ONORC के राष्ट्रीय रोलआउट की घोषणा की।

अब तक कवरेज क्या रहा है?

- अब तक, 32 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ONORC में शामिल हो चुके हैं, जिसमें लगभग 69 करोड़ NFSA लाभार्थी शामिल हैं। चार राज्यों को अभी इस योजना में शामिल होना बाकी है - असम, छत्तीसगढ़, दिल्ली और पश्चिम बंगाल।
- जबकि 32 राज्यों में अंतर-राज्य राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी उपलब्ध है, ऐसे लेनदेन की संख्या अंतर-जिला और अंतर-जिला लेनदेन की तुलना में बहुत कम है।

इन चार राज्यों ने अभी तक इसे लागू क्यों नहीं किया?

विभिन्न कारण हैं-

- उदाहरण के लिए, दिल्ली ने अभी तक उचित मूल्य की दुकानों में ePoS का उपयोग शुरू नहीं किया है, जो कि ONORC के कार्यान्वयन के लिए एक एक शर्त है।
- पश्चिम बंगाल के मामले में, राज्य सरकार ने मांग की है कि गैर-NFSA राशन कार्ड धारकों - राज्य सरकार द्वारा जारी राशन कार्ड को भी ONORC के तहत कवर किया जाना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- एक राष्ट्र एक चुनाव
- एक राष्ट्र एक गैस ग्रिड

लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता: बाल स्वराज पोर्टल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- बाल स्वराज पोर्टल के अनुसार, भारत में लगभग 10,000 बच्चों को तत्काल देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।
- इनमें मार्च 2020 से COVID-19 महामारी के दौरान शून्य से 17 वर्ष की आयु के अनाथ या लावरिश बच्चे शामिल हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

बाल स्वराज पोर्टल

- **द्वारा निर्मित:** राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR)
- **महत्व:** NCPCR ने इसे किशोर न्याय अधिनियम, 2015 की धारा 109 के तहत एक निगरानी प्राधिकरण की अपनी भूमिका के हिस्से के रूप में विकसित किया है और COVID-19 से प्रभावित होने वाले बच्चों की बढ़ती समस्या का समाधान करने के लिए इसे विकसित किया है।
- **उद्देश्य:**
    - ऑनलाइन ट्रैकिंग और

- उन बच्चों की रीयल-टाइम निगरानी जिन्होंने COVID-19 के दौरान माता-पिता दोनों को खो दिया है और जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

- **काम करना:** यह बाल कल्याण समिति (CWC) के समक्ष बच्चों को पेश करने से लेकर उनके माता-पिता/अभिभावक/रिश्तेदारों को बच्चों की बहाली और उसके बाद की अनुवर्ती कार्रवाई तक कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को ट्रैक करेगा।
    - प्रत्येक बच्चे का डाटा पोर्टल में जिला अधिकारी एवं राज्य अधिकारी द्वारा भरा जायेगा।

यह न्यूज़ क्यों मायने रखती है?

- इन बच्चों को तस्करी और देह व्यापार में धकेले जाने का अधिक जोखिम रहता है।
- आयोग को पहले ही सरकारी प्राधिकारियों द्वारा बच्चों के विवरण को निजी संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों को अवैध रूप से स्थानांतरित करने की कई शिकायतें प्राप्त हुई थीं।
- ये COVID-19 से बर्बाद हुए समाज के कमजोर वर्ग हैं।

स्वास्थय समस्या

संशोधित केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना (CGHS), राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN) की अम्ब्रेला योजनाएं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण (NHA) के आईटी प्लेटफॉर्म पर विवेकाधीन अनुदान (HMDG) को हाल ही में लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** स्वास्थ्य मंत्रालय
- **उद्देश्य:** कैशलेस, पेपरलेस और नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना।

महत्वपूर्ण तथ्य

केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS)

- यह सेवारत कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, संसद सदस्यों, पूर्व सांसदों आदि और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एक व्यापक स्वास्थ्य योजना है।

राष्ट्रीय आरोग्य निधि (RAN)

- RAN के तहत गंभीर जानलेवा बीमारियों से पीड़ित गरीब मरीजों को सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए 15 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है।
- RAN के तहत सेवाओं का लाभ उठाने के लिए पात्रता मानदंड राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार बीपीएल सीमा पर आधारित थे।

स्वास्थ्य मंत्री विवेकाधीन अनुदान (HMDG)

- एचएमडीजी के तहत उन रोगियों को अधिकतम 1.25 लाख रुपये प्रदान किए जाते हैं जिनकी वार्षिक आय 1.25 लाख रुपये से कम है।
- लाभार्थी अपना राशन कार्ड नंबर प्रदान करके दोनों योजनाओं के तहत वित्तीय सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं।

क्षतिपूर्ति और वैक्सीन मूल्य निर्धारण

संदर्भ: फाइजर, जो फाइजर-बायोएनटेक एमआरएनए वैक्सीन की आपूर्ति करता है, के बारे में कहा जाता है कि सरकार से जैब (प्रहार) मिलने के बाद किसी भी प्रतिकूल प्रभाव के आधार पर भविष्य में वैक्सीन उपयोगकर्ताओं से उत्पन्न होने वाले किसी भी दावे से इसकी क्षतिपूर्ति करने का अनुरोध किया है।

क्षतिपूर्ति क्या है और इसकी मांग क्यों की जाती है?

- क्षतिपूर्ति अनुबंध का एक रूप है।
- भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की धारा 124, क्षतिपूर्ति के अनुबंध को परिभाषित करती है, जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे पक्ष को होने वाले किसी भी नुकसान से बचाने का वादा करता है।
- अदालत द्वारा भुगतान का आदेश देने की स्थिति में, कंपनी सरकार से राशि वसूल करने की स्थिति में होगी।
- यदि किसी कंपनी को किसी विशेष दवा या टीके के लिए कोई क्षतिपूर्ति देती है, तो यह केवल भारत सरकार की ओर से निष्पादित क्षतिपूर्ति बांड के रूप में या किसी अनुबंध में खंड या खंड के सेट के रूप में हो सकती है कि सरकार आपूर्तिकर्ता के साथ हस्ताक्षर करे।
- भारत में किसी भी दवा के लिए ऐसी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने वाली किसी कंपनी के लिए कोई मिसाल नहीं है।

क्या क्षतिपूर्ति की मांग या अनुदान एक मानक प्रथा है?

- क्षतिपूर्ति अनिवार्य रूप से आपूर्तिकर्ता और प्राप्तकर्ता के बीच एक संविदात्मक मामला है, इसलिए, ऐसे समझौतों के साथ काफी गोपनीयता जुड़ी होती है।
- हालांकि, COVID-19 महामारी से उत्पन्न अजीबोगरीब वैश्विक स्थिति और भारत जैसे देशों द्वारा सामना किए जा रहे टीकों की कमी को देखते हुए, जिसे तत्काल लाखों लोगों को टीका लगाने की आवश्यकता है, शर्तें निर्धारित करने के लिए कुछ वैक्सीन आपूर्तिकर्ता इस स्थिति में हो सकते हैं ।

अब तक विदेशी कंपनियों को क्या मिला है?

- भारत के औषधि महानियंत्रक ने स्थानीय परीक्षणों की आवश्यकता को समाप्त कर टीकों के आयात में तेजी लाने की दिशा में पहले ही एक बड़ा कदम उठाया है।
- हालांकि, कंपनियों को शायद इस बात का डर है कि लक्ष्य प्राप्त करने के बाद प्रतिकूल रूप से प्रभावित किसी व्यक्ति के भविष्य के दावों से उत्पन्न होने वाले नुकसान के सामान्य कानून के तहत वे अभी भी उत्तरदायी होंगे।

क्षतिपूर्ति देने के क्या निहितार्थ हैं?

- **कम कीमत:** क्षतिपूर्ति के अभाव में, विदेशी निर्माता टीकों की कीमत पर जोखिम का भार डाल सकते हैं, जिससे प्रत्येक खुराक अधिक महंगी हो जाएगी। इन टीकों के संबंध में कंपनियों को क्षतिपूर्ति देकर, भारत सरकार कम कीमतों और अधिक मात्रा में बातचीत करने में सक्षम हो सकती है।
- **तेजी से टीकाकरण:** कम कीमतों और तेज उत्पादन से भारत के राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान में तेजी लाने में मदद मिल सकती है।
- **समान स्तर की मांग:** फाइजर से क्षतिपूर्ति की मांग ने घरेलू वैक्सीन-निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (SII) की समान मांग को पहले ही जन्म दे दिया है, जो कहता है कि सभी खिलाड़ियों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
- **सरकार को संपूर्ण जोखिम उठाने की आवश्यकता है:** समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा सभी को क्षतिपूर्ति प्रदान करना एक अरब से अधिक वैक्सीन लक्ष्य से जुड़े पूरा खतरा स्वयं पर आ रहा है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- वैक्सीन राष्ट्रवाद
- वैक्सीन कूटनीति
- टीकों के लिए ट्रिप्स छूट

UNGA का संकल्प 75/260

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - स्वास्थ्य; अंतरराष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने HIV/AIDS की रोकथाम पर संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly-UNGA) के 75वें सत्र को संबोधित किया।
- UNGA का संकल्प 75/260 HIV/AIDS पर प्रतिबद्धता की घोषणा और HIV/AIDS पर राजनीतिक घोषणाओं के कार्यान्वयन से संबंधित है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारत का अद्वितीय HIV निवारण मॉडल 'सामाजिक अनुबंध' (Social Contracting) की अवधारणा पर केंद्रित है, जिसके माध्यम से नागरिक समाज के समर्थन से 'लक्षित हस्तक्षेप कार्यक्रम (Targeted Interventions Program)' लागू किया जाता है।
- HIV/AIDS निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम, 2017 संक्रमित और प्रभावित आबादी के मानवाधिकारों की रक्षा के लिये एक कानूनी और सक्षम ढाँचा प्रदान करता है।
- भारत करीब 14 लाख लोगों को मुफ्त एंटी-रेट्रो-वायरल उपचार मुहैया करा रहा है।

अन्य पहल

- **सनराइज़ परियोजना:** स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2016 में भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों में विशेषकर ड्रग्स का इंजेक्शन लगाने वाले लोगों में बढ़ते HIV प्रसार से निपटने के लिये यह पहल शुरू की गई थी।
- **लाल रिबन:** लाल रिबन (Red Ribbon) HIV से पीड़ित लोगों के लिये जागरूकता और समर्थन का सार्वभौमिक प्रतीक है।
- **90-90-90 :** देश में HIV पॉज़िटिव लोगों में से 90 प्रतिशत लोग अपनी HIV स्थिति जान सकें, पॉज़िटिव HIV वाले 90 प्रतिशत लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएँ पहुँच सकें और इलाज तक पहुँच प्राप्त 90 प्रतिशत लोगों में इस वायरस के दबाव को कम किया जा सके।
- **एड्स, तपेदिक और मलेरिया से लड़ने के लिए वैश्विक कोष (GFATM):** इसे महामारी के रूप में एड्स, तपेदिक और मलेरिया की समाप्ति में तेज़ी लाने के लिये बनाया गया है।

अन्य संबंधित तथ्य

राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम

- **द्वारा शुरू किया गया:** राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन (NACO) 1992-1999 में शुरू किया गया।
    - NACO स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का एक प्रभाग है।
- भारत धीरे-धीरे HIV से पीड़ित लोगों को डोलटेग्रेविर (एक सुरक्षित और प्रभावोत्पादक एंटी-रेट्रो-वायरल दवा आहार) में परिवर्तित कर रहा है।

तीसरी लहर की तैयारी

संदर्भ: तथ्य यह है कि भारत ने संक्रमण की दूसरी गंभीर लहर का सामना किया, जिसने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को अभिभूत कर दिया, तीसरी लहर के लिए अच्छी तैयारी के महत्व को रेखांकित किया है।

यहां पांच चीजें हैं जो कोविड -19 संक्रमण की संभावित तीसरी लहर के प्रभाव को कम करने के लिए की जानी चाहिए।

1. टीकाकरण की गति बढ़ाएँ

- राष्ट्रव्यापी तीसरी लहर है या नहीं, यह निर्धारित करने में टीकाकरण की गति सबसे अधिक मायने रखती है।
- इसलिए सरकार को टीकाकरण की गति बढ़ाने की जरूरत है।

2. परीक्षण सुविधाओं का विस्तार करने की आवश्यकता है

- समय पर जांच करना और संक्रमित मरीजों को आइसोलेट करना ही कोविड-19 संक्रमण को रोकने की कुंजी है।
- देश के 735 जिलों में से 31 में कोई नमूना संग्रह केंद्र नहीं था। 99 में सिर्फ एक संग्रह केंद्र था। स्पष्ट रूप से, इसे बदलने की जरूरत है, अगर महामारी की बेहतर निगरानी करनी है।

3. लोगों, विशेषकर गरीबों को चिकित्सकीय सलाह लेने के लिए प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।

- नजदीकी स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव और वहनीयता गरीबों के बीच चिकित्सा सलाह न लेने के कारण हैं।
- शुरुआती परीक्षण और उपचार चाहने वाले संदिग्ध रोगियों के व्यवहार में बदलाव की आवश्यकता है क्योंकि कोविड-19 की शुरुआत बुखार और सर्दी जैसे सामान्य लक्षणों से होती है।

4. कोविड -19 अस्पताल में भर्ती के वित्तीय बोझ को स्वीकार करें

- एक औसत कोविड-19 अस्पताल में भर्ती होने के मामले में 50,000 रुपए से अधिक खर्च होने की संभावना है।
- COVID अस्पताल में भर्ती होने के खर्च के लिए बैंकों से सॉफ्ट लोन जैसे सरकारी पक्ष से कुछ मदद प्रदान करना तीसरी लहर की तैयारी में एक लंबा रास्ता तय करेगा।

5. स्वास्थ्य बीमा कवर के विस्तार से मदद मिलेगी

- 2017-18 के NSO सर्वेक्षण के अनुसार, भारत में अस्पताल में भर्ती होने के तीन-चौथाई से अधिक मामलों में ऐसे व्यक्ति शामिल हैं जो स्वास्थ्य व्यय बीमा या योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।
- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY) जिसे 2018 में शुरू किया गया था, को महामारी के समय की जरूरतों के अनुरूप विस्तारित और संशोधित करने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PM-JAY)
- स्वास्थ्य पर आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21
- स्वास्थ्य डेटा प्रबंधन नीति: राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- भारतीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ब्रेन ड्रेन
- भारत में चिकित्सा ऑक्सीजन संकट

भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रौद्योगिकी

संदर्भ: WHO के अनुसार "सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज (UHC) सार्वजनिक स्वास्थ्य की पेशकश करने वाली एकमात्र सबसे शक्तिशाली अवधारणा है। यह एक शक्तिशाली सामाजिक तुल्यकारक और निष्पक्षता की अंतिम अभिव्यक्ति है।"

UHC के लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए उभरती प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाया जा सकता है, इनमें से कुछ हैं-

- **रोबोट:** अस्पताल रोबोट का उपयोग COVID-19 रोगियों को दवाएं और भोजन पहुंचाने के लिए कर सकते हैं। इससे अस्पताल के कर्मचारियों को संक्रमण होने की संभावना कम हो जाती है।
- **ब्लॉकचैन प्रौद्योगिकी:** स्वास्थ्य ब्लॉकचैन में सभी चिकित्सा डेटा का एक संपूर्ण अनुक्रमित इतिहास होगा, जिसमें औपचारिक चिकित्सा रिकॉर्ड और मोबाइल एप्लिकेशन और पहनने योग्य सेंसर से स्वास्थ्य डेटा शामिल है। यह स्वास्थ्य सूचना और प्रौद्योगिकी प्रणालियों के सामने आने वाली अंतःक्रियाशीलता चुनौतियों को दूर करने में मदद करता है।
- **AI और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स:** IoMT को चिकित्सा उपकरणों, सॉफ्टवेयर अनुप्रयोगों और स्वास्थ्य प्रणालियों और सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे के रूप में परिभाषित किया जाता है। IoMT का उपयोग स्वास्थ्य देखभाल अनुप्रयोगों को प्रदान करने के लिए किया जाता है जो बीमारी के त्वरित निदान में मदद करता हैं।
- क्लाउड कंप्यूटिंग एक अन्य एप्लिकेशन है जो डॉक्टरों, विभागों और यहां तक कि संस्थानों और चिकित्सा प्रदाताओं के बीच सहयोग और डेटा के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करता है ताकि सर्वोत्तम उपचार सक्षम हो सके।

उपरोक्त प्रौद्योगिकियों के लिए संभावित चुनौतियाँ क्या हैं?

इस प्रयास में संभावित बाधाएं हैं

- स्वास्थ्य डेटा का मानकीकरण
- डेटा साझा करने के लिए एक टेम्पलेट विकसित करना
- उच्च निवेश

आगे की राह

- **डिजिटल रणनीति:** भारत को अपनी डिजिटल स्वास्थ्य रणनीति अपनानी होगी जो काम करती है और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज और व्यक्ति-केंद्रित देखभाल की ओर ले जाती है। इस तरह की रणनीति को डिजिटल प्रौद्योगिकियों की नैतिक उपयुक्तता पर जोर देना , डिजिटल विभाजन को पार करना और अर्थव्यवस्था में समावेश सुनिश्चित करना चाहिए।
- **स्थानीय ज्ञान का उपयोग करना:** मजबूत स्वास्थ्य प्रणालियों के अलावा, एक प्रभावी राष्ट्रीय प्रतिक्रिया भी स्थानीय ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। भारत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थानीय/पारंपरिक ज्ञान और अनुभव की जांच कर आधुनिक तकनीक के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन
- डिजिटल दुनिया में महामारी और असमानता
- एकीकृत स्वास्थ्य सूचना मंच (IHIP)

सफेद खाद्य पदार्थों का सेवन कई गुना बढ़ा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II- स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- सफेद खाद्य पदार्थ वे होते हैं जिन्हें संसाधित और परिष्कृत किया जाता है, जैसे कि परिष्कृत गेहूं का आटा, सफेद चावल, सफेद ब्रेड, सफेद पास्ता और साधारण शर्करा जैसे सफेद परिष्कृत चीनी, शहद और उच्च फ्रुक्टोज कॉर्न सिरप।
- बेकरी और मसाला उद्योग, जो मुख्य सामग्री के रूप में परिष्कृत गेहूं के आटे और सफेद चीनी का उपयोग करते हैं, ये तेजी से बढ़े हैं।

सफेद खाद्य पदार्थों के सेवन के हानिकारक प्रभाव

- फास्ट फूड, क्रोइसैन्ट, सफेद ब्रेड और पनीर का अधिक सेवन खराब ग्लाइसेमिक नियंत्रण से विपरीत रूप से जुड़ा था।
- साक्ष्य ने लगातार परिष्कृत चीनी की बड़ी खपत, विशेष रूप से शर्करा पेय के रूप में, मोटापे और पेट की चर्बी के संचय के साथ जोड़ा है जो मधुमेह और हृदय रोगों का कारण बनता है।
- शुगर सीधे तौर पर एसोफैगल एडेनोकार्सिनोमा, छोटी आंत के कैंसर और फुफ्फुस कैंसर के अधिक जोखिम से जुड़ा था।
- गुलाबी, नीले और काले नमक के साथ सफेद टेबल नमक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। लेकिन अधिक मात्रा में सेवन करने पर यह उच्च रक्तचाप, क्रोनिक किडनी रोग और ऑस्टियोपोरोसिस जैसे नकारात्मक स्वास्थ्य परिणाम उत्पन्न करता है।

स्वस्थ सफेद खाद्य पदार्थ

- कुछ सफेद खाद्य पदार्थ समग्र स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। कुछ उदाहरणों में शामिल हैं - फूलगोभी, प्याज, लहसुन, मूली, मशरूम, काजू, तिलहन।

सफेद खाद्य पदार्थों के सेवन से बचने के सुझाव

- सफेद ब्रेड को होल या मल्टी ग्रेन ब्रेड से बदला जा सकता है, ओट्स जिसमें अधिक फाइबर महत्वपूर्ण सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं।
- वांछित स्वाद लाने के लिए सफेद और अन्य लवणों को जड़ी-बूटियों और मसालों से बदला जा सकता है।

संबंधित लेख: जीवनशैली से जुड़ी बीमारियां भारतीयों के लिए सबसे बड़ा स्वास्थ्य खतरा।

WHO ने गिनी में इबोला के प्रकोप की घोषणा की

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II- स्वास्थ्य

सुर्खियों में-

- हाल ही में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने यह घोषणा की है कि फरवरी 2021 में गिनी में शुरू हुआ इबोला का प्रकोप अब खत्म हो गया है।

इबोला वायरस रोग (EVD) के बारे में

- इबोला वायरस रोग (EVD), जिसे पहले इबोला रक्तस्रावी बुखार के रूप में जाना जाता था, मनुष्यों में होने वाली एक गंभीर, घातक बीमारी है।
- यह वायरस जंगली जानवरों से लोगों में फैलता है और मानव आबादी में मानव-से-मानव में संचरण करता है।
- **संचरण:** फ्रूट बैट' टेरोपोडीडेई परिवार (Pteropodidae family) से संबंधित है जो वायरस के प्राकृतिक वाहक (Natural Hosts) है।
    - **जानवरों से मानव संचरण:** इबोला का संक्रमण उन जानवरों के रक्त, स्राव, अंगों या अन्य शारीरिक तरल पदार्थों जैसे कि फ्रूट बैट, चिंपांजी, गोरिल्ला, बंदर, वन मृग या पोर्कपीस के साथ निकट संपर्क के माध्यम से मानव आबादी में फैलता है। यह वायरस बीमार या मृत अवस्था में पाए जाते हैं या वर्षावनों में पाए जाते हैं।
    - **मानव से मानव संचरण:** इबोला सीधे संपर्क (टूटी हुई त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली के माध्यम से) के साथ फैलता है:
- जो व्यक्ति इबोला से बीमार है या उसकी मृत्यु हो गई है उसके रक्त या शरीर के तरल पदार्थ के संपर्क में आने से फैलता है।
- ऐसे शरीर के तरल पदार्थ (जैसे रक्त, मल, उल्टी) से दूषित वस्तुएँ।
- **लक्षण:**
    - यह अचानक हो सकता है और इसमें शामिल हैं: बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द, सिरदर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, गुर्दे का ख़राब होना और यकृत कार्य संबंधित लक्षण तथा कुछ मामलों में आंतरिक और बाहरी रक्तस्राव ।
- **निदान:**
    - एलिसा (ELISA) (antibody-capture enzyme-linked immunosorbent assay)
    - रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पोलीमरेज़ चेन रिएक्शन (RT-PCR) एक प्रयोगशाला तकनीक आदि।
- **टीके:**
    - एर्वेबो वैक्सीन (Ervebo vaccine)।
    - मई 2020 में यूरोपियन मेडिसिन एजेंसी ने 1 वर्ष और उससे अधिक उम्र के व्यक्तियों के लिये ज़ब्डेनो-एंड-मावाबिया (Zabdeno-and-Mvabea) नामक टीके के 2-घटक को विपणन प्राधिकरण देने की सिफारिश की।
- **उपचार:**
    - अमेरिका द्वारा वयस्कों और बच्चों में जाइरे इबोला वायरस संक्रमण के इलाज के लिये दो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी (Inmazeb and Ebanga) को मंज़ूरी दी गई है।

सरकारी योजनाएँ

बच्चों के लिए PM-CARES योजना

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने कोविड-19 के कारण अनाथ हुए सभी बच्चों के लिए "पीएम-केयर्स फॉर चिल्ड्रन" योजना की घोषणा की।
- साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने ज़िला अधिकारियों को 'राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग' (NCPCR) द्वारा निर्मित 'बाल स्वराज' पोर्टल पर ऐसे बच्चों का विवरण प्रदान करने का आदेश दिया है, जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है।

योजना की मुख्य विशेषताएं

- **10 लाख रुपये का कोष:**
  - इनमें से प्रत्येक बच्चे को पीएम केयर फंड से 10 लाख रुपए का कोष आवंटित किया जाएगा।
  - यह 18 वर्ष की आयु से मासिक स्कॉलरशिप प्रदान करेगा।
  - 23 वर्ष पूरे होने पर, उसे एकमुश्त के रूप में कोष की राशि मिलेगी।
- **बच्चों को शिक्षा (10 वर्ष से कम):**
  - केन्द्रीय विद्यालयों/निजी स्कूलों में प्रवेश सुनिश्चित।
  - समान पाठ्य पुस्तकों और नोटबुक के लिए PM CARES भुगतान करेगा
  - यदि बच्चे को किसी निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाता है तो RTE मानदंडों के अनुसार शुल्क प्रदान किया जाएगा
- **बच्चों को शिक्षा (11-18 वर्ष):**
  - बच्चे को केंद्र सरकार के किसी भी आवासीय विद्यालय में प्रवेश दिया जाएगा
  - यदि बच्चे को अभिभावक की देखरेख में जारी रखना है, तो उसे नजदीकी केन्द्रीय विद्यालय/निजी स्कूल में प्रवेश दिया जाएगा।
- **उच्च शिक्षा:**
  - ट्यूशन फीस/शैक्षिक ऋण के बराबर छात्रवृत्ति का प्रावधान।
  - ऋण पर ब्याज का भुगतान PM-CARES फंड द्वारा किया जाएगा।
- **स्वास्थ्य बीमा:**
  - सभी बच्चों को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी के रूप में नामांकित किया जाएगा
  - ऐसे बच्चों के 18 वर्ष के होने तक प्रीमियम राशि का भुगतान पीएम-केयर्स फंड द्वारा किया जाएगा।

सेज (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन) पहल का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II- नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- SAGE (सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन') पहल और सेज पोर्टल हाल ही में लॉन्च किया गया।
- **मंत्रालय:** सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय,

- **उद्देश्य:** भारत के बुजुर्गों की सहायता करना

पहल के बारे में:

- SAGE पोर्टल विश्वसनीय स्टार्ट-अप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं का "वन-स्टॉप एक्सेस" होगा।
- प्रत्येक चयनित स्टार्ट-अप को एकमुश्त इक्विटी के रूप में रु.1 करोड़ तक की निधि प्रदान की जाएगी।
- रजत की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि आवंटित की गई है।

अन्य संबंधित तथ्य

- रजत की अर्थव्यवस्था वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण और खपत की प्रणाली है जिसका उद्देश्य वृद्ध और वृद्ध लोगों की क्रय क्षमता का उपयोग करना और उनके उपभोग, जीवन और स्वास्थ्य की जरूरतों को पूरा करना है।
- इससे पहले एक वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष 2016 में शुरू किया गया था।

स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण-II

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - गवर्नेंस

सुर्खियों में-

- स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) [SBM (G)] चरण- II कोविड-19 महामारी की वजह से उत्पन्न चुनौतियों के बीच लगातार प्रगति कर रहा है, जिसमें 1249 गाँवों को ODF (खुले में शौच मुक्त) प्लस घोषित किया गया है।

SBM (G) चरण- II के बारे में:

- SBM (G) चरण- II को फरवरी 2020 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा अनुमोदित किया गया था और इसे वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक की अवधि के लिये 1,40,881 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ एक मिशन के रूप में कार्यान्वित किया जाएगा।
- केंद्र और राज्यों के बीच सभी घटकों के लिये फंड शेयरिंग का अनुपात पूर्वोत्तर राज्यों, हिमालयी राज्यों और जम्मू एवं कश्मीर केंद्रशासित प्रदेश के लिये 90:10, अन्य राज्यों के लिये 60:40 और अन्य केंद्रशासित प्रदेशों के लिये 100 होगा।

SBM के हिस्से के रूप में अन्य योजनाएं:

- **व्यक्तिगत घरेलू शौचालय (IHHL):** SBM के तहत लोगों को शौचालय निर्माण के लिये लगभग 15 हज़ार रुपए मिलते हैं।
- **गोबर-धन (Galvanizing Organic Bio-Agro Resources Dhan- GOBAR-DHAN) योजना:** इसे वर्ष 2018 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया था। इस योजना का उद्देश्य गाँवों को स्वच्छ रखना, ग्रामीण घरों की आय बढ़ाना और मवेशियों द्वारा उत्पन्न कचरे से ऊर्जा का उत्पादन करना है।
- **स्वच्छ विद्यालय अभियान:** शिक्षा मंत्रालय ने एक वर्ष के भीतर सभी सरकारी स्कूलों में लड़कों और लड़कियों के लिये अलग-अलग शौचालय उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छ विद्यालय कार्यक्रम शुरू किया।

उचित मूल्य की दुकानों पर इलेक्ट्रॉनिक माप तौल मशीनें

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों से राशन की दुकानों हेतु इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल डिवाइस बचत (ePoS) से इलेक्ट्रॉनिक तौल मशीन खरीदने को कहा है।

- इसके लिये उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने ई-पीओएस उपकरणों के विवेकपूर्ण उपयोग के माध्यम से बचत करने हेतु राज्यों को प्रोत्साहित करने के लिये खाद्य सुरक्षा नियम (राज्य सरकार के लिये सहायता नियम) 2015 में संशोधन किया है।
- **लाभ:**
    - इलेक्ट्रॉनिक तौल तराजू के साथ ईपीओएस उपकरणों का एकीकरण, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न के वितरण में लाभार्थियों को उनकी पात्रता के अनुसार लाभान्वित करेगा।
    - ईपीओएस उपकरणों के माध्यम से बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण द्वारा लक्षित लाभार्थी को सब्सिडी वाला खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के बारे में

- **उद्देश्य:** सम्मान के साथ जीवन जीने के लिये लोगों को सस्ती कीमतों पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तक पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना।
- **कवरेज:** लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न प्राप्त करने के लिये 75% ग्रामीण आबादी और 50% शहरी आबादी को कवरेज प्रदान किया गया है।
- **पात्रता:**
    - राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्राथमिकता वाले परिवारों को TPDS के तहत कवर किया जाना है।
    - मौजूदा अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत आने वाले परिवार।
- **प्रावधान:**
    - 5 किलोग्राम खाद्यान्न प्रति व्यक्ति प्रति माह रु. 3/2/1 प्रति किलोग्राम चावल/गेहूं/मोटे अनाज के लिए।
    - 14 वर्ष तक के बच्चों को भोजन।
    - खाद्यान्न या भोजन की आपूर्ति न होने की स्थिति में लाभार्थियों को खाद्य सुरक्षा भत्ता।
    - ज़िला और राज्य स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र की स्थापना।

मिशन कर्मयोगी के लिए विशेष प्रयोजन वाहन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप

सुर्खियों में-

- हाल ही में अपने महत्त्वाकांक्षी "मिशन कर्मयोगी (Mission Karmayogi)" के माध्यम से प्रमुख नौकरशाही सुधार लाने में सरकार की मदद करने के लिये एक तीन सदस्यीय टास्क फोर्स का गठन किया गया है।
    - केंद्र ने हाल ही में देश में सभी सिविल सेवाओं की भूमिका हेतु क्षमता विकास के लिये नियम आधारित प्रशिक्षण द्वारा परिवर्तनकारी बदलाव लाने हेतु 'सिविल सेवा क्षमता विकास के लिये राष्ट्रीय कार्यक्रम- मिशन कर्मयोगी (National Programme for Civil Services Capacity Building – Mission Karmayogi)' को मंज़ूरी दी है।

टास्क फोर्स के बारे में

- इस सक्षमता संचालित मिशन को प्रभावी ढंग से चलाने के लिये एक विशेष प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) अर्थात् 'कर्मयोगी भारत' को एक गैर-लाभकारी कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- इसे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के तहत 100% सरकारी स्वामित्व वाली इकाई के रूप में स्थापित किया जाएगा।
- **SPV उत्तरदायी होगा:**
- टेलीमेट्री डेटा के शासन का प्रबंधन और निगरानी और मूल्यांकन का प्रावधान सुनिश्चित करना।

- टास्क फोर्स अपने विज़न, मिशन और कार्यों को संरेखित करते हुए SPV की संगठनात्मक संरचना पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करेगा।

परिवर्तनकारी शहरी मिशनों के 6 वर्ष

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II- राजनीति और शासन

सुर्खियों में-

- हाल ही में आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) ने तीन परिवर्तनकारी शहरी मिशनों [स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM), अटल शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (AMRUT) तथा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)] के छह वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक ऑनलाइन कार्यक्रम का आयोजन किया।

मिशन	विवरण	प्रगति
प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)	इसे 25 जून, 2015 को लॉन्च किया गया था और इसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिये आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना पात्र शहरी गरीबों के लिये पक्का घर सुनिश्चित करके झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले लोगों समेत शहरी गरीबों के बीच शहरी आवास की कमी को दूर करती है।	• 1.1 से करोड़ मकान स्वीकृत • पहली बार 18 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले MIG को दिए गए होम लोन पर ब्याज सब्सिडी क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना। • शहरी प्रवासियों/गरीबों के लिए किफायती किराये के आवास परिसरों को कोविड -19 द्वारा प्रेरित रिवर्स माइग्रेशन की प्रतिक्रिया के रूप में लॉन्च किया गया।
अमृत मिशन	• घरों में पानी की आपूर्ति, सीवरेज आदि जैसी बुनियादी सेवाएं प्रदान करने और शहरों में सुविधाओं का निर्माण करने का लक्ष्य है। • अमृत के तहत 500 शहरों का चयन किया गया।	• अमृत मिशन के तहत अब तक 1.05 करोड़ घरेलू नल कनेक्शन और 78 लाख सीवर /सेप्टेज कनेक्शन प्रदान किये गए हैं। • 101 लाख के लक्ष्य की तुलना में 88 एलईडी स्ट्रीट लाइटों को ऊर्जा दक्ष एलईडी लाइटों से बदला गया है जिससे 193 करोड़ यूनिट ऊर्जा की बचत हुई है। • ऊर्जा एवं संसाधन संस्थान (TERI) के अनुसार, अमृत के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से 84.6 लाख टन कार्बन फुटप्रिंट को कम किया गया।
स्मार्ट सिटीज़ मिशन (SCM)	• उन शहरों को बढ़ावा देना है जो अपने नागरिकों को स्मार्ट समाधान जैसे स्मार्ट ग्रिड स्मार्ट वाटर IoT आदि का उपयोग करने के लिए बुनियादी बुनियादी ढांचा, स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण प्रदान करते हैं।	• स्मार्ट सिटी मिशन के तहत 70 शहरों ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों (ICCCs) का विकास और संचालन किया है, जिनका उपयोग कोविड प्रबंधन के लिए वॉर रूम के रूप में किया गया।

अंतरराष्ट्रीय

चीन की बाल नीति

संदर्भ : 1950 के दशक के बाद से चीन की जनगणना के आंकड़ों में जनसंख्या वृद्धि धीमी गति से घटने के कुछ दिनों बाद, देश ने घोषणा की है कि वह अब प्रति विवाहित जोड़े में तीन बच्चों की अनुमति देगा - पांच साल बाद पहली बार अपनी विवादास्पद एक-बाल नीति को दो तक सीमित कर दिया।

चीन की एक बच्चे की नीति कितनी कारगर रही?

- **जनसंख्या वृद्धि आर्थिक विकास में बाधक:** चीन द्वारा 'वन चाइल्ड पॉलिसी' की शुरुआत वर्ष 1980 में की गई थी, उस समय चीन की जनसँख्या लगभग एक अरब के करीब थी और चीनी-सरकार को इस बात की चिंता थी कि देश की बढ़ती आबादी, आर्थिक प्रगति को बाधित करेगी।
- **प्रारंभिक सफलता:** चीनी प्राधिकारियों द्वारा लंबे समय तक इस नीति को एक सफलता के रूप में बताया जाता रहा और दावा किया गया कि इस नीति ने लगभग 40 करोड़ लोगों को पैदा होने से रोककर देश के समक्ष आने वाली भोजन और पानी की कमी संबंधी गंभीर समस्याओं को टालने में मदद की है।
- **एक बच्चे की नीति की आलोचना:** हालाँकि यह नीति देश में असंतोष का एक कारण भी थी क्योंकि राज्य द्वारा जबरन गर्भपात और नसबंदी जैसी क्रूर रणनीति का इस्तेमाल किया गया। इसकी आलोचना भी की गई और यह मानवाधिकारों के उल्लंघन एवं गरीबों के साथ अन्याय करने के लिये विवादास्पद रही। क्योंकि अमीर लोग नीति का उल्लंघन करने पर आर्थिक प्रतिबंधों का भुगतान कर सकते थे।
- **सामाजिक नियंत्रण का उपकरण:** इसके अतिरिक्त, चीन के शासकों पर सामाजिक नियंत्रण के एक उपकरण के रूप में प्रजनन सीमाओं को लागू करने का आरोप लगाया गया। उदाहरण के लिए, उइगर मुस्लिम जातीय अल्पसंख्यक अपनी जनसंख्या के विकास को प्रतिबंधित करने के लिए कम बच्चे पैदा करने के लिए मजबूर किया गया।
- **तेजी से उम्र बढ़ने की समस्या:** विशेषज्ञों ने अन्य देशों की तुलना में चीन की जनसंख्या की उम्र को तेजी से बढ़ने, देश की विकास क्षमता को प्रभावित करने के लिए नीति को भी दोषी ठहराया है। उदाहरण के लिए, भारत की जनसंख्या इस सदी के मध्य से बूढ़ी होने लगेगी।

क्या वन चाइल्ड पॉलिसी में ढील देने से मदद मिली?

- वर्ष 2016 में अपनी जनसंख्या वृद्धि दर में तीव्र गिरावट को देखते हुए वन चाइल्ड पॉलिसी को परिवर्तित करते हुए चीनी सरकार ने अंततः प्रत्येक विवाहित जोड़े को दो बच्चे पैदा करने की अनुमति दी।
- हालांकि, नीति में बदलाव जो बहुत कम हुआ। इस महीने की शुरुआत में जारी चीनी जनगणना, 2020 के आँकड़ों के बाद यह घोषणा की गई थी कि वर्ष 2016 में प्रदान की गई छूट के बावजूद देश की जनसंख्या वृद्धि दर तेज़ी से गिर रही है।
- 2025 तक, यह देश भारत से अपना 'सबसे अधिक आबादी वाला' टैग खो देगा, जिसमें 2020 में अनुमानित 138 करोड़ लोग थे, जो चीन से 1.5 प्रतिशत पीछे था।

थ्री चाइल्ड पॉलिसी के बारे में कई लोग संशय में क्यों रहते हैं?

विशेषज्ञों का कहना है कि केवल प्रजनन अधिकारों पर ढील देने से एक अवांछित जनसांख्यिकीय बदलाव को टालने में बहुत मदद नहीं मिल सकती है।

- **आर्थिक कारक:** कम बच्चों के जन्म के पीछे मुख्य कारक, जीवन यापन की बढ़ती लागत, शिक्षा और वृद्ध माता-पिता का समर्थन करना। लंबे समय तक काम करने की देश की व्यापक संस्कृति से समस्या और भी बदतर हो गई है।
- **सांस्कृतिक बदलाव:** दशकों के दौरान एक सांस्कृतिक बदलाव भी आया है जिसमें एक बच्चा नीति लागू रही, कई जोड़ों का मानना था कि एक बच्चा पर्याप्त है, और कुछ बच्चे पैदा करने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं।

प्रश्न : क्या भारत को भी चीन की आबादी को नियंत्रित करने का तरीका अपनाना चाहिए?

कैबिनेट ने मास मीडिया सहयोग पर SCO समझौते को कार्योत्तर मंजूरी दी

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- केंद्रीय सरकार ने शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के सभी सदस्य देशों के बीच "मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" के लिये एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुमोदन को मंज़ूरी दे दी है।
- जून 2019 में इस समझौते पर हस्ताक्षर किये गए थे।

"मास मीडिया के क्षेत्र में सहयोग" पर समझौते के बारे में

- **उद्देश्य:** मास मीडिया के क्षेत्र में संघों के बीच समान और पारस्परिक रूप से लाभप्रद सहयोग को बढ़ावा देना।
- यह समझौता सदस्य देशों को मास मीडिया के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों और नवीन नवाचारों को साझा करने का अवसर प्रदान करेगा।

प्रमुख बिंदु

- अपने राज्यों के लोगों के जीवन के बारे में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिये मास मीडिया के माध्यम से सूचनाओं के व्यापक वितरण हेतु एक अनुकूल प्रणाली का निर्माण।
- यह मीडिया पेशेवरों को प्रशिक्षित करने में पारस्परिक सहायता प्रदान करेगा।

यह समाचार क्यों मायने रखती है?

- मास मीडिया लोगों को सूचित, शिक्षित और मनोरंजन करता है।
- वे लोगों के दुनिया को देखने के तरीके को प्रभावित करते हैं और उनसे अपने विचार बदलते हैं।
- वे जनमत को व्यवस्थित करने में मदद करते हैं।

अन्य सम्बंधित तथ्य

शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

- SCO एक स्थायी अंतर-सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है।
- यह एक यूरेशियन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा संगठन है, जिसका उद्देश्य संबंधित क्षेत्र में शांति, सुरक्षा व स्थिरता बनाए रखना है।
- **स्थापित:** 2001
- **सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था:** राज्य परिषद के प्रमुख (HSC)
- यह साल में एक बार मिलता है।
- **दो स्थायी निकाय:**
    - बीजिंग में स्थित SCO सचिवालय।
    - ताशकंद में स्थित क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना (RATS) की कार्यकारी समिति।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - स्वास्थ्य; अंतरराष्ट्रीय

सुर्खियों में-

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) द्वारा आयोजित विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस (7 जून) समारोह में वर्चुअल माध्यम से भाग लिया।
- पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित भोजन तक पहुँच जीवन को बनाए रखने और अच्छे स्वास्थ्य को बढ़ावा देने की कुंजी है।
- वैश्विक खाद्य अपशिष्ट वैश्विक ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन का 6.7% है, जो सीधे तौर पर जलवायु परिवर्तन का कारण बनता है।

विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के बारे में

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और संयुक्त राष्ट्र का खाद्य और कृषि संगठन (FAO) संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के पालन की सुविधा प्रदान करते हैं।
- यह पहली बार वर्ष 2019 में "द फ्यूचर ऑफ फूड सेफ्टी" के तहत अदीस अबाबा सम्मेलन और जिनेवा फोरम द्वारा 2019 में की गई खाद्य सुरक्षा को बढ़ाने की प्रतिबद्धता को मज़बूत करने के लिये मनाया गया था।
- **उद्देश्य:** खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि, कृषि, बाजार पहुंच, पर्यटन और सतत विकास में योगदान करने, खाद्य जनित जोखिमों को रोकने, पता लगाने और प्रबंधित करने में मदद करने के लिए ध्यान आकर्षित करना और कार्रवाई को प्रेरित करना।
- **2021 की थीम :** स्वस्थ कल के लिये सुरक्षित भोजन।

अन्य सम्बंधित तथ्य

खाद्य सुरक्षा के लिए भारतीय पहल:

- FSSAI ने खाद्य सुरक्षा के पाँच मापदंडों पर राज्यों के प्रदर्शन को मापने के लिये राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक (SFSI) विकसित किया है। मापदंडों में मानव संसाधन और संस्थागत व्यवस्था, अनुपालन, खाद्य परीक्षण- बुनियादी ढाँचे और निगरानी, प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण एवं उपभोक्ता अधिकारिता शामिल हैं।
- **ईट राइट इंडिया मूवमेंट:** यह सभी भारतीयों के लिये सुरक्षित, स्वस्थ और टिकाऊ भोजन सुनिश्चित करने हेतु देश की खाद्य प्रणाली को बदलने के लिये भारत सरकार और FSSAI की एक पहल है।
- **ईट राइट अवार्ड्स:** FSSAI ने नागरिकों को सुरक्षित और स्वस्थ भोजन विकल्प चुनने के लिये खाद्य कंपनियों तथा व्यक्तियों के योगदान को मान्यता देने हेतु 'ईट राइट अवार्ड्स' की स्थापना की है, जो उनके स्वास्थ्य और कल्याण को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **ईट राइट मेला:** FSSAI द्वारा आयोजित यह नागरिकों को सही खाने हेतु प्रेरित करने के लिये एक आउटरीच गतिविधि है। यह विभिन्न प्रकार के भोजन के स्वास्थ्य और पोषण लाभों के बारे में नागरिकों को जागरूक करने के लिये आयोजित किया जाता है।

यह भी पढ़ें: COVID-19 और खाद्य सुरक्षा

आई-फैमिलिया (I-Familia) : लापता व्यक्तियों की पहचान के लिये वैश्विक डेटाबेस

भाग- जीएस प्रीलीम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय

सुर्खियों में-

- हाल ही में इंटरपोल ने परिवार के डीएनए के माध्यम से लापता व्यक्तियों की पहचान करने और सदस्य देशों के जटिल मामलों को सुलझाने में पुलिस की मदद करने के लिये आई-फैमिलिया (I-Familia) नामक एक नया वैश्विक डेटाबेस लॉन्च किया है।

आई-फैमिलिया के बारे में

- बढ़ती अंतर्राष्ट्रीय यात्राएँ, संगठित अपराध और मानव तस्करी के प्रसार, वैश्विक प्रवासन, संघर्ष और प्राकृतिक आपदाओं में वृद्धि के कारण दुनिया भर में लापता व्यक्तियों और अज्ञात पीड़ितों की संख्या के बारे में अंतरराष्ट्रीय चिंताएँ बढ़ रही हैं।
- अपनी तरह का पहला, I-Familia अंतर्राष्ट्रीय डीएनए (डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड) नातेदारी संबंधों के आधार पर लापता व्यक्तियों की पहचान करने के लिये इस प्रकार का पहला वैश्विक डेटाबेस है।
- डेटाबेस लापता व्यक्तियों या अज्ञात मानव अवशेषों को परिवार के सदस्यों के डीएनए नमूनों का उपयोग करके पहचान करता है , जबकि इसकी प्रत्यक्ष तुलना संभव नहीं है।
- परिवार के सदस्यों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खोज के लिये अपने डेटा का उपयोग करने हेतु सहमति देनी होगी।

अन्य सम्बंधित तथ्य

अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल)

- अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) एक अंतर-सरकारी संगठन है जो 194 सदस्य देशों के पुलिस बल के समन्वय में मदद करता है।
- प्रत्येक सदस्य देश एक इंटरपोल राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो (NCB) का आयोजन करता है जो यह उनके राष्ट्रीय कानून प्रवर्तन को अन्य देशों और सामान्य सचिवालय से जोड़ता है।
- केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को भारत के राष्ट्रीय केंद्रीय ब्यूरो के रूप में नामित किया गया है।
- इंटरपोल द्वारा जारी किया जाने वाला नोटिस सदस्य देशों में पुलिस को अपराध से संबंधित महत्त्वपूर्ण जानकारी साझा करने में सहयोग या अलर्ट (Alert) के लिये अंतर्राष्ट्रीय अनुरोध होता है।

USA और UK के बीच न्यू अटलांटिक चार्टर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने 80 साल पुराने अटलांटिक चार्टर के एक नए संस्करण पर हस्ताक्षर किए।
    - अटलांटिक चार्टर 14 अगस्त, 1941 को न्यूफ़ाउंडलैंड में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी. रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधान मंत्री विंस्टन चर्चिल द्वारा जारी एक संयुक्त घोषणा थी।

न्यू अटलांटिक चार्टर (2021)

- नया चार्टर लोकतंत्र और क्षेत्रीय अखंडता के वैश्विक संबंधों की एक भव्य दृष्टि की दिशा में एक प्रयास है।
- यह पश्चिमी सहयोगियों से चुनाव सहित दुष्प्रचार या अन्य घातक प्रभावों के माध्यम से हस्तक्षेप का विरोध करने का आह्वान करता है।
- यह प्रतिज्ञा करता है कि जब तक परमाणु हथियार हैं तब तक उत्तर अटलांटिक संधि संगठन (North Atlantic Treaty Organisation- NATO) एक परमाणु गठबंधन बना रहेगा।

यूरोपीय संघ ने श्रीलंका को दिए गए अपने GSP+दर्जे पर विचार करने का आग्रह किया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में -

- हाल ही में, यूरोपीय संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसमें यूरोपीय संघ (EU) आयोग से श्रीलंका को दी गई वरीयता प्लस (GSP+) की सामान्यीकृत योजना को अस्थायी रूप से वापस लेने पर विचार करने का आग्रह किया गया।

- यूरोपीय संघ के GSP को व्यापक रूप से कवरेज और लाभों के मामले में सबसे प्रगतिशील माना जाता है।
- यूरोपीय संघ लगातार GSP+ लाभार्थी देशों के मानवाधिकारों, श्रम अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों के प्रभावी कार्यान्वयन की निगरानी और समीक्षा करता है।
- GSP को 1968 में नई दिल्ली में अंकटाड में अपनाया गया था और 1971 में स्थापित किया गया था
    - व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन 1964 में एक स्थायी अंतर सरकारी निकाय के रूप में स्थापित किया गया।
    - अंकटाड संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है जो व्यापार, निवेश और विकास के मुद्दों से निपटता है।

वरीयता की सामान्यीकृत प्रणाली (GSP)

- सामान्यीकृत वरीयता प्रणाली (GSP) एक अम्ब्रेला अवधारणा है, जिसमें औद्योगिक देशों द्वारा विकासशील देशों को दी जाने वाली अधिमान्य योजनाओं का बड़ा हिस्सा शामिल है।
- इसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन (MFN) के रूप में कम टैरिफ या लाभार्थी देशों द्वारा दाता देशों के बाज़ारों में निर्यात योग्य उत्पादों की शुल्क-मुक्त प्रविष्टि आदि शामिल है।

FAO सम्मेलन का 42वां सत्र

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री ने खाद्य और कृषि संगठन (FAO) के सम्मेलन के 42वें सत्र को संबोधित किया।
- यह सम्मेलन हर दो वर्ष में होता है यह FAO का सर्वोच्च शासी निकाय है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से FAO इंडिया द्वारा तैयार किए गए देश कार्यक्रम की रूपरेखा में बहु-क्षेत्रीय दृष्टिकोण है।
- भारत मुख्य रूप से फॉल आर्मी वर्म और डेजर्ट टिड्डी के सीमा पार कीटों की घटनाओं में तकनीकी विशेषज्ञता और सहायता प्रदान करता रहा है।
- FAO अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष जो वर्ष 2016 में मनाया गया था और वर्ष 2023 को बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित करने के लिये भारतीय प्रस्ताव का समर्थन करता है।
- जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों के प्रति कृषि को लचीला बनाने के लिये तकनीकों का विकास, प्रदर्शन और प्रसार करने हेतु सतत् कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (NMSA) प्रारंभ किया गया।
- भारत बड़े पैमाने पर जैविक खेती को बढ़ावा दे रहा है।

भारत द्वारा COVID-19 के दौरान पहल

- भारतीय कृषि क्षेत्र ने कोविड-19 के दौरान 305 मिलियन टन खाद्यान्न का सर्वकालिक उच्च उत्पादन दर्ज किया।
- **किसान रेल:** इसे जल्दी खराब होने वाली बागवानी उपज, दूध और डेयरी उत्पाद सहित आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन केंद्रों से बड़े शहरी बाज़ारों तक परिवहन के लिये पेश किया गया था।
- **प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज:** इस योजना के तहत 810 मिलियन लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न प्रदान किया गया और इसे आगे भी जारी रखा गया है जिसमें श्रमिकों को नवंबर, 2021 तक लाभान्वित किया जाएगा।

- **पीएम किसान योजना:** किसानों को आय सहायता प्रदान करने के लिये इसके तहत 10 करोड़ से अधिक किसानों के बैंक खातों में 1,37,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि भेजी गई है।

अदन की खाड़ी में पहला भारतीय नौसेना-यूरोपीय संघ नौसैनिक बल (EUNAVFOR) अभ्यास

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- समुद्री डकैती रोधी अभियानों के लिए तैनात भारतीय नौसेना का जहाज त्रिकंद से अदन की खाड़ी में भारतीय नौसेना और यूरोपीय संघ नौसैनिक बल के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास के लिए पहली बार भाग ले रहा है।
- **समन्वयक:** यूरोपीय संघ नौसेना बल (EU NAVFOR)
    - भारतीय नौसेना के साथ-साथ अन्य नौसैनिक बल इटली, स्पेन और फ्रांस से हैं।
- नौसैनिक अभ्यास में उन्नत वायु रक्षा और पनडुब्बी रोधी अभ्यास, सामरिक युद्धाभ्यास, खोज और बचाव और अन्य समुद्री सुरक्षा अभियान शामिल थे।
- यूरोपीय संघ नौसेना बल और भारतीय नौसेना विश्व खाद्य कार्यक्रम (UN WFP) के चार्टर के तहत काउंटर पायरेसी ऑपरेशन और तैनात जहाजों की सुरक्षा सहित कई मुद्दों पर जुटे हैं।
- दोनों नौसेनाओं के बीच बहरीन में प्रतिवर्ष आयोजित होने वाली SHADE (साझा जागरूकता और विघटन) बैठकों के माध्यम से नियमित रूप से बातचीत होती है।

अदन की खाड़ी के बारे में

- अदन की खाड़ी को बरबेरा की खाड़ी के रूप में भी जाना जाता है।
- यह उत्तर में यमन, पूर्व में अरब सागर, पश्चिम में जिबूती और दक्षिण में गार्डाफुई चैनल, सोकोट्रा (यमन) और सोमालिया के बीच एक गहरे पानी की खाड़ी है। (मानचित्र देखें)
- जलमार्ग हिंद महासागर में भूमध्य सागर और अरब सागर के बीच महत्वपूर्ण स्वेज नहर शिपिंग मार्ग का हिस्सा है।

यूएस-रूस : बाइडेन-पुतिन मुलाकात

संदर्भ: मार्च 2021 में, व्हाइट हाउस संभालने के बाद, श्री बिडेन ने श्री पुतिन को "हत्यारा" बताया और अमेरिकी चुनावों में रूस के हस्तक्षेप की आलोचना की। तीन महीने बाद, बिडेन ने पुतिन से मुलाकात की और "दो महान शक्तियों" के बीच अधिक अनुमानित संबंध की मांग की।

पश्चिम और चीन

- **चीन पर ध्यान केंद्रित किया गया:** पहले नाटो का मुख्य फोकस रूस था अब चीन है। नाटो के सदस्यों ने चीन के उदय से उत्पन्न "नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए प्रणालीगत चुनौतियों" के खिलाफ चेतावनी दी।
- **चीन के मानव संसाधन रिकॉर्ड की आलोचना:** G-7 औद्योगिक देशों ने हाल ही में चीन के मानवाधिकार रिकॉर्ड की निंदा करते हुए एक विज्ञप्ति जारी की। शिनजियांग में उइगरों को हिरासत में लेने, हांगकांग में असंतोष पर कार्रवाई, ताइवान के साथ बढ़ते तनाव जैसे मुद्दों पर प्रकाश डाला गया।
- **बेहतर प्रतिस्पर्धा के लिए सहयोग:** अमेरिका और यूरोपीय संघ ने एक उच्च स्तरीय व्यापार और प्रौद्योगिकी परिषद स्थापित करने का फैसला किया है, जो चीन के साथ बेहतर प्रतिस्पर्धा करने के लिए नवाचार और निवेश को बढ़ावा देगा।

निष्कर्ष

- रूस-यू.एस. रिश्ते में कोई सार्थक परिवर्तन देखना जल्दबाजी होगी। लेकिन जिनेवा शिखर सम्मेलन से पता चलता है कि वाशिंगटन में नीति निर्माताओं ने कम से कम रूस को एक माध्यमिक चुनौती के रूप में सोचना शुरू कर दिया है, जिसे न केवल जबरदस्ती के माध्यम से कूटनीतिक रूप से निपटने की जरूरत है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- क्वाड
- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल
- शंघाई सहयोग संगठन (SCO)
- चीन से निपटने के लिए सार्क को पुनर्जीवित करना

अंटार्कटिक संधि (Antarctic Treaty) की 60 वीं वर्षगांठ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में, अंटार्कटिक संधि की 60वीं वर्षगांठ मनाई है।
- यह एक एकल संधि का एकमात्र उदाहरण है जो पूरे महाद्वीप को नियंत्रित करती है।
    - यह एक स्थायी आबादी वाले महाद्वीप के लिए नियम-आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की नींव भी है।
    - अंटार्कटिका को 60° दक्षिण अक्षांश के दक्षिण में स्थित बर्फ से आच्छादित भूमि के रूप में परिभाषित किया गया है।

अंटार्कटिक संधि के बारे में

- अंटार्कटिक महाद्वीप को केवल वैज्ञानिक अनुसंधान के लिये संरक्षित करने एवं असैन्यीकृत क्षेत्र बनाने के लिये 1 दिसंबर, 1959 को वाशिंगटन में 12 देशों के बीच अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किये गए थे।
- **12 मूल हस्ताक्षरकर्त्ता :** अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, चिली, फ्राँस, जापान, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, यूके और यूएस हैं।
    - भारत 1983 में इस संधि का सदस्य बना।
- **मुख्यालय:** ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना।
- **प्रमुख प्रावधान:**
    - वैज्ञानिक अनुसंधान की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना।
    - देश महाद्वीप का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए कर सकते हैं।
    - सैन्य गतिविधियों, परमाणु परीक्षणों और रेडियोधर्मी कचरे के निपटान पर रोक।
    - प्रादेशिक संप्रभुता को निष्प्रभावी करते हुए, इसका अर्थ है कि कोई नया दावा करने या मौजूदा दावे के विस्तार पर एक सीमा रखी गई थी।
    - इसने महाद्वीप पर दावेदारों के बीच उनके क्षेत्रों पर किसी भी विवाद पर रोक लगा दी।

भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम के बारे में

- यह नेशनल सेंटर फॉर अंटार्कटिक एंड ओशन रिसर्च (NCPOR) के तहत एक वैज्ञानिक अनुसंधान और अन्वेषण कार्यक्रम है।
- इसकी शुरुआत 1981 में हुई थी जब अंटार्कटिका के लिए पहला भारतीय अभियान बनाया गया था।

- **दक्षिण गंगोत्री:** अंटार्कटिका में स्थापित पहला भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान बेस स्टेशन
- **मैत्री:** अंटार्कटिका में भारत का दूसरा स्थायी अनुसंधान केंद्र। यह शिरमाकर ओएसिस नामक चट्टानी पहाड़ी क्षेत्र पर स्थित है। भारत ने मैत्री के आसपास मीठे पानी की एक झील भी बनाई जिसे प्रियदर्शिनी झील के नाम से जाना जाता है।
- **भारती:** 2012 से भारत का नवीनतम अनुसंधान केंद्र संचालन रहा है। यह भारत की पहली प्रतिबद्ध अनुसंधान सुविधा है।
- **सागर निधि:** 2008 में, भारत ने शोध के लिए सागर निधि की स्थापना की। एक आइस-क्लास पोत, अंटार्कटिक जल को नेविगेट करने वाला पहला भारतीय पोत, यह 40 सेमी गहराई की पतली बर्फ को काट सकता है।

G-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री ने कहा है कि भारत श्रम बल की भागीदारी में लैंगिक अंतराल को कम करने के लिये सामूहिक प्रयास कर रहा है।
- वह G-20 श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक में घोषणा और रोज़गार कार्य समूह की प्राथमिकताओं पर बैठक को संबोधित कर रहे थे।
- रोजगार कार्य समूह ने महिला रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और दूरस्थ कार्य सहित प्रमुख मुद्दों पर विचार-विमर्श किया।

भारत द्वारा हाइलाइट की गई पहल

- **शैक्षिक और कौशल प्रयास (Educational and Skilling Efforts)**
    - राष्ट्रीय शैक्षिक नीति, 2020 के माध्यम से भारत, पूर्वस्कूली से वरिष्ठ माध्यमिक स्तर तक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपने शैक्षिक और कौशल प्रयासों को मजबूत कर रहा है। इसका उद्देश्य स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणालियों में सुधार करना है।
- **राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन:** इसका उद्देश्य कौशल प्रशिक्षण गतिविधियों के संदर्भ में सभी क्षेत्रों और राज्यों को केंद्रबिंदु बनाना है।
- **प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना:** युवाओं को बेहतर अवसर हासिल करने में मदद करने के लिए उद्योग से संबंधित कौशल प्रशिक्षण लेने में सक्षम बनाती है।
- **नई श्रम संहिता 2019 :** यह वेतन, भर्ती और रोजगार की शर्तों में लिंग आधारित भेदभाव को कम करेगा।
- **प्रधानमंत्री मुद्रा योजना:** यह महिला उद्यमियों को लघु उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इस योजना में लगभग 70% महिलाएं हैं।

ब्रिस्बेन लक्ष्य की ओर तथा उससे आगे G20 रोडमैप

- महिलाओं के रोजगार की मात्रा और गुणवत्ता में वृद्धि करना।
- समान अवसर सुनिश्चित करना और श्रम बाजार में बेहतर परिणाम प्राप्त करना।
- महिलाओं तथा पुरुषों के बीच भुगतान और अवैतनिक काम के अधिक संतुलित वितरण को प्रोत्साहित करना।
- श्रम बाजार में भेदभाव और लैंगिक रुढ़िबद्धता का समाधान करना।

अभ्यास 'सी ब्रीज 2021'

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- रूस और यूक्रेन के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच यूक्रेन के साथ पश्चिमी सहयोग का प्रदर्शन करते हुए यूक्रेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका ने काला सागर में संयुक्त नौसैनिक अभ्यास 'सी ब्रीज' (Sea Breeze) की शुरुआत की है।
- अभ्यास सी ब्रीज का आयोजन वर्ष 1997 से किया जा रहा है, जिसमें नाटो राज्य तथा काला सागर क्षेत्र में स्थित नाटो सहयोगी देश शामिल होते हैं।
    - यह संस्करण (वर्ष 2021) अभी तक आयोजित अभ्यासों के इतिहास में सबसे बड़ा होगा जिसमें 30 से अधिक देशों के लगभग 5,000 सैन्यकर्मी शामिल होंगे।

अभ्यास का उद्देश्य

- नौसेना और भूमि संचालन में सुधार
- सहभागी देशों के बीच सहयोग में सुधार करना
- क्षेत्र में स्थिरता और शांति बनाए रखने के लिए एक शक्तिशाली संदेश भेजना।

रूस के लिए काला सागर का महत्व

- काला सागर क्षेत्र का अद्वितीय भूगोल रूस को कई भू-राजनीतिक लाभ प्रदान करती है।
    - रूस हमेशा से इस क्षेत्र को नियंत्रित करना चाहता है।
- यह पूरे क्षेत्र के लिये एक महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक चौराहे के रूप में कार्य करता है।
- इसकी पहुंच कई निकटवर्ती क्षेत्रों में शक्ति के प्रक्षेपण को काफी बढ़ा देती है।
- यह क्षेत्र माल और ऊर्जा परिवहन के लिये एक महत्त्वपूर्ण पारगमन गलियारे के रूप में कार्य करता है।
- यह सांस्कृतिक और जातीय विविधता में समृद्ध है, और रूस के साथ घनिष्ठ ऐतिहासिक संबंध साझा करता है।

ब्रिक्स : शक्तिशाली पांच का एक साथ आना

ब्रिक्स की उत्पत्ति

- ब्रिक्स का आविष्कार इसके किसी भी सदस्य द्वारा नहीं किया गया था। 2001 में, गोल्डमैन सैक्स के जिम ओ'नील ने "बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक ब्रिक्स" नामक एक पेपर लिखा, जिसमें कहा गया था कि दुनिया में भविष्य की जीडीपी वृद्धि चीन, भारत, रूस और ब्राजील से आएगी।
- महत्वपूर्ण बात यह है कि अखबार ने उनके लिए अलग समूह बनाने की सिफारिश नहीं की, लेकिन यह मामला बनाया कि G-7 समूह में शामिल किया जाना चाहिए।
- सदस्यों के लिए साझा आधार यह सुनिश्चित करके बनाया गया था कि फोरम में कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया गया था।

ब्रिक्स के मुद्दे

- **फोकस की कमी:** 2006 में गठित होने के बावजूद, समूह अभी भी सभी को भ्रमित करता है और फोकस का अभाव है।
- **बहुत कम समानताएं :** उभरती अर्थव्यवस्थाओं के एक वैकल्पिक समूह के रूप में शुरू किया गया जो युद्ध के बाद की विश्व व्यवस्था को चुनौती दे सकता है, इसकी आलोचना चार महाद्वीपों में अलग-अलग देशों के रैग-टैग बैंड के रूप में की गई है, जिनमें बहुत कम समानताएं हैं।
- **रूस-चीन धुरी:** रूस और चीन जैसे देशों के बीच संबंध समूह की अपनी एकजुटता की तुलना में बहुत मजबूत गति से बढ़ रहे हैं
- **निम्न कारणों से समूह के लिए दीर्घकालिक निवेशक भावना मंद है:**
    - 2017 में ट्रिलियन-डॉलर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू करने के चीन के फैसले का भारत ने विरोध किया था, और यहां तक कि रूस भी इसमें शामिल नहीं हुआ था।
    - दक्षिण अफ्रीका की कर्ज से लदी अर्थव्यवस्था और नकारात्मक चालू खाते ने कुछ लोगों को अगले दशक में आर्थिक पतन की भविष्यवाणी करने के लिए प्रेरित किया है।
    - कोविड-19 संकट के दौरान ब्राजील के खराब संचालन ने इसे दुनिया के सबसे अधिक प्रभावित देशों में स्थान दिया है और इसके ठीक होने में देरी होने की उम्मीद है।
    - भारत की आर्थिक मंदी कोविड -19 हिट से पहले ही एक चिंता का विषय थी और "आत्मनिर्भर" जैसी सरकारी नीतियों को अंदर की ओर मुड़ने की योजना के रूप में देखा गया था।
    - दक्षिण चीन सागर, भारत के साथ सीमा और आंतरिक रूप से हांगकांग और झिंजियांग में चीन की ओर से आक्रमण को लेकर चिंताएं हैं।

ब्रिक्स की उपलब्धियां

- **नियमित शिखर सम्मेलन:** सभी विरोधाभासों और आलोचनाओं के बावजूद, ब्रिक्स एक ऐसा विचार है जो दो दशकों तक टिका हुआ है, यह एक ऐसा विचार जिसके लिए इसके सदस्य प्रतिबद्ध हैं, और कोई भी 2009 से आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं हुआ है।
- **विश्व बैंक का विकल्प:** ब्रिक्स ने 100 अरब डॉलर की प्रारंभिक पूंजी के साथ स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) का निर्माण किया है।
- वैश्विक तरलता संकट से निपटने के लिए ब्रिक्स आकस्मिक रिजर्व व्यवस्था निधि।

- एक ब्रिक्स भुगतान प्रणाली जो स्विफ्ट भुगतान प्रणाली के विकल्प के रूप में प्रस्तावित है।
- **भू-राजनीतिक घटनाओं पर खड़े हों:** जबकि इसकी नींव आर्थिक थी, ब्रिक्स के बयान हमेशा गहरे राजनीतिक रहे हैं, जिसमें बहुपक्षीय विश्व व्यवस्था में अधिक समावेश का आह्वान किया गया है, यूएस-यूरोप समर्थित सैन्य हस्तक्षेपों की निंदा की गई है, और अफगानिस्तान से पश्चिम एशिया तक कई विश्व घटनाओं पर एक स्वतंत्र रेखा व्यक्त की गई है।
- ब्रिक्स देश एक "ब्रिक्स वैक्सीन सेंटर" पर आगे बढ़ते हैं, जो जोहान्सबर्ग में स्थित होने का प्रस्ताव है, यह देखते हुए कि कम से कम तीन सदस्यों - रूस, भारत और चीन ने विश्व स्तर पर अधिकृत सभी टीकों का एक बड़ा हिस्सा निर्मित किया है।
- ब्रिक्स ने संयुक्त राष्ट्र और UNSC, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन सहित बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार के लिए बार-बार आह्वान किया है।
- ब्रिक्स ने कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए टीकों और दवाओं के लिए व्यापार संबंधी बौद्धिक संपदा अधिकारों (TRIPs) की छूट के लिए विश्व व्यापार संगठन में बातचीत का समर्थन किया।

निष्कर्ष

यह अभी भी संभव है कि अगली पीढ़ी के भीतर ब्रिक समूह G-7 जितना बड़ा हो जाए। यदि ब्रिक देशों और शेष विश्व के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और वित्तीय प्रवाह जारी रहता है, तो विकास का यह स्तर सभी के लिए अच्छा होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की झलक
- शंघाई सहयोग संगठन
- सार्क और बिम्सटेक का भविष्य
- विश्व में बढ़ते ध्रुवीकरण के दौर में भारत की गुटनिरपेक्ष नीति

G-7 और भारत

संदर्भ: यूके के प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन के निमंत्रण पर, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 12 जून और 13 जून को G-7 शिखर सम्मेलन के संपर्क (आउटरीच) सत्रों में डिजिटल माध्यम से भाग लेंगे।

इस बार ब्रिटेन 47वें G-7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है और उसने भारत के अलावा सम्मेलन में शामिल होने के लिए अतिथि देशों के तौर पर ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया और दक्षिण अफ्रीका को भी आमंत्रित किया है।

G-7 के बारे में

- G-7 में यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान शामिल हैं।
- यह एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका गठन 1975 में किया गया।
- वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए ब्लॉक की सालाना बैठक होती है।
- G-7 का कोई औपचारिक संविधान या कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है। वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं द्वारा लिए गए निर्णय गैर-बाध्यकारी होते हैं।
- 1997 में रूस द्वारा मूल सात के शामिल होने के बाद कई वर्षों तक G-7 को 'G-8' के रूप में जाना जाता था। यूक्रेन के क्रीमिया क्षेत्र के बाद के विलय के बाद 2014 में रूस को एक सदस्य के रूप में निष्कासित किए जाने के बाद समूह को G-7 कहा जाने लगा।

इस साल G-7 के एजेंडे में क्या है?

शिखर सम्मेलन का विषय 'बिल्ड बैक बेटर' है और यूके ने अपनी अध्यक्षता के लिए चार प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की रूपरेखा तैयार की है। ये है :

- भविष्य की महामारियों के खिलाफ लचीलेपन को मजबूत करते हुए कोरोनावायरस से वैश्विक सुधार का नेतृत्व करना;
- स्वतंत्र और निष्पक्ष व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देना;
- जलवायु परिवर्तन से निपटना और ग्रह की जैव विविधता का संरक्षण करना;
- साझा मूल्यों और खुले समाजों को चैंपियन बनाना।

क्या भारत पहली बार इसमें भाग ले रहा है?

- 2014 के बाद से, यह दूसरी बार है जब पीएम मोदी G-7 बैठक में भाग लेंगे।
- प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह के यूपीए शासन के दौरान, भारत ने G-8 में पांच बार भाग लिया।
- 2020 में, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका ने भारत को निमंत्रण दिया था।
- G-7 को "बहुत पुराना समूह" बताते हुए ट्रम्प ने सुझाव दिया था कि भारत, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया और रूस को शामिल करके 7 के समूह को "G-10 या G-11" कहा जाए। हालाँकि, महामारी और अमेरिकी चुनावों के परिणाम के कारण ऐसा नहीं हुआ।

इस G-7 शिखर सम्मेलन में क्या देखना है?

- **ट्रम्प की अमेरिका प्रथम नीति से ब्रेक:** यह अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली यूरोप यात्रा होगी, जहां वह अपने मुख्य संदेश "अमेरिका वापस आ गया है" का संकेत देंगे। यह ट्रम्प की अमेरिकी प्रथम नीति से एक बदलाव होगा जहां अमेरिका वैश्विक नेतृत्व की भूमिकाओं से हट गया था।
- **रूस के साथ अमेरिका का पुनर्रेखण:** G-7 शिखर सम्मेलन में सहयोगियों से मिलने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन 14 जून को ब्रसेल्स में नाटो सम्मेलन में शामिल होंगे, बाद में जेनेवा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ उनकी बातचीत से पहले।
- **चीन में सामरिक प्रतिद्वंदी:** मुख्य तत्व जो वाशिंगटन को अपने द्विपक्षीय संबंधों में नुकसान को रोकने के लिए मास्को के साथ जुड़ने का महत्वपूर्ण कदम उठा रहा है, वह यह है कि अमेरिका अपने रणनीतिक प्रतिद्वंद्वी चीन पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है।
- **बहुपक्षवाद को पुनर्जीवित करना:** यह अमेरिकी राष्ट्रपति के बहुपक्षवाद में प्रारंभिक प्रयास के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है - उन्होंने "क्वाड" के नेताओं का पहला शिखर सम्मेलन आयोजित किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका है। इसे ट्रंप के द्विपक्षीय तरीके से व्यवहार करने की शैली के विपरीत माना जाता है।
- **कोविड के बाद आर्थिक सुधार:** सात का समूह "इस महामारी को जल्द से जल्द खत्म करने में मदद करने के लिए एक व्यापक योजना" पर एक और संयुक्त घोषणा कर सकता है।
- **वैश्विक टीकाकरण:** बिडेन, G-7 शिखर सम्मेलन से पहले विश्व को कोविड-19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए एक बड़ी नई पहल की घोषणा करेंगे। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बाइडेन प्रशासन अंतरराष्ट्रीय वितरण के लिए फाइजर/बायोएनटेक वैक्सीन की 500 मिलियन खुराक खरीदने के लिए तैयार है। यह खुराक विकासशील देशों के उद्देश्य से होगी।

इसमें भारत के लिए क्या है?

- **चीन से निबटना:** चीन के प्रबल होने के साथ, अमेरिका सभी समान विचारधारा वाले देशों को बीजिंग से निपटने में भागीदार बनाने का आह्वान कर रहा है। अगर अमेरिका और ब्रिटेन छलांग लगाना चाहते हैं और 10-11 देशों का वैश्विक लोकतांत्रिक गठबंधन बनाना चाहते हैं, तो यह एक महत्वपूर्ण संकेत होगा।

- **वैक्सीन की कमी:** चूंकि भारत टीकों की भारी कमी का सामना कर रहा है, दिल्ली अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित आवंटन को बहुत ध्यान से देख रहा होगा। हाल ही में, अमेरिका ने कहा था कि वह "वैश्विक वैक्सीन साझा करने की रणनीति" के तहत भारत को टीके वितरित करेगा।
- **रूस:** मॉस्को के साथ वाशिंगटन के मेल-मिलाप पर, नई दिल्ली को बहुत राहत मिलेगी क्योंकि अमेरिका तब चीन पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। यह तनाव को दूर करेगा जो रूस के साथ अमेरिकी प्रतिद्वंदीदता के कारण भारत-रूस संबंधों में बने हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत और G-11 महत्वपूर्ण विश्लेषण
- G-20
- OECD
- FATF

गलवान के एक साल बाद भारत-चीन संबंध

संदर्भ: रक्षा मंत्री ने 12 जून को एक संशोधित नीति को मंजूरी दी कि कैसे भारत अपने युद्ध दस्तावेजों और संबंधित इतिहास को संकलित, संग्रहीत और प्रसारित करता है।

नई नीति के अनुसार

- एक बार एक ऑपरेशन/युद्ध पूरा हो जाने के बाद, इतिहास का पहला कट तैयार किया जाता है और पांच साल के भीतर आंतरिक संचलन के लिए प्रसारित किया जाता है।
- इतिहास का यह पहला मसौदा सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना है या नहीं, ऑपरेशन/युद्ध की संवेदनशीलता के आधार पर मामला दर मामला आधार पर निर्धारित किया जाएगा।
- अनुमानतः, चीन के साथ 1962 के युद्ध से संबंधित हेंडरसन ब्रूक्स-भगत रिपोर्ट, जो अभी भी गुप्त है, नई नीति का हिस्सा नहीं होगी। जाहिर है, एक और समिति पिछले युद्धों पर विचार करेगी।

गलवान घटना के एक साल बाद

- राष्ट्रीय संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा करने वाली सेना के बारे में सावधानीपूर्वक आकार के आख्यान किसी भी राजनीतिक नेतृत्व के लिए महत्वपूर्ण हैं - सत्तावादी या लोकतांत्रिक और गालवान में चीन और भारत दोनों के लिए विशेष महत्व है।
- भारत ने गलवान को चीनी आक्रामकता के मामले के रूप में व्याख्यायित किया है और यथास्थिति बहाल करने की जिम्मेदारी बीजिंग पर डाल दी है।
- चीन में इस घटना को सीमा और मातृभूमि की रक्षा के मामले के रूप में पेश किया जा रहा है। इस घटना का इस्तेमाल घरेलू स्तर पर सैन्य और बाहुबली राष्ट्रवाद पर गर्व करने के लिए किया गया।
- गलवान के बारे में भारत की कहानी अनिश्चित बनी हुई है और लद्दाख में मौजूदा सामरिक स्थिति पर रक्षा मंत्रालय की ओर से कोई विस्तृत आधिकारिक बयान नहीं दिया गया है।

आगे की राह

- गलवान वर्षगाँठ से सरकार को विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र पैनल गठित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि उन संस्थागत कमियों की समीक्षा की जा सके जिनके कारण लद्दाख सेक्टर में नियंत्रण रेखा में बदलाव आया।
- साथ-साथ, दिल्ली को निष्पक्ष समीक्षा करनी होगी और अनुमान लगाना होगा कि PLA आगे क्या शुरू कर सकता है।

- इस घटना से सरकार को वहनीय और प्रभावी दीर्घकालिक रणनीतिक/सुरक्षा नीतियों को तैयार करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जो राजनीतिक मजबूरियों से घिरी नहीं हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत-चीन सीमा भड़कना
- 2020 में गलवान घाटी संघर्ष
- गलवान घाटी पर अमेरिकी रिपोर्ट
- गलवान घाटी: एक त्रासदी की पोस्टस्क्रिप्ट
- चीन की बेल्ट एंड रोड पहल

भारत ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन डॉलर का ऋण दिया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II - जीएस-II -अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- हाल ही में, भारत ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए श्रीलंका को 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की लाइन ऑफ क्रेडिट (LOC) प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
    - LOC 1.75% ब्याज के साथ 20 वर्षों की अवधि के लिए है।
    - इस पर श्रीलंका सरकार और भारतीय निर्यात-आयात (EXIM) बैंक के बीच हस्ताक्षर किए गए।
    - एक्जिम बैंक एक विशिष्ट वित्तीय संस्थान है, जिसका पूर्ण स्वामित्व भारत सरकार के पास है।
- LOC श्रीलंका के सौर ऊर्जा क्षेत्र में विभिन्न परियोजनाओं के वित्तपोषण में मदद करेगा

वैश्विक सहयोग के लिए भारत की पहल सौर ऊर्जा

- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA)**
    - 2015 में भारतीय प्रधान मंत्री और फ्रांसीसी राष्ट्रपति द्वारा शुरू किया गया।
    - ISA का विजन: वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड (OSOWOG) को सक्षम बनाना।
- **वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड (OSOWOG)**
    - **केन्द्रित करना:** वैश्विक सहयोग को सुगम बनाने के लिए एक ढांचा, परस्पर जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों (मुख्य रूप से सौर ऊर्जा) के एक वैश्विक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण जिसे आसानी से साझा किया जा सके।

भारत में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं

- हाल ही में, भारत ने इटली को पछाड़कर सौर ऊर्जा परिनियोजन में 5वां वैश्विक स्थान हासिल किया है।
- राष्ट्रीय सौर मिशन का उद्देश्य पूरे देश में इसके परिनियोजन के लिए नीतिगत शर्तें बनाकर भारत को सौर ऊर्जा में एक वैश्विक नेता के रूप में स्थापित करना है।
- **रूफटॉप सोलर योजना:** घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाकर सौर ऊर्जा उत्पन्न करना।
- भारत में उच्च दक्षता वाले सौर PV मॉड्यूल के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन (PLI) योजना।

अर्थव्यवस्था

भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) संकुचन 7.3%

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 2020-21 में 7.3% की कमी आई है।
- COVID-19 महामारी से पहले 2019-20 में GDP वृद्धि 4% थी।

महत्वपूर्ण तथ्य

- अर्थव्यवस्था में सकल मूल्य वर्धित (GVA) भी 2020-21 में 6.2% घट गई, जबकि पिछले वर्ष में यह 4.1% की वृद्धि थी।
- **सबसे तेज गिरावट:** व्यापार, होटल, परिवहन, संचार और प्रसारण से संबंधित सेवाएं (-18.2%), इसके बाद निर्माण (-8.6%), खनन और उत्खनन (-8.5%) और विनिर्माण (-7.2%) का स्थान आता है।

अन्य संबंधित तथ्य

- सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एक विशिष्ट समय अवधि में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य का एक मौद्रिक उपाय है।
- अर्थशास्त्र में, सकल मूल्य वर्धित (GVA) एक अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, उद्योग या क्षेत्र में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का माप है।

विश्व दुग्ध दिवस मनाया गया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- विश्व दुग्ध दिवस के अवसर पर आयोजित एक वर्चुअल कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री ने की।
- प्रतिवर्ष 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- इस अवसर पर, गोपाल रत्न पुरस्कारों के शुभारंभ की घोषणा की गई।
- ई-गोपाला ऐप को उमंग प्लेटफॉर्म के साथ एकीकृत किया जाएगा और उमंग प्लेटफॉर्म के उपयोगकर्ताओं को ऐप तक पहुंच प्राप्त होगी।
- ई-गोपाला (उत्पादक पशुधन के माध्यम से धन का सृजन) एप: यह किसानों के प्रत्यक्ष उपयोग के लिये एक समग्र नस्ल सुधार, बाज़ार और सूचना पोर्टल है।

अन्य संबंधित तथ्य

भारत में दूध क्षेत्र

- वर्तमान में भारत विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक है और वैश्विक दुग्ध उत्पादन का पांचवां हिस्सा है।
- **अन्य प्रमुख उत्पादक:** यूएसए, चीन, पाकिस्तान और ब्राजील।

- दूध के उत्पादन का मूल्य एक साथ गेहूं और धान के उत्पादन के मूल्य से अधिक है

'सतत' पहल को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए शुरू की गई

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने एक वर्चुअल समारोह में सतत (SATAT) पहल को प्रमुख प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए कई पहल शुरू कीं।

अन्य संबंधित तथ्य

- **SATAT योजना का उद्देश्य:** इस पहल के तहत उद्यमियों से संपीड़ित जैव-गैस (Compressed Bio-Gas-CBG) उत्पादन संयंत्र स्थापित करने और स्वचालित ईंधन (Automotive Fuel) में CBG के उपयोग हेतु बाज़ार में इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है।
- 'सतत' का लक्ष्य 2023 तक 5000 संयंत्रों से 15 एमएमटी सीबीजी के उत्पादन का लक्ष्य है।
- इस महत्त्वपूर्ण पहल में अधिक किफायती परिवहन ईंधन, कृषि अवशेषों, मवेशियों का गोबर और नगरपालिका के ठोस अपशिष्ट के बेहतर उपयोग के साथ-साथ किसानों को अतिरिक्त राजस्व स्रोत प्रदान करने की क्षमता है।
- यह 1.75 लाख करोड़ का निवेश, किसानों को एक अतिरिक्त राजस्व स्रोत और 75,000 प्रत्यक्ष रोजगार के अवसर और लाखों अप्रत्यक्ष रोजगार भी प्रदान करेगा।

SDO घोषित होने वाला पहला संस्थान बना RDSO

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- भारतीय रेलवे का आरडीएसओ (रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गनाइजेशन) बीआईएस (भारतीय मानक ब्यूरो) के "वन नेशन वन स्टैंडर्ड" मिशन के तहत मानक विकास संगठन (एसडीओ) घोषित होने वाला पहला संस्थान बन गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), जो राष्ट्रीय मानक निकाय है, ने एक योजना शुरू की है जो भारत सरकार के "एक राष्ट्र एक मानक" दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए "एसडीओ की मान्यता" प्रदान करती है।
- **योजना का उद्देश्य:** भारत में विभिन्न संगठनों की मौजूदा क्षमताओं और समर्पित डोमेन विशिष्ट विशेषज्ञता को समेकित और एकीकृत करना जो अपने विशिष्ट क्षेत्रों में मानकों के विकास में लगे हुए हैं।
- यह सभी मानक विकास गतिविधियों के अभिसरण को भी सक्षम करेगा जिसके परिणामस्वरूप "एक विषय के लिए एक राष्ट्रीय मानक" होगा।
- इसके लिए रेल मंत्रालय का लखनऊ स्थित एकमात्र अनुसंधान एवं विकास संगठन सक्रिय है। यह भारतीय रेल के लिए मानक तय करने का काम करता है और देश के प्रमुख मानक तय करने वाले संस्थानों में से एक है।

भारत की जीडीपी में गिरावट

संदर्भ: भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2020-21 में 7.3% कम हो गया। 1990 के दशक की शुरुआत से जब तक देश में महामारी नहीं आई, भारत में प्रतिवर्ष औसतन लगभग 7% की वृद्धि हुई।

जीडीपी में इस संकुचन को देखने के दो तरीके हैं।

- पहला तरीका इसे बाहरी रूप में देखना है - आखिरकार, भारत अधिकांश अन्य देशों की तरह, एक सदी में एक बार महामारी का सामना करता है।
- दूसरा तरीका यह होगा कि इस संकुचन को पिछले एक दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ क्या हो रहा है - और अधिक सटीक रूप से पिछले सात वर्षों के संदर्भ में देखा जाए।

शायद इस तरह के निष्कर्ष पर पहुंचने का सबसे अच्छा तरीका अर्थव्यवस्था के तथाकथित बुनियादी सिद्धांतों को देखना होगा।

सकल घरेलू उत्पाद	• वैश्विक वित्तीय संकट के मद्देनजर गिरावट के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था ने मार्च 2013 में अपनी वसूली शुरू की। • यह सुधार 2016-17 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर) के बाद से विकास की एक धर्मनिरपेक्ष मंदी में बदल गया। • देश में कोविड-19 के आने से ठीक पहले, जीडीपी विकास दर वित्त वर्ष 17 में 8% से गिरकर वित्त वर्ष 2020 में लगभग 4% हो गई। • 8 नवंबर, 2016 को विमुद्रीकरण को कई विशेषज्ञ ट्रिगर के रूप में देखते हैं जिसने भारत के विकास को नीचे की ओर धकेल दिया। • भारत का सकल घरेलू उत्पाद विकास पैटर्न कोविड-19 के अर्थव्यवस्था में आने से पहले ही एक "उल्टे V" जैसा दिखता था।
प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी को कुल जनसंख्या से विभाजित)	• जैसा कि चार्ट 3 (उपरोक्त) में लाल वक्र दिखाता है, 99,700 रुपये के स्तर पर, भारत की प्रति व्यक्ति जीडीपी अब 2016-17 में हुआ करती थी जिस वर्ष स्लाइड शुरू हुई थी। • परिणामस्वरूप, भारत अन्य देशों से हार रहा है। एक उदाहरण यह है कि कैसे प्रति व्यक्ति-जीडीपी के मामले में बांग्लादेश ने भी भारत को पीछे छोड़ दिया है।
बेरोजगारी दर	• यह वह मीट्रिक है जिस पर भारत ने संभवत: सबसे खराब प्रदर्शन किया है। • 2017-18 में बेरोजगारी 45 साल के उच्चतम स्तर पर थी। विमुद्रीकरण के बाद के वर्ष और जीएसटी की शुरूआत के बाद। • फिर 2019 में खबर आई कि 2012 और 2018 के बीच नौकरीपेशा लोगों की कुल संख्या में 9 मिलियन की गिरावट आई - स्वतंत्र भारत के इतिहास में कुल रोजगार में गिरावट का ऐसा पहला उदाहरण। • 2% -3% की बेरोज़गारी दर के मानदंड के विपरीत, भारत में कोविड-19 से पहले के वर्षों में नियमित रूप से 6% -7% के करीब बेरोज़गारी दर देखी जाने लगी। बेशक, महामारी ने मामलों को काफी बदतर बना दिया।
महंगाई का दर	• 2011 से 2014 तक 110 डॉलर प्रति बैरल के करीब रहने के बाद, 2015 में तेल की कीमतें (इंडिया बास्केट) तेजी से गिरकर केवल 85 डॉलर और 2017 और 2018 में 50 डॉलर से नीचे (या आसपास) हो गई। देश में उच्च खुदरा मुद्रास्फीति गिरावट ने सरकार को वश में करने की अनुमति दी। • लेकिन 2019 की अंतिम तिमाही से, भारत लगातार उच्च खुदरा मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। यहां तक कि 2020 में कोविड -19 द्वारा प्रेरित लॉकडाउन के कारण मांग में गिरावट भी मुद्रास्फीति की वृद्धि को नहीं समाप्त कर सकी • आने वाले समय में महंगाई भारत के लिए बड़ी चिंता का विषय है।

राजकोषीय घाटा	• कागज पर, भारत के राजकोषीय घाटे का स्तर निर्धारित मानदंडों से थोड़ा अधिक था, लेकिन वास्तव में, कोविड -19 से पहले भी। • चालू वित्त वर्ष के केंद्रीय बजट में, सरकार ने माना कि वह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 2% से राजकोषीय घाटे को कम कर रही है।
रुपया बनाम डॉलर	• 2014 में एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 59 रुपये थी। सात साल बाद, यह 73 रुपये के करीब है। • रुपये की सापेक्ष कमजोरी भारतीय मुद्रा की घटती क्रय शक्ति को दर्शाती है।

ग्रोथ को लेकर क्या है आउटलुक?

- भारत में विकास का सबसे बड़ा इंजन आम लोगों द्वारा अपनी निजी क्षमता में किया जाने वाला खर्च है। माल की यह "मांग" सभी सकल घरेलू उत्पाद का 55% है।
- चार्ट-3 में, नीला वक्र इस निजी उपभोग व्यय के प्रति व्यक्ति स्तर को दर्शाता है, जो 2016-17 में पिछली बार देखे गए स्तरों तक गिर गया है। इसका मतलब है कि अगर सरकार मदद नहीं करती है, तो भारत की जीडीपी आने वाले कई वर्षों तक पूर्व-कोविड प्रक्षेपवक्र में वापस नहीं आ सकती है।
- यही कारण है कि नवीनतम जीडीपी को अपवाद के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत को एक वित्तीय परिषद की आवश्यकता है।

भारतीय आर्थिक चुनौतियां

संदर्भ: NSO's के 2020-21 के अनंतिम अनुमानों के अनुसार, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में वार्षिक संकुचन 7.3 प्रतिशत हो गया, जो पहले के 8 प्रतिशत के अनुमान से सुधार था।

आर्थिक अनुमान

- 2021-22 में 7.8 प्रतिशत की वास्तविक जीडीपी वृद्धि की आवश्यकता होगी ताकि 2019-20 के वास्तविक जीडीपी स्तर पर वापस पहुंच सकें।
- यह अनुमान लगाया गया है कि उपयुक्त नीतिगत हस्तक्षेपों के साथ, 9 प्रतिशत वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि अभी भी संभव हो सकती है यदि लॉकडाउन जुलाई के अंत तक समाप्त हो जाता है।
- केंद्र के राजकोषीय समुच्चय के लिए लेखा महानियंत्रक के आंकड़े 2020-21 के लिए 20.2 लाख करोड़ रुपये के सकल कर राजस्व (GTR) और 14.2 लाख करोड़ रुपये के शुद्ध कर राजस्व का संकेत देते हैं।
- 2021-22 के लिए अनुमानित सकल और शुद्ध कर राजस्व का मतलब क्रमशः 22.7 लाख करोड़ रुपये और 15.8 लाख करोड़ रुपये होगा।
- हाल ही में केंद्र को आरबीआई द्वारा घोषित 0.99 लाख करोड़ रुपये के लाभांश को ध्यान में रखते हुए, मुख्य कमी गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्तियों में हो सकती है। कुल मिलाकर, गैर-ऋण प्राप्तियों में कुल कमी लगभग 0.9 लाख करोड़ रुपये या अनुमानित नाममात्र जीडीपी के 0.4 प्रतिशत तक सीमित हो सकती है।

किस खर्च को प्राथमिकता दी जानी चाहिए?

- दूसरी लहर के मद्देनजर आर्थिक चुनौतियों को देखते हुए, तीन व्यय शीर्षों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।

- पहला, कमजोर ग्रामीण और शहरी आबादी के लिए आय सहायता उपायों के प्रावधान में वृद्धि। इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता होगी जो आंशिक रूप से व्यय पुनर्गठन के माध्यम से प्रदान की जा सकती है।
- दूसरा, हाल के निर्णय में, 0.35 लाख करोड़ रुपये के टीकाकरण पर बजट व्यय को बढ़ाया जाना चाहिए इसे कम से कम दोगुना किया जाना चाहिए।
- तीसरा, चुनिंदा क्षेत्रों, विशेष रूप से स्वास्थ्य देखभाल के लिए अतिरिक्त पूंजीगत व्यय के लिए भी प्रावधान किया जाना चाहिए। यह 1 लाख करोड़ रुपये हो सकता है।
- ये अतिरिक्त व्यय कुल मिलाकर 1.7 लाख करोड़ रुपये होंगे, जो अनुमानित नाममात्र सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 0.8 प्रतिशत है।

इन सबका राजकोषीय घाटे पर क्या असर होगा?

- इस प्रकार, हमें सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 7.9 प्रतिशत के राजकोषीय घाटे की योजना बनाने की आवश्यकता है जिसमें शामिल हैं
  (a) 6.7 प्रतिशत का बजटीय राजकोषीय घाटा
  (b) कुल गैर-ऋण प्राप्तियों में कमी के लिए 0.4 प्रतिशत और
  (c) अतिरिक्त प्रोत्साहन उपायों के लिए 0.8 प्रतिशत।
- उच्च राजकोषीय घाटे को देखते हुए, उसे अपने उधार कार्यक्रम में और 2.6 लाख करोड़ रुपये जोड़ने होंगे, जिससे GST मुआवजे सहित कुल उधारी अब 12.05 लाख करोड़ रुपये से लगभग 16.3 लाख करोड़ रुपये हो जाएगी।

आगे की राह

- केंद्र के उधार कार्यक्रम की सफलता आरबीआई द्वारा प्रदान की गई सहायता पर निर्भर करती है।
- समर्थन प्रत्यक्ष होना आवश्यक नहीं है। यह अप्रत्यक्ष हो सकता है जैसा कि वर्तमान में आरबीआई द्वारा सिस्टम में तरलता को बड़े पैमाने पर इंजेक्ट करने के साथ हो रहा है।
- नकदी के अन्तःक्षेपण की अपनी सीमाएं हैं। यहां तक कि जब हम सरकारी खर्च में विस्तार पर जोर देते हैं, तो मुद्रास्फीति के लिए नकदी विस्तार के निहितार्थों को ध्यान में रखना आवश्यक है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- केंद्रीय बजट 2021-21
- भारत में मंदी
- आर्थिक सर्वेक्षण 2021

क्रिप्टोकरेंसी और RBI

संदर्भ: कुछ प्रमुख बैंकों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी में लेनदेन के खिलाफ लोगों को आगाह करने के कुछ दिनों बाद, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने कहा कि बैंक आभासी मुद्राओं पर अपने अप्रैल 2018 के आदेश का हवाला नहीं दे सकते हैं - जिसने उन पर प्रतिबंध लगा दिया था - क्योंकि इसे 2020 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अलग रखा गया।

क्रिप्टोकरेंसी कैसे काम करती है?

- क्रिप्टोकरेंसी ब्लॉकचेन नामक तकनीक का उपयोग करके काम करती है। ब्लॉकचेन एक विकेन्द्रीकृत तकनीक है जो कई कंप्यूटरों में फैली हुई है जो लेनदेन का प्रबंधन और रिकॉर्ड करती है।
- इसलिए, आरबीआई जैसे पारंपरिक वित्तीय संस्थानों पर भरोसा करने के बजाय, जो आपके लेनदेन को सत्यापित और गारंटी देते हैं, क्रिप्टोकुरेंसी लेनदेन मुद्रा के नेटवर्क में लॉग इन उपयोगकर्ता के कंप्यूटर द्वारा सत्यापित होते हैं।

- ब्लॉकचेन एक प्रकार का विकेंद्रीकृत बही-खाता (Distributed Ledger) होता है, जिसमें विनिमय से संबंधित जानकारी को कूटबद्ध तरीके से एक ब्लॉक के रूप में सुरक्षित किया जाता है।
- खनन की प्रक्रिया मौजूदा परिसंचारी आपूर्ति में नए सिक्कों को पेश करने के लिए भी जिम्मेदार है और यह उन प्रमुख तत्वों में से एक है जो क्रिप्टोकरेंसी को किसी तीसरे पक्ष के केंद्रीय प्राधिकरण की आवश्यकता के बिना पीयर-टू-पीयर विकेन्द्रीकृत नेटवर्क के रूप में काम करने की अनुमति देता है।

क्रिप्टोकरेंसी के साथ चिंता

अत्यधिक अस्थिरता

- यह एक संप्रभु राज्य और केंद्रीय बैंक जैसी सार्वजनिक संस्था द्वारा समर्थित नहीं है।
- विनियामक प्राधिकारियों ने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग सहित अवैध गतिविधियों के लिए उपकरणों के रूप में इनके इस्तेमाल पर चिंता व्यक्त की है।
- क्रिप्टोकरेंसी पर भारत की स्थिति को प्रभावित करने वाली नियामक अनिश्चितताओं के बारे में निवेशकों में चिंता। कहा जाता है कि भारतीय निवेशकों के पास पहले से ही डिजिटल मुद्रा में लगभग 10,000 करोड़ रुपये हैं।

आरबीआई के स्पष्टीकरण का निहितार्थ: क्रिप्टोकरंसीज के निवेशकों को राहत

- जितने भारतीयों ने बिटकॉइन और एथेरियम जैसी क्रिप्टोकरेंसी में निवेश किया है, आरबीआई का कदम उनके लिए एक बड़ी राहत होगी और उनका पैसा लगभग 10,000 करोड़ रुपये अवरुद्ध नहीं होगा।
- साथ ही, बैंक अदालत और आरबीआई के निर्देशों का पालन करते हुए वर्चुअल करेंसी में निवेशकों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते हैं।

आरबीआई की स्थिति क्या है?

- ध्यातव्य है कि अप्रैल 2018 के आदेश में RBI ने अपने द्वारा विनियमित सभी बैंकों और अन्य वित्तीय इकाइयों को तीन माह के अंदर क्रिप्टोकरेंसी के व्यापार से स्वयं को अलग करने के निर्देश दिये थे।
- आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में कहा था कि "केंद्रीय बैंक की डिजिटल मुद्रा पर काम चल रहा है। आरबीआई की टीम इस पर काम कर रही है, प्रौद्योगिकी पक्ष और प्रक्रियात्मक पक्ष इसे कैसे लॉन्च और रोल आउट किया जाएगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी
- चीन की डिजिटल मुद्रा

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) 4.0

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- सरकार ने आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS) के दायरे को तीन और महीनों के लिए बढ़ा दिया है।
- **इसे क्यों बढ़ाया गया?**
    - COVID 19 महामारी की दूसरी लहर के कारण होने वाले व्यवधानों का अवलोकन किया गया है। यह विस्तार अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में व्यवसायों की मदद करेगा।

ECLGS 4.0 के बारे में

- अस्पतालों/नर्सिंग क्लीनिकों/मेडिकल कॉलेजों/घरों में 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 100% गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा।

- ऑन-साइट ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र स्थापित करने के लिए ऋण का उपयोग किया जा सकता है। इस ऋण पर ब्याज दर 5% पर सीमित कर दी गई है।
- नागरिक उड्डयन क्षेत्र ECLGS 3.0 के तहत पात्र होगा।
- ECLGS की वैधता 30 सितंबर 2021 तक या 3 ट्रिलियन रुपए की गारंटी तक बढ़ाई गई समस्याएँ हैं।

महत्व

- ECLGS 4.0 MSMEs को अतिरिक्त सहायता प्रदान करके ECLGS की उपयोगिता और प्रभाव को बढ़ाएगा।
- यह आजीविका की रक्षा करेगा।
- यह व्यावसायिक गतिविधि को फिर से शुरू करने में मदद करेगा।
- यह उचित शर्तों पर संस्थागत ऋण के प्रवाह को सुगम बनाएगा।

अन्य संबंधित तथ्य

आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ECLGS)

- ECLGS को मई 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया था।
- **उद्देश्य:** लॉकडाउन के कारण अर्थव्यवस्था पर उत्पन्न संकट को दूर करना।
- इसने विभिन्न क्षेत्रों को ऋण प्रदान करके उनकी मदद की।
- सैद्धांतिक पुनर्भुगतान पर एक वर्ष की प्रतिबंध अवधि के अलावा उन्हें चार साल के लिए ऋण प्रदान किया गया था।

एसडीजी भारत सूचकांक 2020-21 में शीर्ष पर केरल, बिहार का प्रदर्शन सबसे निचले स्तर पर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - विकास; शासन

सुर्खियों में-

- सतत विकास लक्ष्य (SDG) भारत सूचकांक 2020-21 हाल ही में जारी किया गया।
- **द्वारा शुरू किया गया:** नीति आयोग
- एसडीजी भारत सूचकांक को भारत में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI), ग्लोबल ग्रीन ग्रोथ इंस्टीट्यूट और संयुक्त राष्ट्र के सहयोग से विकसित किया गया।
- केरल ने शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि बिहार को सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला स्थान दिया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- **दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य :** हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु।
- **बिहार के अलावा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य:** झारखंड और असम।

सूचकांक मायने क्यों रखता है?

- यह भारत में SDGs पर प्रगति की निगरानी के लिए एक प्राथमिक उपकरण है।
- स्थिरता, लचीलापन और भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए एक समर्थन उपकरण के रूप में सूचकांक सफल रहा है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

सतत विकास लक्ष्य या वैश्विक लक्ष्य

- वे 17 परस्पर जुड़े हुए वैश्विक लक्ष्यों का एक संग्रह हैं।
- उन्हें "सभी के लिए बेहतर और अधिक टिकाऊ भविष्य प्राप्त करने का खाका" बनने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

- 2015 में स्थापित
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्थापित
- **लक्ष्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य:** 2030

केंद्र ने राज्यों से मनरेगा योजना के तहत मजदूरी भुगतान को अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करने के लिए कहा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- केंद्र ने राज्यों से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) योजना के तहत इस वित्तीय वर्ष से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य के लिए अलग-अलग श्रेणियों में वेतन भुगतान को विभाजित करने के लिए कहा है।
- SC और ST श्रेणियों के लिए सरकार द्वारा अलग-अलग बजट शीर्ष भी उपलब्ध कराए जाएंगे।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए उपलब्ध कराए गए जॉब कार्ड के अनुसार धन आवंटित किया जाएगा।

आदेश के साथ मुद्दे

- यह अनावश्यक रूप से भुगतान प्रणाली को जटिल बना देगा,
- इससे योजना के वित्त पोषण में कमी भी आ सकती है।

अन्य सम्बंधित तथ्य

MGNREGA के बारे में

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (NREGA) 2005 में अधिसूचित किया गया था।
- **लक्ष्य:** ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका सुरक्षा में सुधार करना।
- यह एक सार्वभौमिक योजना है जो मांग व्यक्त करने वाले प्रत्येक ग्रामीण परिवार को एक वर्ष में 100 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।
- नौकरी आवेदन प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर रोजगार के प्रावधान की विफलता के परिणामस्वरूप नौकरी चाहने वालों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान किया जाएगा।
- आवेदक के निवास के 5 किमी के दायरे में रोजगार उपलब्ध कराया जाना है।
- मनरेगा के तहत रोजगार एक कानूनी अधिकार है।

तेल की कीमतों में वृद्धि

संदर्भ: कच्चे तेल की कीमतें दो साल के उच्च स्तर पर पहुंच गई हैं, जिसमें ब्रेंट क्रूड 71 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल के स्तर को पार कर गई है।

कच्चे तेल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं?

- **आर्थिक सुधार:** कच्चे तेल की कीमतें 2021 की शुरुआत से लगातार बढ़ रही हैं, जब ब्रेंट क्रूड लगभग 52 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, दोनों भौगोलिक क्षेत्रों में आर्थिक सुधार के कारण मांग में सुधार की उम्मीद से उत्साहित थे।
- **प्रमुख तेल उत्पादक देशों द्वारा आपूर्ति में कटौती:** पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ने 2020 में की गई आपूर्ति में कटौती की, जब कच्चे तेल की कीमतें 2021 के पहले पांच महीनों के दौरान 19 डॉलर प्रति बैरल के निचले स्तर पर पहुंच

गई थीं। सऊदी अरब ने विशेष रूप से एक अतिरिक्त स्वैच्छिक फरवरी से अप्रैल के बीच प्रतिदिन 10 लाख बैरल उत्पादन में कटौती की।

- **ईरान राहत का कोई प्रभाव नहीं:** एक नए ईरान परमाणु समझौते के लिए अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में एक संभावित सफलता जो ईरानी तेल पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों को हटा देगी, ओपेक के अनुसार तेल की कीमतों पर भी कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ईरान से कच्चे तेल के उत्पादन में कोई भी वृद्धि धीरे-धीरे होगी और इससे कच्चे तेल की कीमतें अस्थिर नहीं होंगी।

कच्चे तेल की ऊंची कीमतें भारत को कैसे प्रभावित करती हैं?

- **मुद्रास्फीति:** पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तब तक वृद्धि होना तय है जब तक कि ऑटो ईंधन पर शुल्क में कटौती या कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट नहीं होती है। ये बढ़ती कीमतें वस्तुओं और सेवाओं की परिवहन लागत को प्रभावित करेंगी और इस प्रकार मुद्रास्फीति का कारण बनेंगी।
- राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल के पंप मूल्य का लगभग 58 प्रतिशत और डीजल के पंप मूल्य का 52 प्रतिशत राज्य और केंद्रीय करों का है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 2020 तेल बाजार में मंदी
- भारत की जीडीपी में गिरावट
- भारत में सामरिक तेल भंडार

विश्व बैंक द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना रिपोर्ट

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III- अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- जून, 2021 में वाशिंगटन डी.सी. स्थित विश्व बैंक समूह द्वारा वैश्विक आर्थिक संभावना (Global Economic Prospects) रिपोर्ट, 2021 जारी की गई।
- इसने वर्ष 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर 8.3% रहने का अनुमान लगाया है।
- भारत की अर्थव्यवस्था 2022-23 के लिए 7.5% और 2023-24 के लिए 6.5% की दर से बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष

- विश्व अर्थव्यवस्था के 5.6% की दर से विस्तार होने की उम्मीद है, जो 80 वर्षों में मंदी के बाद की सबसे तेज वृद्धि दर है।
- हालांकि, वैश्विक उत्पादन अभी भी वर्ष के अंत तक महामारी पूर्व अनुमानों से 2% कम रहेगा।
- महामारी की शुरुआत के बाद से किसी भी देश के सबसे बड़े प्रकोप से भारत की वसूली में बाधा आ रही है।
- वर्ष 2021 में भारत की विकास दर 8.3 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी कोविड -19 लहर और स्थानीय गतिशीलता प्रतिबंधों से अपेक्षित आर्थिक क्षति को ध्यान में रखा गया है।
- 2022-23 के लिए, परिवारों, कंपनियों और बैंकों की वित्तीय स्थिति पर महामारी के प्रभाव के परिणामस्वरूप विकास दर धीमी होकर 7.5% होने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के सुझाव

- विशेष रूप से कम आय वाले देशों के लिए वैक्सीन वितरण और ऋण राहत में तेजी लाने के लिए विश्व स्तर पर समन्वित प्रयास आवश्यक हैं।

- स्वास्थ्य संकट कम होने के साथ नीति निर्माताओं को महामारी के स्थायी प्रभावों को दूर करने और व्यापक तौर पर आर्थिक स्थिरता सुनिश्चित करते हुए हरित, मजबूत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाने की आवश्यकता होगी।"

विश्व बैंक की प्रमुख रिपोर्ट

- व्यापार करने में आसानी।
- मानव पूंजी सूचकांक।
- विश्व विकास रिपोर्ट।
- प्रवासन और विकास संक्षिप्त।
- वैश्विक आर्थिक संभावनाएं।

2020-21 के लिए भारत का कृषि व्यापार सारांश

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III- अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- पिछले तीन वर्षों से स्थिर रहने के बाद, 2020-21 के दौरान कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात बढ़कर 41.25 अरब डॉलर हो गया, जो 17.34% की वृद्धि दर्शाता है।
- भारत के कृषि उत्पादों के लिए सबसे बड़ा बाजार: संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, बांग्लादेश, संयुक्त अरब अमीरात, वियतनाम, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, नेपाल, ईरान और मलेशिया।
- **निर्यात की जाने वाली प्रमुख कृषि वस्तुएं:** समुद्री उत्पाद, चावल, भैंस का मांस, मसाले आदि।
- 2020-21 के दौरान जैविक निर्यात में 50.94% की वृद्धि दर्ज की गई।
- जैविक निर्यात में शामिल हैं: ऑयल केक/मील, तिलहन, अनाज एवं बाजरा, मसाले एवं कोंडीमंट (छौंक), चाय, औषधीय पादप उत्पाद, सूखे मेवे, चीनी, दलहन, काफी आदि शामिल हैं।

वृद्धि मुख्य रूप से इसके लिए जिम्मेदार है:

- कोविड-19 के कारण पेश किए गए अवसर वैश्विक कमोडिटी कीमतों में तेज वृद्धि की तरह पेश किए गए।
- कृषि निर्यात नीति, 2018 से उभर रहे विभिन्न कार्यक्रम
- **बेहतर बाजार पहुंच:** भारत ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया में अनार के लिए, अर्जेंटीना में आम और बासमती चावल के लिए बाजार पहुंच हासिल की है।
- विदेशी देशों में नए बाजारों पर कब्जा
- यूरोपीय संघ के मानदंडों का पालन
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहचान के लिए घरेलू उत्पादों को जीआई टैग

विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस ईयरबुक (World Competitiveness Yearbook- WCY) के अनुसार भारत ने वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक (World Competitiveness Index) में 43वाँ स्थान बनाए रखा है।

- विश्व प्रतिस्पर्द्धात्मकता सूचकांक एक व्यापक वार्षिक रिपोर्ट और देशों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को लेकर विश्वव्यापी संदर्भ बिंदु है।

- **संकलित:** प्रबंधन विकास संस्थान (IMD)।
- इसने इस साल दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर COVID-19 के प्रभाव की जांच की।
- यह चार कारकों (334 प्रतिस्पर्द्धात्मकता मानदंड) की जाँच करके देशों की समृद्धि और प्रतिस्पर्द्धात्मकता को मापता है:
  - आर्थिक प्रदर्शन
  - सरकारी दक्षता
  - व्यापार दक्षता
  - आधारभूत संरचना

रिपोर्ट द्वारा मुख्य विश्लेषण

- कई देश दूरस्थ शिक्षा की अनुमति देते हुए दूरस्थ कार्य दिनचर्या में परिवर्तन करने में सफल रहीं।
- बेरोजगारी को संबोधित करना मौलिक रहा है।

रैंकिंग

- **शीर्ष देश:** स्विट्जरलैंड (पहला), स्वीडन (दूसरा), डेनमार्क (तीसरा), नीदरलैंड (चौथा)।
- शीर्ष प्रदर्शन करने वाली एशियाई अर्थव्यवस्थाएं: सिंगापुर (5वां), हांगकांग (7वां), ताइवान (8वां) और चीन (16वां)।

भारत का प्रदर्शन

- भारत ने पिछले तीन वर्षों से अपनी स्थिति बनाए रखी है।
- इस वर्ष, सरकारी दक्षता में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
- भारत की शक्ति दूरसंचार (प्रथम), मोबाइल टेलीफोन लागत (प्रथम), आईसीटी सेवाओं के निर्यात (तीसरे), सेवा व्यवसायों में पारिश्रमिक (चौथा) और व्यापार सूचकाँक (पाँचवें) में निवेश में बेहतर प्रदर्शन किया।
- भारत का प्रदर्शन सब-इंडेक्स जैसे- ब्रॉडबैंड सब्सक्राइबर (64वाँ), पार्टिकुलेट पॉल्यूशन (64वाँ), मानव विकास सूचकांक (64वाँ), प्रति व्यक्ति जीडीपी (63वाँ) और प्रति व्यक्ति विदेशी मुद्रा भंडार (62वाँ) आदि में सबसे खराब रहा है।

अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए भारत द्वारा हाल ही में उठाए गए कदम

- सरकार ने भारत की विनिर्माण क्षमताओं और निर्यात को बढ़ाने के लिये विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना शुरू की है।
- आत्मनिर्भर भारत अभियान (या आत्मनिर्भर भारत मिशन) के पाँच स्तंभ हैं- अर्थव्यवस्था, बुनियादी ढाँचा, प्रणाली, जीवंत जनसांख्यिकी और मांग।

FDI अंतर्वाह

संदर्भ: भारत ने वित्तीय वर्ष 2020-21 (वित्त वर्ष 2019-20 से 10% अधिक) के दौरान 81.72 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सबसे अधिक FDI प्रवाह आकर्षित किया है। आरबीआई ने बताया कि अंतर्वाह का इक्विटी घटक 61.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक था।

सकारात्मक

- भारत में बढ़ते FDI अंतर्वाह ऐसे समय हैं जब 2020 में वैश्विक FDI अंतर्वाह 2019 के स्तर से 42% कम हो गया और विकासशील देशों में अंतर्वाह में 12% की गिरावट आई।

चिंता

- **जियो डील:** डेटा से पता चलता है कि तीन रिलायंस समूह की कंपनियों ने वित्त वर्ष 2020-21 की तीन तिमाहियों के दौरान कुल इक्विटी प्रवाह का 27.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर या 54.1% प्राप्त किया।
- **वितरण में एकाग्रता :** शीर्ष पांच FDI सौदों के बिना, 2020-21 के दौरान FDI प्रवाह में एक साल पहले अपने स्तर के लगभग एक तिहाई की गिरावट आई होगी।
- **उत्पादक परिसंपत्तियों के निर्माण में कमी:** निवेशों के बड़े हिस्से की प्रकृति में देश में उत्पादक संपत्ति बनाए बिना शेयरों का मात्र हस्तांतरण शामिल था। इस प्रकार, FDI अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में ज्यादा योगदान नहीं दे सकता है।
- **विनिर्माण क्षेत्र में अपर्याप्त निवेश:** इस क्षेत्र को 2020-21 के दौरान कुल अंतर्वाह का केवल 17.4% प्राप्त हुआ, जबकि सेवा क्षेत्र ने कुल प्रवाह का 80% आकर्षित किया।

निष्कर्ष

- आगे बढ़ते हुए, 2021-22 के लिए FDI की पाइपलाइन को PLI और घरेलू विकास संभावनाओं पर दिए गए जोर से समर्थन मिल सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना
- भारतीय अर्थव्यवस्था में मंदी
- आर्थिक सर्वेक्षण

फेडरल रिजर्व सिग्नल और भारतीय बाजार

संदर्भ: यूएस फेडरल रिजर्व ने संकेत दिया कि 2023 तक दो दरों में बढ़ोतरी हो सकती है।

- इस घोषणा के बाद, भारत में बेंचमार्क सेंसेक्स में मामूली गिरावट आई और डॉलर के मुकाबले रुपये में 1% से अधिक की गिरावट आई।

फेडरल रिजर्व ने क्या कहा?

- यूएस फेडरल रिजर्व ने कहा कि वे अर्थव्यवस्था को समर्थन देने, रोजगार पैदा करने और लगभग 2% की मुद्रास्फीति हासिल करने के लिए एक उदार मौद्रिक नीति और बांड खरीद कार्यक्रम जारी रखेंगे।
- साथ ही, उन्होंने केंद्रीय बैंक के बांड खरीद कार्यक्रम की दर वृद्धि और एक अंतिम कमी, या टेपरिंग पर चर्चा की। यह मार्च की घोषणा से विचलन था।
    - मार्च 2021 में, फेड ने संकेत दिया कि वे 2023 तक दरों को शून्य के करीब रखेंगे।
- कुछ सदस्य 2022 में कम से कम एक बार दरें बढ़ाने के पक्ष में भी थे।
- फेडरल रिजर्व ने नोट किया कि टीकाकरण पर प्रगति ने संयुक्त राज्य अमेरिका में कोविड-19 के प्रसार को कम कर दिया है और मजबूत नीति समर्थन के साथ अर्थव्यवस्था के मूल सिद्धांतों ने वृद्धि दर को मजबूत किया है।

बाजारों की प्रतिक्रिया कैसी रही?

- यू.एस. में ब्याज दरों में वृद्धि का न केवल अमेरिका में बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं में भी ऋण और इक्विटी बाजारों पर असर पड़ता है।
    - यूएस फेडरल रिजर्व की आसान मौद्रिक नीति के कारण पिछले एक साल में भारत ने रिकॉर्ड विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) देखा था। निवेशक आसान ऋण प्राप्त कर सकते हैं और इसे त्वरित रिटर्न के लिए उभरते बाजारों में स्पंदित कर सकते हैं।

- फेड के संकेत के बाद, डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल 265 अंक गिर गया और ट्रेजरी यील्ड 1.498% से बढ़कर 1.569% हो गया।
- भारत में, बेंचमार्क सेंसेक्स 461 अंक या 0.87% गिर गया और डॉलर के मुकाबले रुपया 75 पैसे या 1% गिर गया।

ब्याज दरों में जल्द बढ़ोतरी का असर क्या हो सकता है?

- यू.एस. में ब्याज दर में वृद्धि की खबर से न केवल इक्विटी से यू.एस. ट्रेजरी बांडों में धन का उत्प्रवाह होता है, बल्कि उभरती अर्थव्यवस्थाओं से अमेरिका में धन का उत्प्रवाह भी होता है।
- डॉलर के मजबूत होने से रुपया के भाव में गिरने की आशंका है।
- जून के बाद भारतीय पूंजी बाजारों में 14,500 करोड़ रुपये का FPI प्रवाह देखा गया, यह देखा जाना बाकी है कि आने वाले हफ्तों और महीनों में प्रवाह की गति में मंदी है या नहीं।

भारत के लिए घरेलू चिंताएं क्या हैं?

- थोक मुद्रास्फीति पांच महीने से बढ़ रही है, इसके और बढ़ने की उम्मीद है क्योंकि कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और कमजोर रुपये के कारण कमोडिटी की कीमतों में बढ़ोतरी का असर है।
- चूंकि, इस बीच आरबीआई द्वारा दर में कटौती की कोई और गुंजाइश नहीं है, सभी की निगाहें विकास को गति देने के लिए राजकोषीय नीति कार्रवाई के लिए सरकार पर हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- रोजगार और भारतीय अर्थव्यवस्था की वसूली
- भारत में मंदी

नए वित्तीय प्रोत्साहन की मांग

संदर्भ: भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) ने सरकार से अर्थव्यवस्था में मांग को बढ़ावा देने के लिए नए वित्तीय प्रोत्साहन के रूप में अतिरिक्त 3 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का आग्रह किया है।
यह भी सुझाव दिया है कि यह पैसा कहां खर्च किया जाना चाहिए

- जन धन बैंक खातों वाले परिवारों को सीधे नकद हस्तांतरण प्रदान करें,
- मनरेगा आवंटन बढ़ाने और ग्रामीण भारत में अधिक रोजगार की गारंटी प्रदान करने के लिए,

बार-बार नए प्रोत्साहन की मांग क्यों?

- आर्थिक सुधार की राह पर है लेकिन सरकार की ओर से नए प्रोत्साहन के अभाव में वसूली काफी धीमी हो सकती है।
- कुल मिलाकर, वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन (या आपूर्ति) और खपत (या मांग) दोनों के आने वाले समय में कम होने की संभावना है, जब तक कि सरकार लोगों के हाथों में पैसा किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं करती है।

अतिरिक्त 3 लाख करोड़ रुपये कहां से आएंगे?

- सरकार का वित्त पहले से ही काफी बढ़ा हुआ है। राजकोषीय घाटा पहले से ही FRBM अधिनियम द्वारा निर्धारित मानदंडों के दोगुने से अधिक है।
- CII ने सुझाव दिया कि सरकार को आरबीआई से "बढ़ी हुई प्रोत्साहन राशि को समायोजित करने के लिए अपनी बैलेंस शीट का विस्तार करने" के लिए कहना चाहिए। दूसरे शब्दों में, वह चाहता है कि आरबीआई 3 लाख करोड़ रुपये की नई नकदी छापे और सरकार को खर्च करने के लिए दे।
- अतिरिक्त पैसे की छपाई का अनुरोध किया जाता है ताकि उधार की लागत कम रहे।
    - यदि सरकार प्रोत्साहन को निधि देने के लिए बाजार से धन उधार लेती है, तो धन के लिए परिणामी प्रतिस्पर्धा बाजार में ब्याज दरों में वृद्धि करेगी, जिसे निजी क्षेत्र द्वारा आर्थिक प्रतिक्षेप की तलाश में पसंद नहीं किया जाता है।

पैसे छापने की चिंता

- पैसे छापने से मुद्रास्फीति हो सकती है। भारत में पहले से ही उच्च मुद्रास्फीति है इसलिए यह सुझाव समस्याग्रस्त है।
- साथ ही, महंगाई सबसे ज्यादा गरीबों को प्रभावित करती है।
- पैसे की छपाई सरकारों को गैर-जिम्मेदाराना तरीके से खर्च करने के लिए प्रेरित करती है, जिससे वित्तीय स्थिति खराब और पैसे का दुरपयोग हो सकता है।

क्या अधिक पैसे छापने का कोई विकल्प है?

कई विकल्प हैं।

1. कॉर्पोरेट जगत में "वेतन अनुपात" को कम करना

- एक फर्म का वेतन अनुपात (उदा: 5), फर्म में शीर्ष वेतन पाने वाले प्रबंधक (रु. 25 लाख) के वेतन का फर्म में औसत वेतन (रु. 5 लाख) से अनुपात है।
- वेतन-अनुपात को कम करने से श्रमिकों के हाथ में अधिक पैसा आएगा जिससे उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी और मांग बढ़ेगी।
- हालांकि, यह उपाय कंपनियों को तय करना है और सरकार कुछ नहीं कर सकती।

2. धन कर

- 2018 में भारत में निजी व्यक्तियों की कुल संपत्ति 570 लाख करोड़ रुपये थी।
- इस राशि में शीर्ष 1% के पास 58% या लगभग 330 लाख करोड़ रु.
- सिर्फ शीर्ष 1% की संपत्ति पर 2% कर लगाने से 6.6 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।

3. विरासत कर

- अगर हम मान लें कि इस शीर्ष स्टार्टअप की कुल संपत्ति का 5% हर साल विरासत के रूप में अपने बच्चों या अन्य विरासतों को हस्तांतरित हो जाता है, तो इस तरह की विरासत के एक तिहाई का मामूली कराधान भी 5.5 लाख करोड़ रुपये प्राप्त होगा।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- आत्मानिर्भर भारत अभियान
- आत्मानिर्भर भारत अभियान 3.0 के तहत आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज

ई-कॉमर्स साइटों पर 'फ्लैश बिक्री' पर प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III- ई-कॉमर्स

सुर्खिओ में क्यों-

- सरकार ने ई-कॉमर्स वेबसाइटों पर दी जाने वाली गहरी छूट की निगरानी के लिए सभी "फ्लैश बिक्री" पर प्रतिबंध लगाते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (ई-कॉमर्स) नियम 2020 में बदलाव का प्रस्ताव रखा।

परिवर्तन करने का औचित्य

- तीसरे पक्ष के विक्रेताओं द्वारा पारंपरिक फ्लैश बिक्री ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। केवल 'शिकारी' लोगों पर प्रतिबंध लगाया जाएगा,

- छोटे व्यवसायों ने अमेज़ॅन और फ्लिपकार्ट जैसे ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस द्वारा बाजार प्रभुत्व के दुरुपयोग और गहरी छूट की शिकायत की।

अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव

- ई-कॉमर्स साइटों को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24×7 समन्वय के लिए एक नोडल संपर्क व्यक्ति, अधिकारियों को उनके आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने और निवासी शिकायत अधिकारी की नियुक्ति सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।
- इन कंपनियों को एक निवासी शिकायत अधिकारी का भी नाम देना होगा, जिसे कंपनी का कर्मचारी और भारत का नागरिक होना चाहिए।
- अधिमान्य व्यवहार की बढ़ती चिंताओं से निपटने के लिए, नए नियमों में यह सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है कि किसी भी संबंधित पक्ष को 'अनुचित लाभ' के लिए किसी भी उपभोक्ता जानकारी का उपयोग करने की अनुमति नहीं है।
- कंपनियों को अपने मूल देश के आधार पर माल की पहचान भी करनी होगी और ग्राहकों के लिए खरीद से पहले के चरण में एक फिल्टर तंत्र प्रदान करना होगा।
- घरेलू विक्रेताओं को "उचित अवसर" प्रदान करने के लिए उन्हें इन आयातित सामानों के विकल्प भी पेश करने होंगे।
- यदि कोई विक्रेता किसी वस्तु या सेवा को प्रदान करने में विफल रहता है, तो अंतिम दायित्व ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस पर पड़ेगा।
- भारत में काम कर रही ई-कॉमर्स फर्मों को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत भी पंजीकरण कराना होगा।

ई-कॉमर्स के बारे में

- इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स (ई-कॉमर्स) एक व्यवसाय मॉडल है जो फर्मों और व्यक्तियों को इंटरनेट पर चीजें खरीदने और बेचने की सुविधा देता है।
- भारतीय ई-कॉमर्स बाजार के 2026 तक बढ़कर 200 अरब अमेरिकी डॉलर होने की उम्मीद है, जो 2017 में 38.5 अरब अमेरिकी डॉलर था।
    - स्मार्टफोन की बढ़ती निवेश
    - 4G नेटवर्क का शुभारंभ
    - बढ़ती उपभोक्ता संपत्ति
- 2034 तक यह अमेरिका को पछाड़कर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ई-कॉमर्स बाजार बनने की उम्मीद है।

ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए नए ड्राफ्ट नियम

संदर्भ: सरकार ने कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल के तहत ई-कॉमर्स नियमों में बदलाव का प्रस्ताव दिया है ताकि वह ढांचा तैयार किया जा सके जिसके तहत फर्में अधिक सख्त काम करती हैं।

प्रस्तावित प्रमुख परिवर्तन हैं-

- **आईटी मध्यस्थ नियमों के साथ समानताएं:** मसौदा नियम कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ 24x7 समन्वय के लिए एक मुख्य अनुपालन अधिकारी, एक नोडल संपर्क व्यक्ति की नियुक्ति को भी निर्धारित करते हैं।

- **फॉल-बैक लायबिलिटी:** यहां, ई-कॉमर्स फर्मों को उत्तरदायी ठहराया जाएगा यदि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई विक्रेता लापरवाह आचरण के कारण सामान या सेवाओं को वितरित करने में विफल रहता है, जिससे ग्राहक को नुकसान होता है। पहले प्लेटफॉर्म यह था कि पीड़ित व्यक्ति सीधा विक्रेता को निर्देशित करता था, अब वे प्लेटफॉर्म तक ही पहुंच सकेंगे।
- **निष्पक्ष मंच:** नियमों में ई-कॉमर्स कंपनियों को "खोज परिणामों या खोज अनुक्रमणिका में हेरफेर" करने से प्रतिबंधित करने का प्रस्ताव है ताकि कुछ उत्पादों के लिए बेहतर उपचार को रोका जा सके।
- **मेड-इन-इंडिया उत्पादों के लिए धक्का:** ई-कॉमर्स संस्थाएं आयातित वस्तुओं या सेवाओं की पेशकश करने के लिए 'मूल देश के आधार पर माल की पहचान करने के लिए एक फिल्टर तंत्र को शामिल करती हैं और घरेलू सामानों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने के लिए विकल्प सुझाती हैं'।
- **ई-कॉमर्स संस्थाओं द्वारा "विशिष्ट फ्लैश बिक्री" पर प्रतिबंध:** जबकि मसौदा नियमों के अनुसार, पारंपरिक ई-कॉमर्स फ्लैश बिक्री पर प्रतिबंध नहीं है, विशिष्ट फ्लैश बिक्री या बैक-टू-बैक बिक्री "जो ग्राहक की पसंद को सीमित करती है तथा कीमतों में वृद्धि करती है।
- **उपभोक्ता हेल्पलाइन के साथ एकीकरण:** मसौदा संशोधन में ई-कॉमर्स फर्मों को अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का हिस्सा बनने के लिए कहने का भी प्रस्ताव है।

अन्य प्रस्ताव

- सभी ई-कॉमर्स खिलाड़ियों के लिए पंजीकरण भी अनिवार्य कर दिया गया है।
- 10 प्रतिशत या उससे अधिक सामान्य अंतिम लाभकारी स्वामित्व वाली किसी भी इकाई को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का "संबद्ध उद्यम" माना जाएगा।
- साइबर सुरक्षा मुद्दों सहित कानून के किसी भी उल्लंघन की जांच करने वाली अधिकृत सरकारी एजेंसी द्वारा किए गए किसी भी अनुरोध पर सभी संस्थाओं को 72 घंटों के भीतर जानकारी प्रदान करनी होगी।

मसौदा नियमों का विश्लेषण

- **सरकार द्वारा अधिक निगरानी:** नए आईटी नियमों के अधिनियमन के बाद, मसौदा ई-कॉमर्स संशोधन सभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अधिक से अधिक निगरानी करने के लिए सरकार की बढ़ती उत्सुकता को दर्शाता है।
- **ऑफलाइन खुदरा विक्रेताओं के लिए समान अवसर:** जेब ढीली करने वाली ई-कॉमर्स कंपनियों ने अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गहरी छूट की रणनीति अपनाई है। इस हिंसक व्यवसाय प्रथाओं ने ऑफ़लाइन खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाई है। नए नियमों का मुख्य उद्देश्य इसे सही करना है।

चिंता

- इनमें से कई मानदंडों को लागू करने से लंबी कानूनी लड़ाई को बढ़ावा मिलेगा।
- अब तक विस्तारित ई-कॉमर्स क्षेत्र में विकास और रोजगार सृजन को मंद करने वाले व्याख्यात्मक अस्पष्टता जोखिमों की गुंजाइश के साथ अति-विनियमन।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- नए आईटी नियम
- सोशल मीडिया चिंताएं
- बड़ी तकनीक का प्रभुत्व
- ऑस्ट्रेलिया का समाचार मीडिया बार्गेनिंग कोड

प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III- अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- वित्तीय वर्ष 2021-22 के पहले ढाई महीनों (अप्रैल-जून) में भारत का प्रत्यक्ष कर संग्रह लगभग 1.86 लाख करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में लगभग दोगुना है।
    - इसमें निगम कर संग्रह तथा व्यक्तिगत आयकर प्रवाह शामिल हैं।
- प्रत्यक्ष कर संग्रह में उछाल स्वस्थ निर्यात और विभिन्न औद्योगिक एवं निर्माण गतिविधियों की निरंतरता को दर्शाता है।
    - यह उम्मीद की जा रही है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जीडीपी (सकल घरेलू उत्पाद) दोहरे अंकों में विस्तार दर्ज करेगी।

प्रत्यक्ष कर के बारे में

- प्रत्यक्ष कर एक ऐसा कर है जो एक व्यक्ति या संगठन द्वारा प्रत्यक्ष तौर पर उस संस्था को दिया जाता है जिसने इसे इसे लगाया है।
- उदाहरण के लिये एक व्यक्तिगत करदाता, आयकर, वास्तविक संपत्ति कर, व्यक्तिगत संपत्ति कर सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिये सरकार को प्रत्यक्ष कर का भुगतान करता है।

प्रत्यक्ष करों में सुधार के लिए सरकार की पहल

- वित्त अधिनियम, 2020 ने व्यक्तियों और सहकारी समितियों को रियायती दरों पर आयकर का भुगतान करने का विकल्प प्रदान किया है यदि वे निर्दिष्ट छूट और प्रोत्साहन का लाभ नहीं उठाते हैं।
- **विवाद से विश्वास:** इसके तहत वर्तमान में लंबित कर विवादों के निपटारे के लिये घोषणाएँ दायर की जा रही हैं।
    - इससे सरकार को समय पर राजस्व सृजित करने और मुकदमेबाजी की बढ़ती लागत को कम करने से करदाताओं को भी लाभ होगा।
- कर आधार को व्यापक बनाने के लिए, कई नए लेनदेन को स्रोत पर कर कटौती (TDS) और स्रोत पर कर संग्रह (TCS) के दायरे में लाया गया है।
- इन लेन-देन में भारी नकद निकासी, विदेशी प्रेषण, लक्जरी कारों की खरीद, ई-कॉमर्स प्रतिभागियों, सामानों की बिक्री, अचल संपत्ति का अधिग्रहण आदि शामिल हैं।
- **'पारदर्शी कराधान - ईमानदार का सम्मान' मंच:** इसका उद्देश्य आयकर प्रणालियों में पारदर्शिता लाना और करदाताओं को सशक्त बनाना है।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूक्ष्म वित्त के विनियमन पर एक परामर्शदायी दस्तावेज

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- भारतीय रिजर्व बैंक ने सूक्ष्म वित्त के विनियमन पर एक परामर्शदायी दस्तावेज जारी किया है।
- यह दस्तावेज सूक्ष्म वित्त के क्षेत्र में विभिन्न कर्जदाताओं को नियमों से तालमेल बनाए रखने का मार्गदर्शन देता है।
- इसने यह भी कहा कि सभी सूक्ष्म ऋणों को दिशानिर्देशों के एक सामान्य सेट द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए, भले ही उन्हें कोई भी दे।

सलाहकार दस्तावेज के प्रमुख प्रस्ताव हैं

- सभी विनियमित संस्थाओं के लिए सूक्ष्म वित्त ऋण की एक सामान्य परिभाषा।

- ब्याज दर के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं होगी। सूक्ष्म ऋणों के लिए कोई संपार्श्विक अनुमति नहीं होगी।
- विनियमित संस्थाओं की वेबसाइटों पर सूक्ष्म वित्त ऋणों पर लगाए गए न्यूनतम, अधिकतम और औसत ब्याज दरों का प्रदर्शन।

माइक्रोफाइनेंस इंस्टीट्यूशन (MFI) के बारे में

- माइक्रोफाइनेंस वित्तीय सेवा का एक रूप है जो गरीब और कम आय वाले परिवारों को छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है।
- MFI वित्तीय कंपनियां हैं जो ऐसे लोगों को छोटे ऋण प्रदान करती हैं जिनके पास बैंकिंग सुविधाओं तक पहुंच नहीं है।
- भारत में, सभी ऋण जो 1 लाख रूपये को सूक्ष्म ऋण माना जाता है।
- NBFC-MFI और अन्य NBFC के बीच अंतर यह है कि जहां NBFC बहुत उच्च स्तर पर काम कर सकते हैं, वहीं MFI केवल छोटे सामाजिक स्तर को पूरा करते हैं, जिसमें ऋण के रूप में छोटी राशि की आवश्यकता होती है।

प्रवर्तन निदेशालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधियों की संपत्ति हस्तांतरित की

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - मनी लॉन्ड्रिंग

सुर्खिओ में क्यों-

- प्रवर्तन निदेशालय ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 8,441.50 करोड़ रूपये की संपत्ति हस्तांतरित की है, विजय माल्या, नीरव मोदी तथा मेहुल चौकसी द्वारा कथित तौर पर की गई धोखाधड़ी के कारण 22,585.83 करोड़ रूपये का नुकसान हुआ है।
- इन तीनों को मुंबई में PMLA (धन शोधन निवारण अधिनियम) न्यायालय द्वारा 'भगोड़ा आर्थिक अपराधी' घोषित किया गया है।

भगोड़े आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के बारे में

- यह उन आर्थिक अपराधियों की संपत्तियों को जब्त करने का प्रयास करता है जो आपराधिक मुकदमे का सामना करने से बचने के लिए देश छोड़ चुके हैं या अभियोजन का सामना करने के लिए देश लौटने से इनकार करते हैं।
- भगोड़ा आर्थिक अपराधी (FEO)
    - एक ऐसा व्यक्ति जिसके खिलाफ अनुसूची में दर्ज किसी अपराध के संबंध में गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है और इस अपराध का मूल्य कम-से-कम 100 करोड़ रुपए है।
- अधिनियम में सूचीबद्ध कुछ अपराध हैं:
    - नकली सरकारी स्टाम्प या करेंसी बनाना,
    - चेक अस्वीकृत करना
    - मनी लॉन्ड्रिंग
    - क्रेडिटर्स के साथ धोखाधड़ी वाले लेनदेन करना,

धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के बारे में

- मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास और जुर्माना के साथ दंडनीय है।
- भ्रष्ट संपत्ति को "अपराध की आय" माना जाता है और इसे 180 दिनों के लिये अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है।
- इस तरह के आदेश की पुष्टि एक स्वतंत्र न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा की जानी चाहिये।
- प्रवर्तन निदेशालय (ED) PMLA के तहत अपराधों की जाँच के लिये ज़िम्मेदार है।

प्रवर्तन निदेशालय के बारे में

- यह एक विशेष वित्तीय जांच एजेंसी है।
- यह राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है।
- ईडी निम्नलिखित कानूनों को लागू करता है:
    - विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (FEMA)
    - धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (PMLA)

क्या आप जानते हैं?

- मनी लॉन्ड्रिंग का अभिप्राय अवैध रूप से अर्जित आय को छिपाना या बदलना है ताकि वह वैध स्रोतों से उत्पन्न प्रतीत हों।

लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दरें

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- सरकार जुलाई-सितंबर तिमाही के लिए छोटी बचत योजनाओं पर ब्याज दरों में कटौती कर सकती है।
- इस समय छोटी बचत दरों में कटौती से मुद्रास्फीति में वृद्धि के बीच परिवारों को और नुकसान होगा।

लघु बचत योजनाओं/उपकरणों के बारे में

- ये भारत में घरेलू बचत के प्रमुख स्रोत हैं और इसमें 12 उपकरण/प्रपत्र (Instrument) शामिल हैं।
- जमाकर्त्ताओं को उनके धन पर सुनिश्चित ब्याज मिलता है।
- सभी लघु बचत प्रपत्रों से संग्रहीत राशि को राष्ट्रीय लघु बचत कोष (NSSF) में जमा किया जाता है।
- छोटी बचतें सरकारी घाटे के वित्तपोषण के एक प्रमुख स्रोत के रूप में उभरी हैं।

लघु बचत साधनों को इस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है

- डाक जमा जिसमें बचत खाता, आवर्ती जमा, अलग-अलग परिपक्वता की सावधि जमा और मासिक आय योजना शामिल है।
- **बचत प्रमाणपत्र:** राष्ट्रीय लघु बचत प्रमाणपत्र (NSC) और किसान विकास पत्र (KVP)।
- **सामाजिक सुरक्षा योजनाएँ:** सुकन्या समृद्धि योजना, लोक भविष्य निधि (PPF) और वरिष्ठ नागरिक बचत योजना (SCSS)।

कृषि

बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (CDP) हाल ही में शुरू किया गया।
- **उद्देश्य:** बागवानी के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए,
- **द्वारा शुरू किया गया:** कृषि मंत्रालय

महत्वपूर्ण तथ्य

- प्रायोगिक (Pilot) चरण में, कार्यक्रम को 11 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को कवर करते हुए 12 बागवानी समूहों में लागू किया जाएगा।
- यह एक केंद्रीय क्षेत्र का कार्यक्रम है।
- **द्वारा कार्यान्वित:** कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (NHB)।
- **उद्देश्य:** पहचान किए गए बागवानी समूहों को विकसित करना ताकि उन्हें विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके।
- इस कार्यक्रम से लगभग 10 लाख किसानों को लाभ होगा।

अन्य संबंधित तथ्य

बागवानी फसलों में शामिल हैं:

- पेड़, झाड़ी और बारहमासी बेल फल;
- बारहमासी झाड़ी और पेड़ के नट;
- कटे हुए फूल, गमले में लगे सजावटी पौधे, और क्यारी वाले पौधे (जिसमें वार्षिक या बारहमासी पौधे शामिल हैं); तथा
- वृक्षों, झाड़ियों, टर्फ और सजावटी घासों को नर्सरी में भूनिर्माण में उपयोग के लिए या फलों के बागों या अन्य फसल उत्पादन इकाइयों की स्थापना के लिए प्रचारित और उत्पादित किया जाता है।

संबंधित आलेख

ADB, भारत ने हिमाचल प्रदेश में बागवानी का समर्थन करने के लिए 10 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
एग्रो ब्रेन ड्रेन को रोकना।

बीज मिनीकिट कार्यक्रम का शुभारंभ

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- बीज मिनीकिट कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया गया।
- **द्वारा शुरू किया गया:** कृषि मंत्रालय
- दलहन और तिलहन के बीजों की अधिक उपज देने वाली किस्मों से युक्त बीज मिनीकिट किसानों को वितरित किए गए।
- यह पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है।

कार्यक्रम के लाभ

- यह किसानों के खेतों में नई किस्मों के बीजों को लाने का एक प्रमुख साधन है।
- इसका वितरण निःशुल्क है

किट कौन उपलब्ध करा रहा है?

- केंद्रीय एजेंसियां राष्ट्रीय बीज निगम (NCS), नेफेड और गुजरात राज्य बीज निगम

मॉडल किरायेदारी अधिनियम

संदर्भ: 2019 में मसौदा जारी करने के बाद, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत में संपत्ति किराए पर लेने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और संपत्ति क्षेत्र में किराया अर्थव्यवस्था की सहायता के लिए मॉडल किरायेदारी अधिनियम (MTA) को मंजूरी दे दी है।

यह अधिनियम क्यों?

- **प्रतिबंधात्मक कानून:** वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, देश भर में लगभग 1.1 करोड़ मकान खाली थे। मौजूदा किराया नियंत्रण कानून किराये के आवास के विकास को प्रतिबंधित कर रहे हैं और मालिकों को अपने खाली मकानों को फिर से कब्जा करने के डर से किराए पर देने से हतोत्साहित करते हैं।
- **क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अनौपचारिकीकरण:** खाली घर को अनलॉक करने के संभावित उपायों में से एक है परिसर को किराए पर देने की मौजूदा प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना और संपत्ति के मालिक और किरायेदार दोनों के हितों को विवेकपूर्ण तरीके से संतुलित करना।
- **एकरूपता का अभाव:** चूंकि यह राज्य का विषय है, इसलिए राज्यों ने अपने कानून बनाए हैं और यह एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न होता है।

यह कहाँ लागू होता है-

- इस अधिनियम के लागू होने के बाद, कोई भी व्यक्ति लिखित में अनुबंध के अलावा किसी भी परिसर को किराए पर नहीं ले सकता है।
- नया अधिनियम संभावित रूप से लागू होगा और मौजूदा किरायेदारी को प्रभावित नहीं करेगा।
- यह मॉडल अधिनियम शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगा।

प्रारूप मॉडल किरायेदारी अधिनियम में नया क्या है?

- **समर्पित संस्थान:** विवादों के त्वरित समाधान के लिए राज्य एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करेंगे जिसमें रेंट अथॉरिटी, रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल शामिल होंगे।
- **समयबद्ध समाधान:** रेंट कोर्ट और रेंट ट्रिब्यूनल द्वारा शिकायत/अपील का निपटारा 60 दिनों के भीतर अनिवार्य होगा।
- **किराए पर कोई मौद्रिक सीमा नहीं:** वर्तमान में, पुरातन किराया-नियंत्रण अधिनियमों के तहत किराए पर दी गई कई पुरानी संपत्तियों में, इस तरह की उच्चतम सीमा ने जमींदारों को पुरानी किराए की राशि के साथ फंसा दिया है। नए मॉडल एक्ट में इसे खत्म कर दिया जाएगा।
- **निष्कासन के लिए प्रावधान:** रेंट कोर्ट, मकान मालिक द्वारा नोटिस दिए जाने के बाद, यदि किरायेदार परिसर का दुरुपयोग करता है, तो मकान मालिक द्वारा कब्जा करने की अनुमति दे सकता है। परिसर के दुरुपयोग, जैसा कि परिभाषित है, कि सार्वजनिक उपद्रव, क्षति या "अनैतिक या अवैध उद्देश्यों" के लिए इसका उपयोग शामिल है।

मॉडल किरायेदारी अधिनियम (MTA) के गुण

- किराये के आवास के छाया बाजार को औपचारिक बनाना।
- किरायेदार और मालिक दोनों के हितों की रक्षा करता है।

- पारदर्शिता और अनुशासन बढ़ाएँ।
- इस क्षेत्र में निजी निवेश को आकर्षित करता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भूमि पट्टे में सुधार की आवश्यकता
- आदर्श कृषि भूमि पट्टेदारी अधिनियम

क्या 'लाभदायक' MSPs ग्रामीण मांग को बढ़ा रहे हैं?

संदर्भ: 9 जून को, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021-22 खरीफ विपणन सत्र के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को मंजूरी दी।

- धान का MSPs 1940 रूपये प्रति क्विंटल होगा, जबकि पिछले साल यह 1868 रूपये था।
- आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (CCEA) का कहना है कि नवीनतम MSPs 2021-22 में खेती की अनुमानित लागत से 50% अधिक अंक प्रदान करता है।

MSPs की गणना में प्रयुक्त लागत उपाय

A2	फसल उत्पन्न करने के लिए सभी प्रकार के नकद व्यय जैसे बीज, खाद, रसायन, श्रम लागत, ईंधन लागत और सिंचाई लागत।
A2+FL (सरकार द्वारा प्रयुक्त)	(सरकार द्वारा प्रयुक्त) इसमें A2 प्लस न चुकाया हुआ पारिवारिक श्रम का आरोपित मूल्य शामिल है।
C2 (किसानों की मांग)	इसमें A2+FK और स्वामित्व वाली भूमि का अनुमानित किराये का मूल्य और स्वामित्व वाली अचल पूंजी के मूल्य पर ब्याज शामिल है, जिससे कृषि अभ्यास की अवसर लागत शामिल है।

मुद्दे :

1. हाल के वर्षों में MSPs में नाममात्र की वृद्धि कम रही है

- हालांकि सरकार का दावा है कि नवीनतम MSPs घोषणाएं A2+FL मानदंड पर 50% मार्क-अप को पूरा करती हैं, नाममात्र की शर्तों में वृद्धि ज्यादा नहीं है।
- 2021-22 के खरीफ और रबी विपणन सीजन के लिए धान और गेहूं के MSPs में क्रमशः 3.9% और 2.6% की वृद्धि हुई है।

2. नाममात्र की MSPs मांग प्रभाव तक पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं हैं-

- MSPs, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसानों द्वारा प्राप्त कीमतों को प्रभावित करते हैं।
- दूसरी ओर यह मांग क्रय शक्ति का एक कार्य है, जो सापेक्ष कीमतों से निर्धारित होता है।
- धान और गेहूँ की खेती की लागत का 60% से अधिक और लगभग एक-तिहाई A2+FL की मजदूरी है। ग्रामीण मजदूरी, जो 2014-15 तक तेज गति से बढ़ रही थी, हाल के दिनों में यह स्थिर हो गई है।
- यदि कृषि श्रमिक और किसान आय (ग्रामीण मजदूरी का आरोपित मूल्य) पर दबाव का अनुभव करते हैं, तो यह क्रय शक्ति और इसलिए किसानों सहित कुल मांग के ग्रामीण घटक पर दबाव डालेगा।

3. भविष्य में प्रतिकूलता

- आगे चलकर दो कारक किसानों के लिए व्यापार की शर्तों को और खराब कर सकते हैं।
- श्रम बाजार के मामले में कृषि क्षेत्र सदमे अवशोषक है और गैर-कृषि श्रम बाजार को ठीक होने में जितना अधिक समय लगेगा, कृषि क्षेत्र के लिए आय को कम करना उतना ही कठिन होगा।

सरकार को आगे क्या करना चाहिए?

- यह सोचना अवास्तविक है कि गैर-कृषि क्षेत्र संकट में होने पर भी कृषि अर्थव्यवस्था फलती-फूलती रहेगी।
- इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि सरकार कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों के श्रम प्रधान घटक को वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- अधिशेष के युग में MSP
- नए कृषि अधिनियम
- पिछले कुछ वर्षों में कृषि-विपणन नीति कैसे बदली है
- किसान की आय दोगुनी करने पर अशोक दलवई समिति
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम

धान, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खिओ में क्यों-

- केंद्र सरकार ने फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए धान, दलहन और तिलहन के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि की है।
- MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है।
    - यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।

MSP के तहत फसलें

- कृषि लागत और मूल्य आयोग (MSP) 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP और गन्ने के लिए उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) की सिफारिश करता है।
    - CACP कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
- अनिवार्य फसलों में खरीफ मौसम की 14 फसलें, 6 रबी फसलें और 2 अन्य वाणिज्यिक फसलें शामिल हैं।
- तोरिया और छिलके वाले नारियल के MSP क्रमशः रेपसीड/सरसों और खोपरा के FRP के आधार पर तय किए जाते हैं।

CACP, MSP कैसे तय करता है?

- **यह ध्यान में रखता है:**
    - वस्तु के लिए आपूर्ति और मांग की स्थिति
    - बाजार मूल्य रुझान (घरेलू और वैश्विक)
    - उपभोक्ताओं के लिए प्रभाव (मुद्रास्फीति)
    - पर्यावरण (मिट्टी और पानी का उपयोग)
    - कृषि और गैर-कृषि क्षेत्रों के बीच व्यापार की शर्तें।

MSP वृद्धि का महत्व

- पोषक तत्वों से भरपूर अनाज पर ध्यान केंद्रित करने से उन क्षेत्रों में इसके उत्पादन को प्रोत्साहन मिलेगा जहां चावल-गेहूं नहीं उगाए जा सकते।

- तिलहन, दलहन और मोटे अनाज के पक्ष में वास्तविक MSP किसानों को इन फसलों की ओर उत्पादन स्थानांतरित करने के लिए प्रोत्साहित करेगा।

- **हाइक (Hike) के साथ समस्याएं**
  - खेती की लागत और मुद्रास्फीति की तुलना में मामूली वृद्धि
  - सुनिश्चित खरीद के अभाव के कारण फसलों की खेती के लिए कोई प्रोत्साहन नहीं मिला।

संबंधित आलेख:

- MSP-फैक्टिड्स बनाम तथ्य
- नए कृषि विधेयक और इसका विरोध

गेहूं और चावल में पोषक तत्वों की हानि: ICAR अध्ययन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- स्वास्थ्य और जीएस -III- कृषि

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (ICAR) और विधान चंद्र कृषि विश्वविद्यालय के तहत विभिन्न संस्थानों के शोधकर्ताओं ने पाया कि भारत में चावल और गेहूँ की खेती में 'जस्ता और लोहे' की मात्रा में कमी आई है।
  - जस्ता और लौह की कमी वैश्विक स्तर पर अधिकतर लोगों को प्रभावित करती है और ऐसी कमी वाले देशों में मुख्य रूप से चावल, गेहूँ, मक्का तथा जौ से बने आहार प्रचलित होते हैं।

अध्ययन के निष्कर्ष

- **चावल और गेहूं में जस्ते की सांद्रता:**
  - **चावल के लिए:** वर्ष 1960 के दशक में जारी चावल की किस्मों के अनाज में जस्ता की सांद्रता 59.8 मिलीग्राम / किग्रा. थी। यह 2000 के दशक में 43.1 मिलीग्राम/किग्रा. तक कम हो गया।
  - गेहूँ में, जस्ता की सांद्रता 33.3 मिलीग्राम/किग्रा., 1960 के दशक के दौरान जारी की गई किस्मों में 23.5 मिलीग्राम/किग्रा. तक गिर गई है।

- **चावल और गेहूं में लौह सांद्रता:**
  - **चावल के लिए:** वर्ष 1960 के दशक में जारी चावल की किस्मों के अनाज में जस्ता की सांद्रता 59.8 मिलीग्राम / किग्रा. थी। यह 2000 के दशक में 43.1 मिलीग्राम/किग्रा. तक कम हो गया।
  - गेहूं में, 1960 के दशक की किस्मों में आयरन की सांद्रता 57.6 मिलीग्राम/किलोग्राम, 2010 के दौरान जारी की गई किस्मों में 46.4 मिलीग्राम/किलोग्राम तक गिर गई।

- कल्टीवेटर (cultivar) एक पौधे की किस्म है जिसे चयनात्मक प्रजनन द्वारा खेती में उत्पादित किया गया है।

कमी का कारण

- 'कमजोर पड़ने वाला प्रभाव' जो उच्च अनाज उपज की प्रतिक्रिया में पोषक तत्वों की कमी के कारण होता है।
  - इसका मतलब है कि उपज में वृद्धि की दर पौधों द्वारा पोषक तत्व ग्रहण की दर से प्रतिपूर्ति नहीं की जाती है।
- साथ ही, मिट्टी को सहारा देने वाले पौधे, पौधों के लिए उपलब्ध पोषक तत्वों में कम हो सकते हैं।

सुझाव

- भविष्य के बीज कार्यक्रमों में किस्मों को जारी करते हुए 'अनाज आयनोम', अर्थात पोषण संबंधी पैटर्न, में सुधार करके इन नकारात्मक प्रभावों को दूर करने की आवश्यकता है।
- हमें बायोफोर्टिफिकेशन जैसे अन्य विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जहां हम सूक्ष्म पोषक तत्वों से भरपूर खाद्य फसलों का प्रजनन करते हैं।
    - बायोफोर्टिफिकेशन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कृषि संबंधी प्रथाओं, पारंपरिक पौधों के प्रजनन, या आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से खाद्य फसलों की पोषण गुणवत्ता में सुधार किया जाता है।

भारत द्वारा की गई पहल

- हाल ही में, प्रधान मंत्री ने 8 फसलों की 17 बायोफोर्टिफाइड किस्मों को राष्ट्र को समर्पित किया।
- **कुछ उदाहरण:**
    - चावल-CR DHAN 315 में जिंक की अधिकता होती है।
    - गेहूं- HI 1633 प्रोटीन, आयरन और जिंक से भरपूर।
    - मक्का- 1, 2 और 3 की संकर किस्में लाइसिन और ट्रिप्टोफैन से समृद्ध होती हैं।
- मधुबन गाजर, एक बायोफोर्टिफाइड गाजर किस्म है जिसमें बीटा-कैरोटीन और आयरन की मात्रा अधिक होती है।
- कृषि को पोषण से जोड़ने वाली पारिवारिक खेती को बढ़ावा देने के लिए ICAR ने पोषक संवेदनशील कृषि संसाधन और नवाचार (NARI) कार्यक्रम शुरू किया है।

उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए बायोटेक-किसान कार्यक्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III-विज्ञान और तकनीक; कृषि

सुर्खिओ में क्यों-

- विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने 'बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क' (बायोटेक-किसान) मिशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिये एक विशेष आह्वान जारी किया है।
- **उद्देश्य:** NER किसानों की स्थानीय समस्याओं को समझना और उन समस्याओं का वैज्ञानिक समाधान प्रदान करना।

विशेष कॉल का कारण

- 'बायोटेक-कृषि इनोवेशन साइंस एप्लीकेशन नेटवर्क' कार्यक्रम के तहत वर्तमान आह्वान विशेष रूप से पूर्वोतर क्षेत्र पर केंद्रित है, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से कृषि प्रधान है और इसका 70 प्रतिशत कार्यबल कृषि और संबद्ध क्षेत्र में संलग्न है।

विशेष कॉल के बारे में

- **उद्देश्य:** उपलब्ध नवीन कृषि प्रौद्योगिकियों को छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से क्षेत्र की महिला किसानों के साथ खेत से जोड़ना।

बायोटेक-किसान के बारे में

- यह कृषि नवाचार के लिए 2017 में शुरू की गई एक वैज्ञानिक-किसान साझेदारी योजना है।
- **उद्देश्य:** कृषि स्तर पर लागू किए जाने वाले नवीन समाधानों और प्रौद्योगिकियों का पता लगाने के लिए विज्ञान प्रयोगशालाओं को किसानों से जोड़ना।
- **प्रगति:**

- देश के सभी 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों और 110 आकांक्षी ज़िलों को कवर करते हुए 146 बायोटेक-किसान हब स्थापित किये गए हैं।
- इस योजना ने अब तक दो लाख से अधिक किसानों को उनके कृषि उत्पादन और आय में वृद्धि करके लाभान्वित किया है।
- 200 से अधिक उद्यमिता ग्रामीण क्षेत्रों में भी विकसित की गई हैं।

- **मंत्रालय:** जैव प्रौद्योगिकी विभाग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय।

नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल का ई-लॉन्च किया जाएगा

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III- अर्थव्यवस्था; कृषि

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने नेफेड फोर्टिफाइड राइस ब्रान ऑयल (पुष्टिकारक चावल की भूसी का तेल) का ई-लॉन्च किया है।

चावल की भूसी के तेल के बारे में

- पुष्टिकारक चावल की भूसी का तेल चावल की कठोर बाहरी भूरी परत से निकाला गया तेल है जिसे भूसा (चावल की भूसी) कहा जाता है।
- पुष्टिकारक चावल की भूसी के तेल की संरचना मूंगफली के तेल के समान होती है।

स्वास्थ्य सुविधाएं

- कम ट्रांस-वसा सामग्री और उच्च मोनोअनसैचुरेटेड और पॉलीअनसेचुरेटेड वसा सामग्री के कारण कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करना।
- यह एक बूस्टर के रूप में भी काम करता है और इसमें विटामिन-E की उच्च मात्रा के कारण कैंसर के खतरे को कम करता है।
- WHO द्वारा अन्य खाद्य तेलों के सर्वोत्तम विकल्प के रूप में इसकी सिफारिश की जाती है।

नेफेड (NAFED) के बारे में

- भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (NAFED) भारत में कृषि उत्पादों के विपणन सहकारी समितियों का एक शीर्ष संगठन है।
- इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को हुई थी।
- यह बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है।
- **मुख्यालय:** नई दिल्ली
- **मंत्रालय:** कृषि मंत्रालय

पर्यावरण/प्रदूषण

'ब्लैक कार्बन' (Black Carbon) पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - संरक्षण; जलवायु परिवर्तन

सुर्खिओ में क्यों-

- "हिमालय के ग्लेशियर: जलवायु परिवर्तन, ब्लैक कार्बन और क्षेत्रीय लचीलापन" शीर्षक वाली एक रिपोर्ट में कहा गया है कि ये ग्लेशियर 'वैश्विक औसत बर्फ द्रव्यमान' की तुलना में तेज़ी से पिघल रहे हैं।
- हालाँकि ब्लैक कार्बन से संबंधित मज़बूत नीति ग्लेशियरों के पिघलने की प्रक्रिया को तेज़ी से रोक सकती है।
- **रिपोर्ट जारी की गई:** विश्व बैंक
- यह रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी की गई है और इसमें हिमालय, काराकोरम और हिंदूकुश (HKHK) पर्वत शृंखलाएँ शामिल हैं।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- ब्लैक कार्बन (BC) एक अल्पकालिक प्रदूषक है
    - जो कार्बन डाइऑक्साइड (CO_2) के बाद ग्रह को गर्म करने में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्त्ता है।
    - अन्य ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के विपरीत BC जल्दी से धुल जाता है और अगर इसका उत्सर्जन बंद हो जाता है तो इसे वातावरण से समाप्त किया जा सकता है।
- कुल ब्लैक कार्बन में उद्योग (मुख्य रूप से ईंट भट्टे) और ठोस ईंधन जलने से क्षेत्रीय मानवजनित BC के उत्सर्जन का 45-66% हिस्सा होता है, इसके बाद क्षेत्र में ऑन-रोड डीजल ईंधन और खुले में ईंधन जलाने से ब्लैक कार्बन का उत्सर्जन होता है।
- यह ग्लेशियर के पिघलने की गति को तेज करने के लिए दो तरह से कार्य करता है:
    - सूर्य के प्रकाश के सतही परावर्तन को कम करके।
    - हवा का तापमान बढ़ाकर।
- BC को कम करने के लिये मौजूदा नीतियों का पूर्ण कार्यान्वयन इसमें 23% की कमी कर सकता है लेकिन नई नीतियों को लागू करने और देशों के बीच क्षेत्रीय सहयोग के माध्यम से उन्हें शामिल करने से अधिक लाभ प्राप्त हो सकता है।
    - सतत हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने पर राष्ट्रीय मिशन (NMSHE) भारत में अपनाई गई ऐसी ही एक नीति है।
- यह जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (NAPCC) के तहत आठ मिशनों में से एक है।
- हिमालय में उठाए गए कदम
    - निम्न से ब्लैक कार्बन उत्सर्जन कम करें-(1) चूल्हे; (2) डीजल इंजन; (3) खुला में जलना। यह विकिरणकारी बल को काफी कम कर सकता है।
- क्षेत्रीय सरकारों द्वारा उठाए गए कदम
    - जल प्रबंधन पर नीतियों की समीक्षा करना
    - जल प्रवाह और उपलब्धता में परिवर्तन को प्रतिबिंबित करने के लिए जलविद्युत की सावधानीपूर्वक योजना और उपयोग।
    - प्रमाणित प्रौद्योगिकियों के माध्यम से ईंट भट्टों की दक्षता बढ़ाना।
    - इस क्षेत्र से संबंधित अधिक-से-अधिक ज्ञान का साझाकरण भी होना चाहिये।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- HKHK पहाड़ों में लगभग 55,000 हिमनद हैं जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बाहर किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में अधिक मीठे पानी का भंडारण हैं।
- ग्लेशियर पिघलता है
    - फ्लैश फ्लड
    - भूस्खलन
    - मृदा अपरदन
    - ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड (GLOF)
- विकिरण बल वैश्विक ऊर्जा संतुलन को प्रभावित करने और जलवायु परिवर्तन में योगदान करने के लिये एक मज़बूर एजेंट (जैसे- ग्रीनहाउस गैसों, एयरोसोल, क्लाउड और सतही एल्बीदडो) में परिवर्तन के परिणामस्वरूप ऊर्जा संतुलन में परिवर्तन का एक उपाय है।

भारतीय शहरों के लिए हरित भविष्य

संदर्भ: शहरी विकास का एक प्रगतिशील ट्रैक स्थिरता, आपदा जोखिम लचीलापन और सामुदायिक निर्माण को अपने मूल में रखते हुए भारत में शहरी विकास के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत रहा है।
आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के निम्नलिखित राष्ट्रीय कार्यक्रमों और मिशनों ने जलवायु परिवर्तन को कम करने और भारत को हरित शहरों की ओर बढ़ने में मदद की है।

स्वच्छ भारत मिशन (शहरी)

- यह योजना खुले में शौच मुक्त भारत प्राप्त करने, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षमता के निर्माण और व्यवहार में बदलाव लाने पर केंद्रित है।
- वास्तव में, यह हमारे शहरी परिदृश्य के कुल परिवर्तन का अग्रदूत था।

स्मार्ट सिटीज मिशन

- शासन, स्थिरता और आपदा जोखिम लचीलापन में सुधार के लिए हमारे शहरों की तकनीकी प्रगति का प्रभार लेने वाला यह मिशन रहा है।

कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (अमृत)

- अमृत योजना के तहत, 500 लक्षित शहरों में जल आपूर्ति और प्रबंधन, ऊर्जा दक्षता और बढ़ी हुई हरित जगहें लक्ष्य का हिस्सा रही हैं।
- इस मिशन के परिणामस्वरूप 2022 तक GHG उत्सर्जन के बराबर 48.52 मिलियन टन CO2 को कम करने की संभावना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)

- 1.12 करोड़ घरों की मंजूरी के साथ, PMAY(U) ने नई निर्माण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित किया है जो अभिनव, पर्यावरण के अनुकूल और आपदा-लचीले हैं।
- ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज शुरू किया गया था और 54 नई प्रौद्योगिकियों की पहचानकर निर्माण में शामिल किया गया।
- लगभग 43.3 लाख घरों का निर्माण किया जा रहा है जहां फ्लाई ऐश ईंटों/ब्लॉकों और कंक्रीट ब्लॉकों का उपयोग किया जा रहा है।

- कुल मिलाकर, मिशन में 2022 तक GHG उत्सर्जन के लगभग 12 मिलियन टन CO2 समकक्ष को कम करने की क्षमता है।

सार्वजनिक परिवहन- मेट्रो

- अंत में, मेट्रो रेल, एक ऊर्जा-कुशल जन रैपिड ट्रांजिट सिस्टम, 18 शहरों में चालू है, जिसमें 720 किमी से अधिक लाइन का निर्माण किया गया है।
- 27 शहरों में 1,055 किलोमीटर नई लाइनों का निर्माण किया जा रहा है।
- इस नेटवर्क से 2015-2022 तक लगभग 21.58 मिलियन टन CO2 eq GHG को कम करने की उम्मीद है।

निष्कर्ष

- संचयी रूप से, MoHUA के तहत राष्ट्रीय मिशनों को 2022 तक 93 मिलियन टन CO2 के बराबर GHG उत्सर्जन को कम करने का अनुमान है। यह संख्या बढ़ना तय है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस जलवायु समझौता
- शीर्ष तीन SDGs और भारत

हिंदू कुश हिमालय पर्वत पर UNDP रिपोर्ट

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - जलवायु परिवर्तन; संरक्षण

सुर्खिओ में क्यों-

- UNDP (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) की रिपोर्ट के अनुसार, 'पिघलते ग्लेशियर; आजीविका के लिए खतरा; तीसरे ध्रुव को बचाने के लिए जलवायु परिवर्तन का सामना', हिंदू कुश हिमालयन (HKH) पर्वत श्रृंखलाएं 2100 तक अपनी दो-तिहाई बर्फ से विहीन सकती हैं।
- वर्ष 2100 तक लगभग 2 अरब लोगों को भोजन, पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है।
- HKH क्षेत्र में ग्लेशियर के पिघलने का कारण है:
    - वायुमंडल के बड़े मानवजनित संशोधन
    - ग्लोबल वार्मिंग के कारण मौसम के मिजाज और वर्षा में व्यवधान
    - ग्लेशियर की मात्रा में परिवर्तन
    - अनियोजित शहरीकरण

प्रभाव

- जलवायु के साथ-साथ मानसून के पैटर्न के लिए भी खतरा है।
- यह 10 प्रमुख नदी प्रणालियों को प्रभावित करता है जो कृषि गतिविधियों में मदद करती हैं, ये क्षेत्र में पेयजल और जल विद्युत उत्पादन प्रदान करती हैं।
- सामाजिक-आर्थिक व्यवधान और मानव विस्थापन।

अनुशंसा

- ऊर्जा परिवहन और अन्य क्षेत्रों में जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर जाना।
- ग्रीनहाउस गैसों के शुद्ध शून्य उत्सर्जन की ओर बढ़ने के लिए आहार और कृषि पद्धतियों को बदलना।
- डेटा और सूचना क्षमता निर्माण और पूर्व चेतावनी प्रणाली में सुधार करना।

अन्य सम्बंधित तथ्य

- HKH 8 देशों में फैला हुआ है- अफगानिस्तान, भूटान, बांग्लादेश, चीन, भारत म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान।
- इसमें अंटार्कटिका और आर्कटिका के बाद जमे हुए पानी का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा भंडारण है।
- इसे विश्व का तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है।

जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन (NMBHWB)

संदर्भ: जैव विविधता का संरक्षण हमारे लोगों की सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय कल्याण हेतु आवश्यक है।

- अनुमानों से पता चलता है कि अकेले हमारे वनों से प्रति वर्ष एक खरब रुपये से अधिक की सेवाओं का उत्पादन कर सकते हैं। इसके अलावा यह कल्पना की जा सकती है कि घास के मैदानों, आर्द्रभूमि, मीठे पानी और समुद्र जैसे प्राकृतिक संसाधनों द्वारा उत्पादित सेवाओं को जोड़ लिया जाए तो इसका मूल्य कितना बढ़ जाएगा।

जैव विविधता और मानव कल्याण पर राष्ट्रीय मिशन की मुख्य विशेषताएं (NMBHWB)

- **सतत उपयोग :** यह मिशन भारत की प्राकृतिक विरासत को पुनर्स्थापित करने, संरक्षित करने और स्थायी रूप से उपयोग करने के विज्ञान को मजबूत करेगा
- **विकास में एकीकरण :** यह मिशन सभी विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से कृषि, पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं, स्वास्थ्य, जैव-अर्थव्यवस्था और जलवायु परिवर्तन शमन में जैव विविधता को एक प्रमुख विचार के रूप में शामिल करेगा;
- इस मिशन के "एक स्वास्थ्य" कार्यक्रम में, मानव स्वास्थ्य को पशु, पौधे, मिट्टी और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के साथ एकीकृत करते हुए, अप्रत्याशित सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौतियों के लिए हस्तक्षेप क्षमता के साथ-साथ भविष्य की महामारियों को कम करने के लिए निवारक क्षमता दोनों हैं।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- पेरिस समझौता
- सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन (NMSA)

मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस-III - संरक्षण

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में भारतीय प्रधान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र (UN) "मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे पर उच्च स्तरीय वार्ता" को संबोधित किया।

भूमि क्षरण से निपटने के लिए भारत द्वारा उठाए गए कदम

- भारत, भूमि अवक्रमण तटस्थता (LDN) (सतत विकास लक्ष्य लक्ष्य 15.3) पर अपनी राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को प्राप्त करने की राह पर है।
- भारत वर्ष 2030 तक 26 मिलियन हेक्टेयर बंजर भूमि की बहाली के लिये कार्य कर रहा है।
- भूमि क्षरण के मुद्दों के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जा रहा है।
    - यह भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद में है।

भूमि क्षरण क्या है और इसका प्रभाव क्या है?

- भूमि क्षरण कई मजबूती का कारण होता है, जिसमें उच्च मौसम की स्थिति, विशेष रूप से सूखा और मानवीय गतिविधियाँ शामिल हैं जो मिट्टी और भूमि उपयोगिता की गुणवत्ता को प्रदूषित या ख़राब करती हैं।

- यह सूखे, जंगल की आग, अनैच्छिक प्रवास और जूनोटिक संक्रामक रोगों के उद्भव को जोड़ता है।

भूमि क्षरण को रोकने के वैश्विक प्रयास

- **मरुस्थलीकरण का सामना करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCCD):** एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतरराष्ट्रीय समझौता
- **द बॉन चैलेंज :** इसके तहत वर्ष 2020 तक विश्व के 150 मिलियन हेक्टेयर गैर-वनीकृत एवं बंजर भूमि पर और वर्ष 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर भूमि पर वनस्पतियाँ उगाई जाएंगी।
- **ग्रेट ग्रीन वॉल :** यह ग्लोबल एन्वायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) की पहल है जहाँ साहेल-सहारन अफ्रीका के ग्यारह देशों ने भूमि क्षरण के खिलाफ लड़ने और देशी पौधों के पुनर्जीवन के प्रयासों पर ध्यान केंद्रित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट 'चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट'

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III -ई-कचरे

सुर्खिओ में क्यों-

- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने अपनी हालिया रिपोर्ट "चिल्ड्रन एंड डिजिटल डंपसाइट्स" में उस खतरे पर प्रकाश डाला है जो अनौपचारिक प्रसंस्करण में काम करने वाले बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों या ई-कचरे के कारण सामना करना पड़ रहा है।
    - यह इलेक्ट्रॉनिक अपशिष्ट और बाल स्वास्थ्य पर WHO की पहली रिपोर्ट है।
    - यह पुराने ई-कचरा, समाप्त हो चुके या बेकार हो चुके इलेक्ट्रॉनिक आइटम और उनके पुर्जों को संदर्भित करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- लगभग 12.9 मिलियन महिलाएं अनौपचारिक कचरा क्षेत्र में काम कर रही हैं जो उन्हें जहरीले ई-कचरे (जैसे निकिल, सीसा और मरकरी) के संपर्क में ला रही हैं और उनके अजन्मे बच्चों को खतरे में डाल रही हैं।

सुझाव

- ई-कचरे का पर्यावरण के अनुकूल निपटान और कामगारों की सुरक्षा।
- ई-अपशिष्ट एक्सपोजर और स्वास्थ्य परिणामों की निगरानी करें।
- ई कचरे के बेहतर उपयोग को सुगम बनाना।

क्या आप जानते हैं?

- UN ग्लोबल ई-वेस्ट मॉनिटर 2020 के अनुसार 2009 में दुनिया भर में 53.6 मिलियन मीट्रिक टन ई-कचरा उत्पन्न हुआ था।
- इसमें से केवल 17.4% ई-कचरे को एकत्र करके पुनर्चक्रित किया गया।
- चीन और अमेरिका के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक कचरा पैदा करने वाला देश है।
- 2016 में भारत ने ई-अपशिष्ट (प्रबंधन) नियम अधिनियमित किया जिसके तहत ई-अपशिष्ट को दो व्यापक श्रेणियों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है: सूचना प्रौद्योगिकी और दूरसंचार उपकरण तथा उपभोक्ता विद्युत और इलेक्ट्रॉनिक।

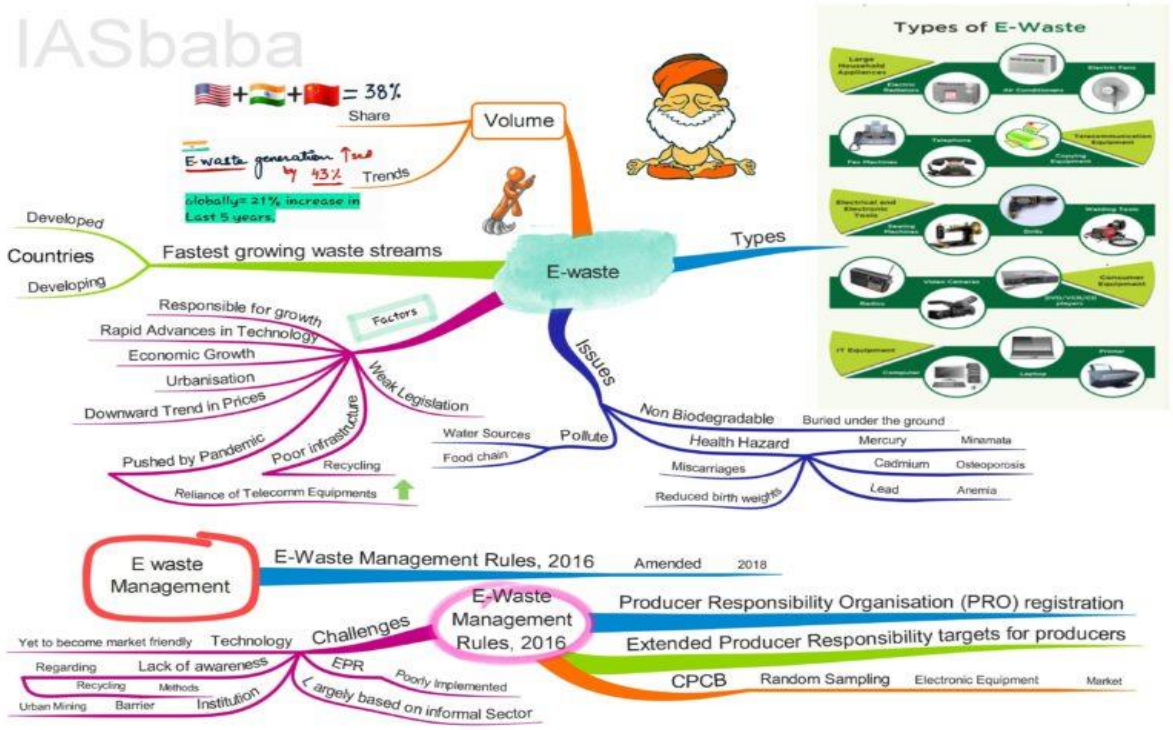

Pic courtesy: Iasbaba

अवैध एचटी बीटी (HTBt) कपास के बीज की बिक्री दोगुनी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - अर्थव्यवस्था; जैव प्रौद्योगिकी

सुर्खियों में-

- हर्बिसाइड टॉलरेंट (HT) बीटी कपास की अवैध खेती में इस साल भारी उछाल देखा गया है।
- क्योंकि अवैध बीज पैकेटों की बिक्री पिछले साल के 30 लाख से बढ़कर इस साल 75 लाख हो गई है।
- बीटी कपास एकमात्र ट्रांसजेनिक फसल है जिसे भारत में व्यावसायिक खेती के लिये केंद्र द्वारा अनुमोदित किया गया है। कपास के बोलवर्म का एक सामान्य कीट का मुकाबला करने हेतु कीटनाशक का उत्पादन करने के लिये आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) किया गया है।
- HTbt कॉटन वैरिएंट पौधे को हर्बिसाइड ग्लाइफोसेट के लिए प्रतिरोधी बनाता है।
- ग्लाइफोसेट में कार्सिनोजेनिक प्रभाव होता है और इसके परिणामस्वरूप परागण के माध्यम से पौधों के पास जड़ी-बूटियों के प्रतिरोध का प्रसार भी हो सकता है।

क्या आप जानते हैं?

- GM फसलों के अनुमोदन के लिए नियामक ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है।
- पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सर्वोच्च निकाय है जो भारत में GM फसलों के वाणिज्यिक रिलीज की अनुमति देती है।

- जैव सुरक्षा पर कार्टाजेना प्रोटोकॉल जैव सुरक्षा मूल्यांकन और पर्यावरण रिलीज सहित GM फसलों के विनियमन के लिए अच्छी तरह से परिभाषित तंत्र प्रदान करता है।

ग्रेट बैरियर रीफ को 'खतरे में' विश्व धरोहर स्थलों की सूची में जोड़ने की सिफारिश की गई

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III- जलवायु परिवर्तन

सुर्खियों में-

- हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति ने सिफारिश की है कि ऑस्ट्रेलिया के 'ग्रेट बैरियर रीफ' को विश्व धरोहर स्थलों की "खतरे की सूची' में जोड़ा जाना चाहिये।
    - इस समिति के अनुसार, जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के कारण दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति प्रणाली को 'खतरे में' सूची में जोड़ा जाना चाहिए।
- रीफ 2050 के बावजूद, गंभीर समुद्री हीटवेव के कारण कोरल रीफ पारिस्थितिकी तंत्र को वर्ष 2015 के बाद से तीन प्रमुख विरंजन घटनाओं का सामना करना पड़ा है।
    - 'रीफ 2050' लॉन्ग-टर्म सस्टेनेबिलिटी प्लान वर्ष 2050 तक ग्रेट बैरियर रीफ की सुरक्षा और प्रबंधन के लिये ऑस्ट्रेलियाई और क्वींसलैंड सरकार की व्यापक रूपरेखा है।

ग्रेट बैरियर रीफ के बारे में

- यह दुनिया का सबसे व्यापक और शानदार प्रवाल भित्ति पारिस्थितिकी तंत्र है जो 2,900 से अधिक व्यक्तिगत भित्तियों और 900 द्वीपों से बना है।
- यह चट्टान संरचना अरबों छोटे जीवों से बनी है, जिन्हें मूंगा जंतु कहा जाता है।
    - पॉलीप्स छोटे, मुलायम शरीर वाले जीव हैं।
- उनके शरीर के ऊपर एक कठोर, सुरक्षात्मक चूना पत्थर का कंकाल होता है जिसे कैलिकल कहा जाता है, जो प्रवाल भित्तियों की संरचना बनाता है।
    - इन पॉलीप्स में सूक्ष्म शैवाल होते हैं जिन्हें ज़ोक्सांथेला (zooxanthellae) कहा जाता है जो उनके ऊतकों के भीतर रहते हैं। प्रवाल और शैवाल का परस्पर (सहजीवी) संबंध होता है।
    - इसे 1981 में विश्व धरोहर स्थल के रूप में चुना गया था।

मूंगों की रक्षा के लिए पहल

- अंतर्राष्ट्रीय कोरल रीफ पहल
- ग्लोबल कोरल रीफ मॉनिटरिंग नेटवर्क (GCRMN)
- ग्लोबल कोरल रीफ एलायंस (GCRA)
- ग्लोबल कोरल रीफ आर एंड डी एक्सेलेरेटर प्लेटफार्म
- पर्यावरण और वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF & CC), भारत ने तटीय क्षेत्र अध्ययन (CZS) के तहत प्रवाल भित्तियों पर अध्ययनों को शामिल किया है।
- भारतीय प्राणी सर्वेक्षण (ZSI), गुजरात के वन विभाग की मदद से, "बायोरॉक" या खनिज अभिवृद्धि तकनीक का उपयोग करके प्रवाल भित्तियों को पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया का प्रयास कर रहा है।

- भारत में प्रवाल भित्तियों की रक्षा और उन्हें बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम।

समाचारों में प्रजातियाँ / नेशनल पार्क्स

समाचार में प्रजातियां: लिटोरिया मीरा

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - पर्यावरण; जैव विविधता

सुर्खियों में-

- मेंढक की एक प्रजाति न्यू गिनी के वर्षावनों में रहती है जो चॉकलेट से बनी प्रतीत होती है।
- कोको रंग के मेंढक एक नई प्रजाति के रूप में सामने आए हैं।
- बड़े आकार, हाथ पर बद्धी, छोटे अंग और आंखों के किनारे पर त्वचा का छोटा बैंगनी पैच।
- न्यू गिनी द्वीप टोरेस जलडमरूमध्य द्वारा क्वींसलैंड के 'सींग' से अलग किया गया है।

देहिंग पटकाई (Dehing Patkai) बना असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - राष्ट्रीय उद्यान

सुर्खियों में-

- हाल ही में असम की राज्य सरकार ने देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य (Dehing Patkai Wildlife Sanctuary) को असम का 7वां राष्ट्रीय उद्यान (National Park) घोषित किया है।
    - यह अधिसूचना असम के कोकराझार जिले में रायमोना राष्ट्रीय उद्यान की घोषणा के बाद आई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 राष्ट्रीय उद्यान हैं और इसके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान के बाद अब असम में तीसरा सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान है।
- **राज्य के पांच पुराने राष्ट्रीय उद्यान:** काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू-सैखोवा।
    - काजीरंगा और मानस यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल हैं।
    - ये नामेरी और ओरंग के साथ-साथ बाघ अभयारण्य भी हैं।
- देहिंग पटकाई हाथियों का प्रमुख निवास स्थान है
- दिरक और बूढ़ी दिहिंग (Burhi Dihing River) नदियों के छोटे हिस्सों को पार्क में शामिल किया गया है,
- रायमोना पश्चिम बंगाल में इसके पश्चिम में बक्सा टाइगर रिजर्व, इसके उत्तर में भूटान में फिप्सू वन्यजीव अभयारण्य और पूर्व में मानस राष्ट्रीय उद्यान के साथ जुड़ा हुआ है।
- रायमोना राष्ट्रीय उद्यान में गोल्डन लंगूर, हाथी, बाघ, क्लाउडेड लेपर्ड और इंडियन गौर आदि प्राणीजगत शामिल है।

खबरों में प्रजातियां: घड़ियाल

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - पर्यावरण; संरक्षण

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में ओडिशा ने महानदी बेसिन में घड़ियालों के संरक्षण के लिये 1,000 रुपए के नकद पुरस्कार की घोषणा की।

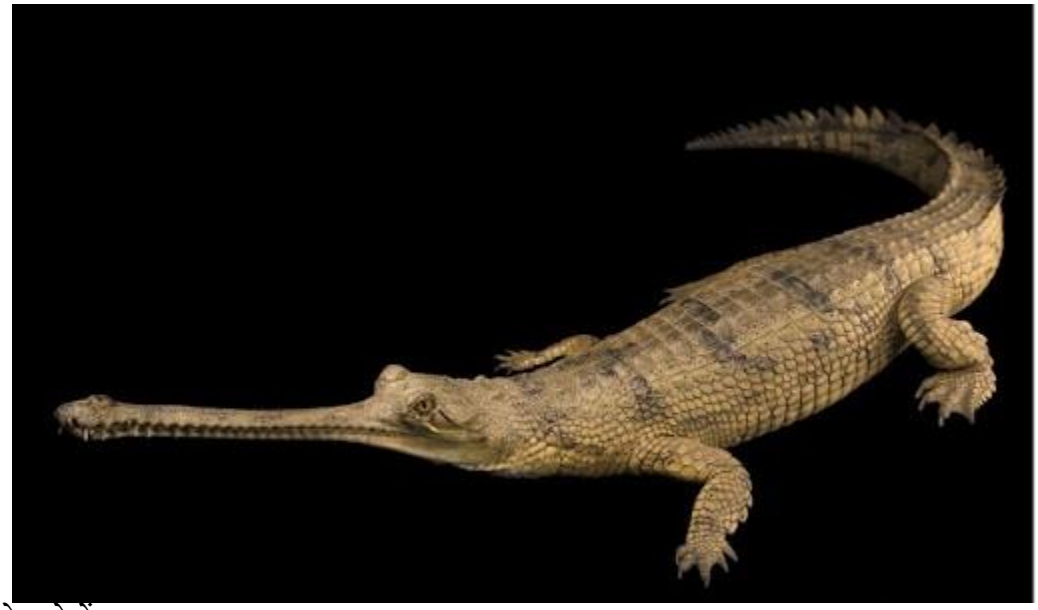

घड़ियाल के बारे में

- घड़ियाल, जिसे कभी-कभी गेवियल (Gavials) भी कहा जाता है, एक प्रकार का एशियाई मगरमच्छ है जो अपने लंबे, पतले थूथन के कारण अलग आकृति का होता है।

- मगरमच्छ सरीसृपों का एक समूह है जिसमें मगरमच्छ, घड़ियाल, कैमन आदि शामिल हैं।
- भारत में मगरमच्छों की तीन प्रजातियाँ हैं अर्थात्:
- घड़ियाल (गेवियलिस गैंगेटिकस): IUCN रेड लिस्ट- गंभीर रूप से संकटग्रस्त
- मगर मगरमच्छ (Crocodylus Palustris): IUCN- सुभेद्य।
- खारे पानी का मगरमच्छ (Crocodylus Porosus): IUCN- कम चिंतनीय।
- तीनों को CITES के परिशिष्ट I और वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची I में सूचीबद्ध किया गया है।
- हालांकि, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और पापुआ न्यू गिनी की खारे पानी की मगरमच्छ आबादी को CITES के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।
- **प्रवासो में शामिल हैं:** उत्तरी भारत का ताजा पानी - चंबल नदी, घाघरा, गंडक नदी और सोन नदी (बिहार)।
- **महत्व:** घड़ियाल की जनसंख्या स्वच्छ नदी जल का एक अच्छा संकेतक है।
- **संरक्षण के प्रयास:** लखनऊ, उत्तर प्रदेश में कुकरैल घड़ियाल पुनर्वास केंद्र व प्रजनन केंद्र, राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य (घड़ियाल इको पार्क, मध्य प्रदेश)।

विरासत के पेड़

- महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने पेड़ों को विरासत के पेड़ करार देकर उनकी रक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है
- एक पेड़ को "विरासत के पेड़" के रूप में मानने के लिए कुछ महत्वपूर्ण मानदंड हैं: उसका आकार, दुर्लभता, सौंदर्य/ऐतिहासिक मूल्य, ऐतिहासिक व्यक्ति, स्थान या यहां तक कि मिथकों के साथ जुड़ाव।
- इस टैग के लिए किसी विशेष प्रजाति का किसी क्षेत्र का मूल निवासी होना आवश्यक नहीं है।

ओलिव रिडले कछुओं के लिये ऑपरेशन ओलिविया

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - संरक्षण

सुर्खिओ में क्यों-

- हाल ही में, भारतीय तटरक्षक बल ने ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा के लिए 'ऑपरेशन ओलिवा' के लिए एक विमान सेवा में लगाया है।

ऑपरेशन ओलिव क्या है?

- इसकी शुरुआत 1980 के दशक की शुरुआत में हुई थी
- प्रतिवर्ष भारतीय तटरक्षक बल का "ऑपरेशन ओलिविया" ओलिव रिडले कछुओं की रक्षा करने में मदद करता है क्योंकि वे नवंबर से दिसंबर तक प्रजनन और घोंसले के शिकार के लिए ओडिशा तट पर एकत्र होते हैं।

ओलिव रिडले कछुए

- ओलिव रिडले कछुए विश्व में पाए जाने वाले सभी समुद्री कछुओं में सबसे छोटे और सबसे अधिक हैं।
- ये मांसाहारी होते हैं।
- वे हर वर्ष भोजन और संभोग के लिये हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करते हैं।

- ये कछुए अपने अद्वितीय सामूहिक घोंसले (Mass Nesting) अरीबदा (Arribada) के लिये सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं, अंडे देने के लिये हज़ारों मादाएँ एक ही समुद्र तट पर एक साथ यहाँ यहाँ आती हैं।
- **प्राकृतिक वास:**
    - ये प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर के गर्म पानी में पाए जाते हैं।
    - ओडिशा के गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य को समुद्री कछुओं की दुनिया की सबसे बड़े प्रजनन स्थल के रूप में जाना जाता है।
- **आईयूसीएन रेड लिस्ट:** संवेदनशील (Vulnerable)
- CITES: परिशिष्ट- I
- वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I
- अन्य पहलें:
- भारत में इनकी आकस्मिक मौत की घटनाओं को कम करने के लिये, ओडिशा सरकार ने ट्रॉल के लिये टर्टल एक्सक्लूडर डिवाइसेस (TEDs) का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है, जालों को विशेष रूप से एक निकास कवर के साथ बनाया गया है जो कछुओं के जाल में फसने के दौरान उन्हें भागने में सहायता करता है।

ब्लैक सॉफ्टशेल कछुए के बारे में

- **वैज्ञानिक नाम:** निल्सोनिया नाइग्रिकन्स (Nilssonia Nigricans)
- **प्राकृतिक वास:**
    - ये पूर्वोत्तर भारत और बांग्लादेश में मंदिरों के तालाबों में पाए जाते हैं।
    - इसकी वितरण सीमा में ब्रह्मपुत्र नदी और उसकी सहायक नदियाँ भी शामिल हैं।
- **सुरक्षा की स्थिति:**
    - IUCN रेड लिस्ट: गंभीर रूप से संकटग्रस्त
    - CITES: परिशिष्ट I
    - वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: कोई कानूनी संरक्षण नहीं
- **संकट:**
    - कछुए के मांस और अंडे का सेवन,
    - रेत खनन (Silt Mining)
    - आर्द्रभूमि का अतिक्रमण
    - बाढ़ के पैटर्न में बदलाव।

कछुआ संरक्षण

- **राष्ट्रीय समुद्री कछुआ कार्य योजना:**
    - इसमें न केवल संरक्षण के लिए अंतर-क्षेत्रीय कार्रवाई को बढ़ावा देने के तरीके और साधन शामिल हैं बल्कि सरकार, नागरिक समाज और सभी संबंधित हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय का मार्गदर्शन भी करते हैं।

- **हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौता (IOSEA)**

- भारत संयुक्त राष्ट्र समर्थित पहल, प्रवासी प्रजातियों पर कन्वेंशन (Convention on Migratory Species-CMS) के हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौते (Indian Ocean Sea Turtle Agreement- IOSEA) का हस्ताक्षरकर्त्ता है।
- यह एक ढांचा तैयार करता है जिसके माध्यम से हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के राज्य और अन्य संबंधित राज्य एक साथ काम कर सकते हैं ताकि घटती समुद्री कछुओं की आबादी को संरक्षित और फिर से भरने के लिए वे जिम्मेदारी साझा कर सकें।

- **कूर्मा एप:**
  - यह एक डिजिटल डेटाबेस के रूप में कार्य करता है जिसमें भारत के ताज़े जल के कछुओं सहित कछुओं की 29 प्रजातियों को शामिल किया गया है।
  - **द्वारा विकसित:** टर्टल सर्वाइवल एलायंस-इंडिया (Turtle Survival Alliance-India) और वाइल्डलाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी-इंडिया (Wildlife Conservation Society-India) के सहयोग से इंडियन टर्टल कंजर्वेशन एक्शन नेटवर्क (ITCAN) है।

संबंधित आलेख:

विश्व कछुआ दिवस 2020

बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य: असम

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - पर्यावरण

सुर्खियों में-

- हाल ही में, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर-इंडिया (WWF) ने असम में बरनाडी वन्यजीव अभयारण्य (Barnadi Wildlife Sanctuary) में कुछ बाघों को पाया।
- यह असम के सबसे छोटे WS (वन्यजीव अभयारण्य) में से एक है।

अभयारण्य के बारे में

- यह उत्तरी असम के बक्सा और उदलगुरी जिलों में भूटान की सीमा के निकट स्थित है।
- इसकी सीमा क्रमशः पश्चिम और पूर्व में बरनाडी नदी और नलपारा नदी से मिलती है।
- बरनाडी की स्थापना विशेष रूप से पिग्मी हॉग (Sus salvanius) और हिस्पिड हेयर (Caprolagus hispidus) की रक्षा के लिए की गई थी।
- BWS के लगभग 60% घास का मैदान बताया गया है, इसमें से अधिकांश अब घासयुक्त वनप्रदेश/जंगल हैं।
- **मुख्य वन प्रकार:** उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती (अभयारण्य का उत्तरी किनारा) और मिश्रित झाड़ियाँ तथा घास के मैदान (दक्षिणी भाग) हैं।
- अधिकांश प्राकृतिक वनस्पतियों का स्थान बॉम्बैक्स सेइबा, टेक्टोना ग्रैंडिस और यूकेलिप्टस के व्यावसायिक वृक्षारोपण और छप्पर घास ने ले लिया है।

असम में अन्य संरक्षित क्षेत्र:

- डिब्रू-सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान
- मानस राष्ट्रीय उद्यान
- नामेरी राष्ट्रीय उद्यान
- राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान

- काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान

इन्फ्रास्ट्रक्चर / ऊर्जा

देविका नदी राष्ट्रीय परियोजना: जम्मू और कश्मीर

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- हाल ही में, उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विकास राज्य मंत्री ने उधमपुर, जम्मू-कश्मीर में
- देविका नदी परियोजना के लिए सुझाव आमंत्रित किये गए हैं।
    - इस परियोजना की तुलना नमामि गंगे परियोजना से की जा रही है।

देविका नदी परियोजना के बारे में

- इस परियोजना की लागत 190 करोड़ रुपए है।
- राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (National River Conservation Plan-NRCP) के तहत मार्च 2019 में इस परियोजना पर काम शुरू किया गया था।
- **परियोजना के तहत,**
    - देविका नदी के तट पर स्नान "घाट" (स्थल) विकसित किए जाएंगे,
    - अतिक्रमण हटाया जाएगा
    - प्राकृतिक जल निकायों को पुन: स्थापित
    - श्मशान भूमि के साथ-साथ जलग्रहण क्षेत्र भी विकसित किये जाएंगे।
    - छोटे जल विद्युत संयंत्र और तीन सौर ऊर्जा संयंत्र भी विकसित किए जाएंगे।
- इस परियोजना से प्रदूषण में कमी आएगी और पानी की गुणवत्ता में सुधार होगा।

देविका नदी के बारे में

- देविका नदी का उद्गम जम्मू और कश्मीर के उधमपुर जिले में पहाड़ी सुध (शुद्ध) महादेव मंदिर से होता है।
- यह पश्चिमी पंजाब (अब पाकिस्तान में) की ओर बहती है जहां यह रावी नदी में मिल जाती है।
- नदी का धार्मिक महत्त्व इसलिये है क्योंकि इसे हिंदुओं द्वारा गंगा नदी की बहन के रूप में मान्यता प्राप्त है।
- जून 2020 में, उधमपुर में देविका ब्रिज का उद्घाटन किया गया।

राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) के बारे में

- यह एक केंद्र द्वारा वित्त पोषित योजना है
- 1995 में इसे लॉन्च किया गया
- **उद्देश्य:** नदियों के प्रदूषण को रोकना।
- नदी संरक्षण के कार्यक्रम राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना (NRCP) और NGRBA (राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण) के तहत कार्यान्वित किए जा रहे हैं।
- **NRCP के तहत गतिविधियां:**
    - खुले नालों के द्वारा नदी में बहने वाले कच्चे मल-जल को रोकने तथा शोधन हेतु उसका पथांतर करने के लिये दिशा अवरोधन एवं दिशा परिवर्तन कार्य।
    - नदी तट पर खुले में शौच को रोकने के लिए कम लागत वाला स्वच्छता कार्य।
    - लकड़ी के उपयोग को संरक्षित करने के लिए इलेक्ट्रिक श्मशान और बेहतर लकड़ी श्मशान घाट

- रिवर फ्रंट डेवलपमेंट कार्य जैसे स्नान घाटों का सुधार।
- जन जागरूकता और जनभागीदारी।

भारतीय रेलवे को मिला 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को भारतीय रेलवे को संचार और सिग्नलिंग प्रणाली में सुधार के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी।
- इस स्पेक्ट्रम के साथ, रेलवे अपने मार्गों पर लॉन्ग-टर्म इवोल्यूशन (LTE) आधारित मोबाइल ट्रेन रेडियो कम्युनिकेशन (MTRC) संचार प्रदान करेगा।
    - LTE चौथी पीढ़ी का (4G) वायरलेस मानक है जो तीसरी पीढ़ी (3G) तकनीक की तुलना में सेलफोन और अन्य सेलुलर उपकरणों के लिए बढ़ी हुई नेटवर्क क्षमता और गति प्रदान करता है।

आवंटन के लाभ

- आधुनिक सिग्नलिंग और ट्रेन सुरक्षा प्रणाली प्रदान करना
- सुरक्षित और विश्वसनीय आवाज, वीडियो और डेटा संचार
- ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने और देरी को कम करने में मदद करना
- इंटरनेट ऑफ थिंग्स (IoT) आधारित रिमोट एसेट मॉनिटरिंग करने के लिए रेलवे को सक्षम बनाना
    - IoT एक कंप्यूटिंग अवधारणा है जो रोजमर्रा की भौतिक वस्तुओं के इंटरनेट से जुड़े होने और अन्य उपकरणों से खुद को पहचानने में सक्षम होने के विचार का वर्णन करती है।

ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (TCAS)

- यह एक माइक्रोप्रोसेसर आधारित नियंत्रण प्रणाली है, जो मोटरमैन की गति, यात्रा की दिशा और सतर्कता की निरंतर निगरानी करती है।
- यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करते हुए अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए सुरक्षा में सुधार और लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
    - आधुनिक रेल नेटवर्क के परिणामस्वरूप परिवहन लागत कम होगी और दक्षता अधिक होगी।

अन्य संबंधित तथ्य

रेडियो स्पेक्ट्रम

- रेडियो स्पेक्ट्रम (रेडियो फ्रीक्वेंसी या RF के रूप में भी जाना जाता है) विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम का एक हिस्सा है।
    - इस फ्रीक्वेंसी रेंज में विद्युतचुंबकीय तरंगों को रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड या बस 'रेडियो तरंगें' कहा जाता है।
    - विद्युतचुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगों की तरंगदैर्घ्य सबसे लंबी होती है।
    - इनकी खोज 1880 के दशक के अंत में हेनरिक हर्ट्ज़ ने की थी।
- RF बैंड 30 kHz और 300 GHz के बीच की सीमा में फैले हुए हैं
- रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड के निर्माण और प्रसारण को राष्ट्रीय कानूनों द्वारा कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, जो एक अंतरराष्ट्रीय निकाय, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (ITU) द्वारा समन्वित है।

भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट: नीति आयोग

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- नीति आयोग, रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट (RMI) और आरएमआई इंडिया की नई रिपोर्ट, "फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट इन इंडिया: ए रोडमैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट-इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट", भारत के लिये अपनी लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने के लिये महत्त्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।
- रिपोर्ट नीति, प्रौद्योगिकी, व्यापार मॉडल और बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित माल ढुलाई क्षेत्र के लिए समाधान की रूपरेखा तैयार करती है।
    - माल परिवहन भूमि, समुद्र या वायु द्वारा वस्तुओं, माल और कार्गो संतुलन के परिवहन की प्रक्रिया है।
- रसद क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद के 5% का प्रतिनिधित्व करता है और 2.2 करोड़ लोगों को रोजगार देता है।
- माल और सेवाओं की बढ़ती मांग के कारण, भविष्य में माल ढुलाई की मांग तेजी से बढ़ने की उम्मीद है।

रिपोर्ट के अनुसार, भारत में क्षमता है

- इसकी रसद लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 4% तक कम करें।
- 2020 और 2050 के बीच 10 गीगाटन संचयी CO2 उत्सर्जन बचत प्राप्त करें।
- 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) और पार्टिकुलेट मैटर (PM) उत्सर्जन में क्रमशः 35% और 28% की कमी करें।

मुद्दे

- उच्च रसद लागत
- शहरों में बढ़ते CO2 उत्सर्जन और वायु प्रदूषण में योगदान देता है।

सिफारिश

- रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ाना
- अंतरमॉडल परिवहन को बढ़ावा देना
- वेयरहाउसिंग और ट्रकिंग प्रथाओं में सुधार
  नीतिगत उपाय
- स्वच्छ प्रौद्योगिकी अपनाने के लिए प्रायोगिक परियोजनाएं
- सख्त ईंधन बचत मानक।

माल ढुलाई के लिए हाल की पहल

- **डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC):** रेलवे कॉरिडोर जो विशेष रूप से माल ढुलाई के लिए है,
- फास्टैग, RFID के साथ ई-वे बिल एकीकरण
- **FAME योजना:** 2030 तक 30% EV पैठ तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को अपनाना।
- भारत चरण VI मानदंड
- **कॉर्पोरेट औसत ईंधन दक्षता (CAFE) विनियम:** 2030 तक सड़क पर वाहनों की ईंधन दक्षता को 35% तक बढ़ाने का लक्ष्य है।

भारत का इथेनॉल रोडमैप

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- केंद्र सरकार ने वर्ष 2025 तक भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के रोडमैप पर एक विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट जारी की है।
- इस रोडमैप में अप्रैल 2022 तक E10 ईंधन की आपूर्ति प्राप्त करने के लिए इथेनॉल-मिश्रित ईंधन के क्रमिक रोलआउट और अप्रैल 2023 से अप्रैल 2025 तक E20 के चरणबद्ध रोलआउट का प्रस्ताव है।
- भारत सरकार ने 2030 से 2025 तक पेट्रोल (जिसे E20 भी कहा जाता है) में 20% इथेनॉल सम्मिश्रण के लक्ष्य को आगे बढ़ाया है।

इथेनॉल क्या है?

- यह प्रमुख जैव ईंधन में से एक है।
- यह प्रमुख जैव ईंधनों में से एक है, जो प्रकृतिक रूप से खमीर अथवा एथिलीन हाइड्रेशन जैसी पेट्रोकेमिकल प्रक्रियाओं के माध्यम से शर्करा के किण्वन द्वारा उत्पन्न होता है।

रोडमैप की सिफारिशें:

- इथेनॉल सम्मिश्रण रोडमैप को सूचित करें
- तेल विपणन कंपनियों के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा
- नियामक मंजूरी में तेजी लाएं
- इथेनॉल मिश्रित वाहन को प्रोत्साहित करें
- इथेनॉल मिश्रित गैसोलीन की कम कीमत

फेम-2 योजना में संशोधन

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस III - अर्थव्यवस्था

सुर्खियों में-

- भारी उद्योग मंत्रालय (DHI) ने हाल ही में FAME II योजना को संशोधित किया है।
- संशोधन का उद्देश्य: इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के लिए प्रेरित करना

संशोधन

- पहले इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी की दर 10,000 रुपये प्रति kWh थी। इसे बढ़ाकर 15,000 रुपये/kWh कर दिया गया है, जो कि वाहन लागत का लगभग 40% है।
- एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा 300,000 इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों की कुल मांग की शुरुआत।

फेम इंडिया योजना (FAME India Scheme)

- इसे 2015 में लॉन्च किया गया था।
- यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का एक हिस्सा है।
- इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देना और उसका सतत विकास सुनिश्चित करना है
- योजना के चरण 2 को पहली अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले तीन वर्षों की अवधि के लिए अनुमोदित किया गया था
- यह योजना 2-व्हीलर, पैसेंजर 4-व्हीलर व्हीकल, 3-व्हीलर ऑटो, लाइट कमर्शियल व्हीकल्स और बसों सहित वाहन सेगमेंट को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।

- FAME के परिणामस्वरूप अब तक 75,000 से अधिक वाहनों की बिक्री से 2 करोड़ लीटर से अधिक ईंधन की बचत हुई है और CO2 में लगभग 4 करोड़ किलोग्राम की कमी आई है।

डगमारा जलविद्युत परियोजना: बिहार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-I- भूगोल और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- हाल ही में डगमारा जलविद्युत परियोजना, जिला सुपौल के कार्यान्वयन के लिये राष्ट्रीय जलविद्युत निगम (NHPC) लिमिटेड और बिहार राज्य जलविद्युत निगम लिमिटेड (BSHPC) के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं।
    - यह परियोजना कोसी नदी पर स्थित है।

परियोजना के बारे में

- यह एक रन-ऑफ-द-रिवर योजना है।
    - रन-ऑफ-रिवर पनबिजली परियोजनाएँ पानी द्वारा ले जाने वाली गतिज ऊर्जा का पता लगाने के लिये नदियों और सूक्ष्म टरबाइन जनरेटर के प्राकृतिक नीचे की ओर प्रवाह का उपयोग करती हैं।
- इस परियोजना की कुल 130 मेगावाट ऊर्जा पैदा करने की क्षमता होगी।

महत्व

- जहां तक हरित ऊर्जा का संबंध है, यह बिहार के बिजली क्षेत्र के परिदृश्य में एक ऐतिहासिक परियोजना होगी।
- यह सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढांचे के विकास को बढ़ावा देगा और रोजगार के अवसर पैदा करेगा।
- स्वच्छ और हरित विद्युत उत्पन्न करने के अलावा यह निष्पादन क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक और बुनियादी ढाँचे के विकास को बढ़ावा देगी और रोज़गार के अवसर भी पैदा करेगी।

कोसी नदी के बारे में

- यह एक सीमापारीय नदी (Trans-Boundary River) है जो तिब्बत, नेपाल एवं भारत से होकर बहती है।
- इसका स्रोत तिब्बत में है
- प्रमुख सहायक नदियाँ: सूर्य कोसी, अरुण और तमूर
- इसकी अस्थिर प्रकृति पाठ्यक्रम में परिवर्तन का कारण बनती है।
- भारत में ब्रह्मपुत्र के बाद कोसी में अधिकतम मात्रा में गाद और रेत है।
- अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे "बिहार का शोक" भी कहा जाता है।

भारत में सीप्लेन सेवाओं के लिये समझौता ज्ञापन

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- बंदरगाह, नौवहन तथा जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) और नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA) ने भारत में सी-प्लेन सेवाओं के विकास के लिये समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये हैं।

समझौता ज्ञापन (MoU) के बारे में

- **उद्देश्य:** इस समझौता ज्ञापन में भारत के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के भीतर सी-प्लेन सेवाओं के गैर-अधिसूचित/अधिसूचित प्रचालन की परिकल्पना की गई है।

- विभिन्न स्थानों पर समुद्री विमान सेवाओं के संचालन को समय पर पूरा करने के लिए एक समन्वय समिति का गठन किया जाना है।
- सदस्यों में MoCA, MOPSW और पर्यटन मंत्रालय (MoT) के अधिकारी शामिल होंगे।

लाभ:

- यह न केवल समुद्री विमानों के माध्यम से पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देकर पूरे देश में सहज संपर्क को बढ़ाएगा बल्कि पर्यटन उद्योग को भी बढ़ावा देगा।
- पर्यटन उद्योग को बढ़ावा
- भारत में नए जल हवाई अड्डों के विकास और नए सी-प्लेन मार्गों के संचालन में तेज़ी लाने में मदद करेगा।

नामित कार्य :

- MoPSW एयरोड्रोम के वाटर फ्रंट इंफ्रास्ट्रक्चर की पहचान और विकास करेगा।
- MoCA बोली लगाएगा और संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों का चयन करेगा।
- MoCA धन/वित्तीय सहायता प्रदान करेगा।

तमिलनाडु रक्षा औद्योगिक गलियारा

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस- III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- एशियाई विकास बैंक (एडीबी) और भारत सरकार ने आज यहां तमिलनाडु में चेन्नई-कन्याकुमारी औद्योगिक गलियारे (सीकेआईसी) में परिवहन संपर्क में सुधार और औद्योगिक विकास को सुगम बनाने के लिए 484 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए।
- सीकेआईसी भारत के पूर्वी तट आर्थिक गलियारे (ईसीईसी) का हिस्सा है।
    - यह पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है
    - यह भारत को दक्षिण, दक्षिणपूर्व और पूर्वी एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है।
    - एडीबी ईसीईसी को विकसित करने में भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है।

CKIC के बारे में

- परियोजना प्रदान करेगी:
    - औद्योगिक समूहों में निर्बाध सड़क संपर्क
    - परिवहन गेटवे और उपभोग केंद्र
- रसद और उत्पादन लागत को कम करने में मदद करें।
- उद्देश्य: आवश्यक परिवहन, ऊर्जा और शहरी आधारभूत संरचना प्रदान करके औद्योगिक परिवर्तन में तेजी लाना
- यह स्थिरता, जलवायु परिवर्तन के लचीलेपन और सड़क सुरक्षा तत्वों पर जोर देता है।

डीप ओशन मिशन

संदर्भ: आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने गहरे समुद्र में संसाधनों का पता लगाने और महासागरीय संसाधनों के सतत उपयोग के लिए गहरे समुद्र प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के उद्देश्य से "गहरे समुद्र अभियान" पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (एमओईएस) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी।

- 'नीली अर्थव्यवस्था' का आशय आर्थिक विकास, बेहतर आजीविका, रोज़गार सृजन और महासागरीय पारिस्थितिकी तंत्र के बेहतर स्वास्थ्य हेतु समुद्री संसाधनों के सतत् उपयोग से है।

भारत के लिए महासागरों का महत्व

- भारत की 7517 किलोमीटर लंबी तटरेखा में 9 तटीय राज्य और 1382 द्वीप मौजूद हैं। भारत तीन दिशाओं से महासागरों से घिरा हुआ है और देश की लगभग 30 प्रतिशत आबादी तटीय क्षेत्रों में रहती है, साथ ही महासागर मत्स्य पालन, जलीय कृषि, पर्यटन, आजीविका एवं 'ब्लू इकॉनमी' का समर्थन करने वाला एक प्रमुख आर्थिक कारक है।
- महासागर कार्बन पृथक्करण, तटीय संरक्षण, अपशिष्ट निपटान और जैव विविधता के अस्तित्व जैसी पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं भी प्रदान करते हैं।

डीप ओशन मिशन में छह प्रमुख घटक शामिल होंगे

1. गहरे समुद्र में खनन और मानवयुक्त पनडुब्बी के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास:

- तीन लोगों को समुद्र में 6,000 मीटर की गहराई तक ले जाने के लिये वैज्ञानिक सेंसर और उपकरणों के साथ एक मानवयुक्त पनडुब्बी विकसित की जाएगी।
- मध्य हिंद महासागर में 6,000 मीटर की गहराई में पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स के खनन के लिए एक एकीकृत खनन प्रणाली भी विकसित की जाएगी।

2. महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास:

- इसके तहत जलवायु परिवर्तनों के भविष्यगत अनुमानों को समझने और उसी के अनुरूप सहायता प्रदान करने वाले अवलोकनों एवं मॉडलों के एक समूह का विकास किया जाएगा।

3. गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार

- इसके तहत सूक्ष्म जीवों सहित गहरे समुद्र की वनस्पतियों और जीवों की सर्वेक्षण और गहरे समुद्र में जैव-संसाधनों के सतत् उपयोग संबंधी अध्ययन पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

4. गहरे समुद्र में सर्वेक्षण और अन्वेषण

- इस घटक का प्राथमिक उद्देश्य हिंद महासागर के मध्य-महासागरीय भागों के साथ बहु-धातु हाइड्रोथर्मल सल्फाइड खनिज के संभावित स्थलों का पता लगाना और उनकी पहचान करना है।

5. समुद्र से ऊर्जा और मीठा पानी

- इसमें अपतटीय 'महासागर थर्मल ऊर्जा रूपांतरण' (OTEC) विलवणीकरण संयंत्र हेतु अध्ययन और विस्तृत इंजीनियरिंग डिज़ाइन तैयार करना शामिल है।

6. महासागर जीवविज्ञान हेतु उन्नत समुद्री स्टेशन

- इस घटक का उद्देश्य समुद्री जीव विज्ञान और इंजीनियरिंग में मानव क्षमता और उद्यम का विकास करना है।
- यह घटक ऑन-साइट व्यापार इनक्यूबेटर सुविधाओं के माध्यम से अनुसंधान को औद्योगिक अनुप्रयोग और उत्पाद विकास में परिवर्तित करेगा।

निष्कर्ष

- इस पहल के लिए सबसे बड़ी बाधा यह है कि गहरे समुद्र में खनन के लिए आवश्यक तकनीकों के रणनीतिक निहितार्थ हैं और व्यावसायिक रूप से उपलब्ध नहीं हैं। ऐसे में स्वदेशीकरण की गुंजाइश है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- सागरमाला परियोजना
- हिंद महासागर में जीनोम मैपिंग

अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतर्देशीय पोत विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है।
    - यह संसद में पारित होने के बाद अंतर्देशीय पोत अधिनियम, 1917 को प्रतिस्थापित करेगा।
- यह विधेयक अंतर्देशीय जहाज़ों की सुरक्षा, बचाव और पंजीकरण को विनियमित करेगा।

विधेयक की विशेषताएं:

- राज्यों द्वारा बनाए गए अलग-अलग नियमों के बजाय संपूर्ण देश के लिए एकीकृत कानून का प्रावधान करना है।
- यह ज्वारीय जल सीमा और राष्ट्रीय जलमार्गों को शामिल करते हुए 'अंतर्देशीय जल' की परिभाषा को व्यापक बनाता है।
- यह अंतर्देशीय जहाजों के प्रदूषण नियंत्रण उपायों से भी संबंधित है।
- यह केंद्र सरकार को रसायनों, पदार्थों आदि की सूची को प्रदूषकों के रूप में नामित करने का निर्देश देता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

अंतर्देशीय जलमार्ग

- भारत में लगभग 14,500 किलोमीटर नौगम्य जलमार्ग (Navigable Waterways) हैं जिनमें नदियाँ, नहरें, बैकवाटर/अप्रवाही जल, खाड़ियाँ आदि शामिल हैं।
- राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 के अनुसार, 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग (NWs) घोषित किया गया है।
- **राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 (NW-1):** इलाहाबाद-हल्दिया जलमार्ग को भारत में राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या-1 का दर्जा दिया गया है। यह जलमार्ग गंगा-भागीरथी-हुगली नदी तंत्र में स्थित है। यह 1620 किमी लंबाई के साथ भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय जलमार्ग है।

क्या आप जानते हैं?

- भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) विश्व बैंक की तकनीकी और वित्तीय सहायता से गंगा के हल्दिया-वाराणसी खंड (NW-1 का हिस्सा) पर नेविगेशन की क्षमता बढ़ाने के लिए जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) को लागू कर रहा है।

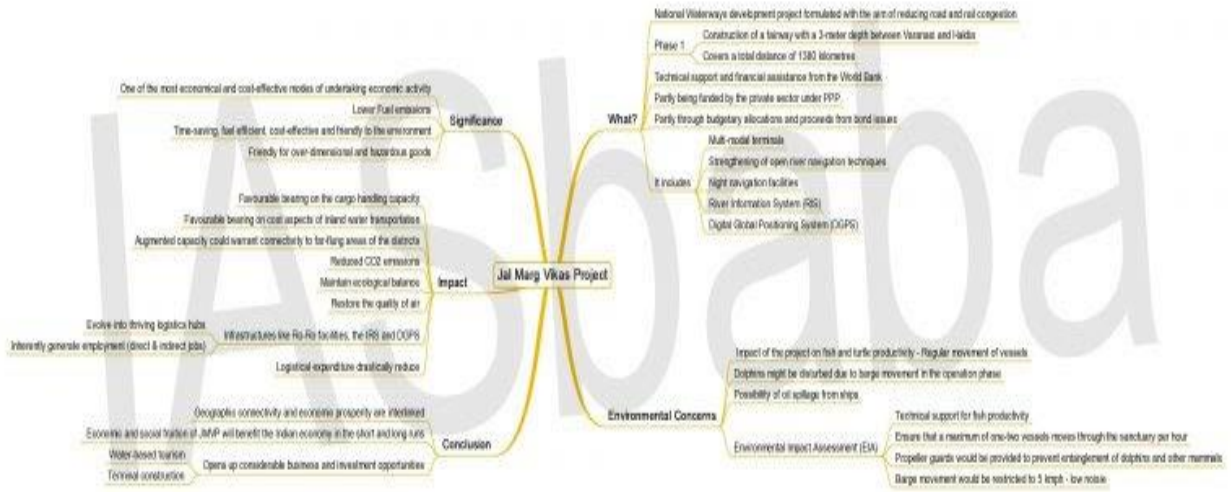

Pic courtesy: iasbaba

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III – इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- पर्यटन मंत्रालय ने भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तीन मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप जारी किया।

- इसका उद्देश्य पर्यटन उत्पादों की पहचान, विविधता, विकास और प्रचार करना है।
- यह मौसमी के पहलू को दूर करने में मदद करेगा और पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए भारत को 365 दिनों के गंतव्य के रूप में बढ़ावा देगा

भारत में ग्रामीण पर्यटन के विकास के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

प्रमुख प्रावधान

- ग्रामीण पर्यटन पर राज्य का आकलन और ट्रैकिंग।
- ग्रामीण पर्यटन के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और मंच।
- क्लस्टरों का विकास और विपणन सहायता
- हितधारकों का निर्माण क्षमता

मेडिकल और वेलनेस टूरिज्म के लिए मसौदा राष्ट्रीय रणनीति और रोडमैप

प्रमुख प्रावधान

- "हील इन इंडिया" ब्रांड द्वारा MWT गंतव्य के रूप में भारत को बढ़ावा देना।
- ऑनलाइन चिकित्सा मूल्य यात्रा पोर्टल स्थापित करके डिजिटलीकरण को सक्षम करें।
- उदारीकृत वीजा नीति और बेहतर हवाई संपर्क।
- राष्ट्रीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य पर्यटन प्रोत्साहन बोर्ड की स्थापना

सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए ड्रोन सर्वेक्षण अनिवार्य

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - इंफ्रास्ट्रक्चर

सुर्खियों में-

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने विकास, निर्माण, संचालन और रख-रखाव के विभिन्न चरणों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की वीडियो रिकॉर्डिंग के लिये ड्रोन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है।
- इन वीडियो को परियोजनाओं पर हुई प्रगति का आकलन करने के लिए NHAI के "डेटा लेक" (Data Lake) पोर्टल पर किया जाएगा।

महत्व

- पारदर्शिता और एकरूपता बढ़ाना।
- वीडियो का उपयोग परियोजनाओं के भौतिक निरीक्षण के दौरान किया जा सकता है।
- उन्हें मध्यस्थ न्यायाधिकरणों और न्यायालयों के समक्ष विवाद समाधान प्रक्रिया के दौरान साक्ष्य के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क की स्थिति का सर्वेक्षण करने के लिये नेटवर्क सर्वेक्षण वाहन (NSV) की अनिवार्य तैनाती से राजमार्गों की समग्र गुणवत्ता में वृद्धि होगी।

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बारे में

- NHAI की स्थापना NHAI अधिनियम, 1988 के तहत की गई थी।
- इसे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना (NHDP) के साथ-साथ विकास, रखरखाव और प्रबंधन के लिए अन्य छोटी परियोजनाओं को सौंपा गया है।
- NHAI राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क को वैश्विक मानकों और लागत प्रभावी तरीके से बनाए रखता है।

NHAI का पोर्टल 'डेटा लेक'

- डेटा लेक और परियोजना प्रबंधन सॉफ्टवेयर के शुभारंभ के साथ NHAI 'पूरी तरह से डिजिटल' हो गया है।
- यह क्लाउड आधारित और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म है।

- सभी परियोजना प्रलेखन, संविदात्मक निर्णय और अनुमोदन अब केवल पोर्टल के माध्यम से किए जाते हैं।

विद्युत क्षेत्र: डिस्कॉम (DISCOMS) के साथ मुद्दे

संदर्भ: विद्युत वितरण कंपनियों या डिस्कॉम (DISCOM) बिजली पैदा करने वाली कंपनियों के बकाया में तेज गिरावट आई क्योंकि उन्होंने केंद्र द्वारा व्यवस्थित नकदी प्रवाह (लिक्विडिटी) सुविधा का उपयोग किया।

मुद्दे

- **निर्वाह के मुद्दे:** डिस्कॉम के वित्तीय और परिचालन संकेतकों में सुधार निरंतर नहीं होने के कारण केंद्र से एक और बचाव पैकेज की मांग की जा रही है।
- वित्तीय वर्ष 2019 में विद्युत वितरण कंपनियों का कुल तकनीकी और वाणिज्य नुकसान (ATC) 21.7% रहा। इसके तहत तकनीकी कारणों से होने वाले क्षति, बिजली की चोरी, अपर्याप्त बिलिंग, भुगतान डिफॉल्ट, राजस्व संग्रह की अक्षमता आदि शामिल है।
- **लाभप्रदता:** डिस्कॉम की लागत (आपूर्ति की औसत लागत) और राजस्व (प्राप्त औसत राजस्व) के बीच का अंतर, जिसे अब तक समाप्त कर दिया जाना चाहिए था, नियमित और अनुरूप टैरिफ वृद्धि की कमी के कारण 0.49 रुपये प्रति यूनिट है।
- **महामारी प्रभाव:** औद्योगिक और वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं की मांग में गिरावट के साथ, इस धारा से राजस्व, जिसका उपयोग अन्य उपभोक्ताओं को क्रॉस-सब्सिडी के लिए किया जाता है, में गिरावट आई है, जिससे डिस्कॉम्स पर दबाव बढ़ गया है।
- **डेटा की कमी:** उदय योजना के शुरू होने के छह साल बाद भी, वितरण श्रृंखला में विभिन्न स्तरों - फीडर, वितरण ट्रांसफार्मर (डीटी) और उपभोक्ता को पूरी तरह से मीटर नहीं किया गया है। डेटा की यह कमी श्रृंखला में उस स्तर का पता लगाना मुश्किल बना देती है जहां नुकसान हो रहा है।

यथास्थिति को बदलने के लिए कुछ सुझाव दिए गए हैं:

- राष्ट्रीय बिजली वितरण कंपनी।
- वितरण श्रृंखला का निजीकरण।
- सार्वजनिक और निजी दोनों बिजली उत्पादन कंपनियों के बकाया डिस्कॉम को आरबीआई के पास राज्य के शेष से घाटा, राज्यों को डिस्कॉम वित्त को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए मजबूर करता है।
- वितरण सुधारों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राज्य उधारी को जोड़ने से राज्यों को कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- भारत का DISCOM तनाव - वित्तीय मुद्दे और समय पर भुगतान में बाधाएँ
- बिजली का मसौदा (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020
- उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना (उदय योजना)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी

एंबीटैग (AmbiTAG)

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - विज्ञान और टेक

सुर्खियों में-

- पंजाब में आईआईटी रोपड़ ने कोल्ड चेन प्रबंधन के लिए भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर "AmbiTAG " विकसित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

- AmbiTAG अपनी तरह का पहला IoT उपकरण है जो खराब होने वाले उत्पादों, टीकों और यहां तक कि शरीर के अंगों और रक्त के परिवहन के दौरान वास्तविक समय के परिवेश के तापमान को रिकॉर्ड करता है।
- यह रिकॉर्ड किया गया तापमान यह जानने में और मदद करता है कि क्या दुनिया में कहीं से भी ले जाया गया वह विशेष वस्तु अभी भी प्रयोग करने योग्य है या तापमान भिन्नता के कारण नष्ट हो गया है।
- यह जानकारी टीकों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जिसमें कोविड-19 वैक्सीन, अंगों और रक्त परिवहन शामिल हैं।
- डिवाइस को टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब - AWADH (कृषि और जल प्रौद्योगिकी विकास हब) और इसके स्टार्टअप स्क्रैचनेस्ट के तहत विकसित किया गया है।
- AWADH भारत सरकार की एक परियोजना है।

लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तकनीक

संदर्भ: 28 मई को 36 उपग्रहों के सफल प्रक्षेपण के बाद, वनवेब का लो अर्थ ऑर्बिट (LEO) तारामंडल 218 इन-ऑर्बिट उपग्रहों तक पहुंच गया।

- 50 डिग्री अक्षांश के उत्तर के सभी क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रस्तुत करने की 'पाँच से 50' सेवा की क्षमता हासिल करने के लिये अब केवल एक और प्रक्षेपण की आवश्यकता है।

वनवेब क्या है?

- वनवेब एक वैश्विक संचार कंपनी है जिसका लक्ष्य अपने LEO उपग्रहों के बेड़े के माध्यम से दुनिया भर में ब्रॉडबैंड उपग्रह इंटरनेट वितरित करना है।
- 2010 में, कंपनी को दिवालिया घोषित कर दिया गया, लेकिन यूके सरकार, ह्यूजेस कम्युनिकेशन, सुनील मित्तल की भारती ग्लोबल लिमिटेड, सॉफ्टबैंक और यूटेलसैट, एक प्रमुख यूरोपीय उपग्रह ऑपरेटर से मिलकर एक संघ से निवेश की आमद के बाद परिचालन फिर से शुरू करने में सक्षम हुई थी।

LEO तकनीक

- LEO उपग्रह 1990 के दशक से ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं, कंपनियों और व्यक्तियों को विभिन्न संचार सेवाएं प्रदान करते हैं।
- लगभग 36,000 किमी दूर स्थित स्थिर कक्षा उपग्रहों की तुलना में LEO उपग्रह पृथ्वी से लगभग 500km-2000km स्थित हैं।
- इसलिए, LEO उपग्रह ब्रॉडबैंड केवल उन क्षेत्रों में बेहतर है जहां फाइबर और स्पेक्ट्रम सेवाओं तक नहीं पहुंचा जा सकता है। इसलिए वनवेब का लक्षित बाजार ग्रामीण आबादी और शहरी क्षेत्रों से दूर संचालित सैन्य इकाइयाँ होंगी।

क्या आप जानते है?

- एरियल वायरलेस नेटवर्क बनाने के लिए उच्च ऊंचाई वाले गुब्बारों का उपयोग करते हुए, Google ने 2013 में अपना 'लून' प्रोजेक्ट लॉन्च किया। ग्रामीण केन्या में सेवा का परीक्षण करने के बाद, Google की मूल कंपनी, अल्फाबेट ने 2021 में इस परियोजना को छोड़ दिया।

- एक अलग ट्रैक लेते हुए, फेसबुक ने ड्रोन का उपयोग करके इंटरनेट को धरती पर लाने का प्रयास किया। हालांकि, दो असफल परीक्षण उड़ानों के बाद, इसने 2018 में इस परियोजना को भी छोड़ दिया।
- 70% से अधिक ग्रामीण भारतीयों की इंटरनेट तक पहुंच नहीं है, एक समस्या जो विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि महामारी के आलोक में शिक्षा और बैंकिंग के क्षेत्र में डिजिटल एकीकरण की बढ़ती आवश्यकता है।

LEO प्रौद्योगिकी की चिंताएं

- **कई खिलाड़ियों के कारण जटिलता:** वनवेब उपग्रह अमेरिका में निर्मित होते हैं, इसके रॉकेट रूस में बनाकर लॉन्च किए जाते हैं और इसके प्रक्षेपण की सुविधा फ्रांस से बाहर की कंपनी द्वारा की जाती है। कई हितधारकों के शामिल होने के कारण, नियामक ढांचा जटिल हो जाएगा।
- **आवृत्ति रुकावट :** निचली कक्षा में यात्रा करने वाले उपग्रह अपने ऊपर परिक्रमा करने वालों की आवृत्ति को भी बाधित करते हैं, यह आरोप स्टारलिंक उपग्रहों पर पहले ही लगाया जा चुका है।
- **अंतरिक्ष में कबाड़ में वृद्धि और टकराव के खतरे:** एक और चिंता की बात यह है कि कक्षा में पहले से ही 1cm व्यास से बड़ी लगभग 1 मिलियन वस्तुएं हैं, जो दशकों की अंतरिक्ष गतिविधियों का उत्पाद है। उन वस्तुओं, जिन्हें बोलचाल की भाषा में 'स्पेस जंक' कहा जाता है, इनमें अंतरिक्ष यान को नुकसान पहुंचाने या अन्य उपग्रहों से टकराने की क्षमता होती है।
- **अधिक लागत:** जबकि वनवेब और स्टारलिंक जैसी कंपनियों ने ग्रामीण भारतीय उपभोक्ताओं के लिए अपनी मार्केटिंग की है, उनके मूल्य बिंदुओं को देखते हुए यह संभावना नहीं है कि अधिकांश ग्रामीण भारतीय उनकी सेवाओं को वहन करने में सक्षम होंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- इन-स्पेस: बढ़ती निजी भूमिका
- स्पेसएक्स क्रू ड्रैगन: अंतरिक्ष अन्वेषण में एक नया युग
- भारत को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार की जरूरत है

प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST): चीन का कृत्रिम सूर्य

बारे में

- प्रायोगिक उन्नत सुपरकंडक्टिंग टोकामक (EAST) रिएक्टर चीन के हेफ़ेई में चीनी विज्ञान अकादमी (ASIPP) के प्लाज्मा भौतिकी संस्थान में स्थित एक उन्नत परमाणु संलयन प्रयोगात्मक अनुसंधान उपकरण है।
- इस कृत्रिम सूर्य का उद्देश्य परमाणु संलयन की प्रक्रिया को दोहराना है, यह वही प्रतिक्रिया है जो सूर्य को शक्ति प्रदान करती है।
- ईएएसटी के अलावा, चीन वर्तमान में HL-2A रिएक्टर के साथ-साथ J-TEXT का भी संचालन कर रहा है।
- ईएएसटी परियोजना अंतर्राष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर (ITER) सुविधा का हिस्सा है, जो 2035 में चालू होने पर दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु संलयन रिएक्टर बन जाएगा। इस परियोजना में भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों का योगदान शामिल है।

'कृत्रिम सूर्य' ईएएसटी कैसे कार्य करता है?

- यह परमाणु संलयन प्रक्रिया पर आधारित है जो सूर्य और अन्य तारों द्वारा की जाती है।
- परमाणु संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न किए बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
- नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से बड़ी मात्रा में अपशिष्ट उत्पन्न किये बिना उच्च स्तर की ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है।
- पहले, परमाणु विखंडन के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन किया जाता था यह एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक भारी परमाणु के नाभिक को हल्के परमाणुओं के दो या अधिक नाभिकों में विभाजित किया जाता था।

- जबकि विखंडन करना एक आसान प्रक्रिया है, यह कहीं अधिक परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करता है। परमाणु विखंडन के विपरीत संलयन ग्रीनहाउस गैसों का उत्सर्जन नहीं करता है और इसे कम जोखिम के साथ एक सुरक्षित प्रक्रिया माना जाता है।
- एक बार महारत हासिल करने के बाद, परमाणु संलयन संभावित रूप से असीमित स्वच्छ ऊर्जा और बहुत कम लागत प्रदान कर सकता है।
- परमाणु संलयन करने के लिये हाइड्रोजन के परमाणुओं पर अत्यधिक ताप और दबाव डाला जाता है ताकि वे एक साथ जुड़ जाए।
- हाइड्रोजन में पाए जाने वाले ड्यूटेरियम और ट्रिटियम दोनों के नाभिक एक साथ मिलकर एक हीलियम नाभिक और एक न्यूट्रॉन के साथ ऊर्जा का निर्माण करते हैं।
- गैसीय हाइड्रोजन ईंधन को 150 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि यह उप-परमाणु कणों का एक गर्म प्लाज़्मा (विद्युत चार्ज गैस) बना सके।
- एक मज़बूत चुंबकीय क्षेत्र की मदद से प्लाज़्मा को रिएक्टर की दीवारों से दूर रखा जाता है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह ठंडा न हो और बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करने की क्षमता कम हो जाए। संलयन होने के लिए प्लाज्मा लंबी अवधि के लिए सीमित है।

ईएएसटी द्वारा नवीनतम रिकॉर्ड क्या है और यह क्यों मायने रखता है?

- ईएएसटी रिएक्टर ने 216 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट का प्लाज्मा तापमान हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया और 288 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट पर 20 सेकंड तक चलने में भी कामयाब रहा।
- इस रिएक्टर में शक्तिशाली मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल गर्म प्लाज्मा को फ्यूज करने और 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस के तापमान तक पहुंचा जाता है। यह सूरज की कोर से दस गुना ज्यादा गर्म है।
- प्रायोगिक रिएक्टर के पीछे वैज्ञानिकों का अगला लक्ष्य लंबे समय तक उच्च तापमान को बनाए रखना है।
- इससे पहले, EAST 2018 में 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस के रिकॉर्ड तापमान पर पहुंच गया था।
- यह भविष्य की तकनीक चीन के हरित विकास को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है और नया रिकॉर्ड कृत्रिम सूर्य बनाने की दिशा में एक छोटा कदम है।
- चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसने उच्च प्लाज्मा तापमान हासिल किया है। वर्ष 2020 में दक्षिण कोरिया के कोरिया सुपरकंडक्टिंग टोकामक एडवांस्ड रिसर्च (Korea Superconducting Tokamak Advanced Research) रिएक्टर ने 20 सेकंड के लिये 100 मिलियन डिग्री सेल्सियस से अधिक के प्लाज़्मा तापमान को बनाए रखते हुए एक नया रिकॉर्ड बनाया।

निष्कर्ष

- चीन के प्रयोगात्मक 'कृत्रिम सूर्य' के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।
- काम कर रहे रिएक्टर को अपने प्रायोगिक चरणों से उभरने में दशकों लगेंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- चांद पर परमाणु रिएक्टर लगाने की अमरीका की योजना
- रूस का तैरता परमाणु ऊर्जा संयंत्र

फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRBs) कैटलॉग का सबसे बड़ा संग्रह

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - विज्ञान और टेक

सुर्खियों में-

- पुणे स्थित टाटा इंस्टीट्यूट फॉर फंडामेंटल रिसर्च (TIFR) और नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स (NCRA) के शोधकर्ताओं ने फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRBs) कैटलॉग का सबसे बड़ा संग्रह इकट्ठा किया है।

- डेटा कैनेडियन हाइड्रोजन इंटेंसिटी मैपिंग एक्सपेरिमेंट (CHIME) से लिया गया है।

फास्ट रेडियो बर्स्ट (FRBs) के बारे में

- FRBs चमकदार फटने वाले होते हैं जिनकी अवधि मिलीसेकंड-स्केल में होती है, जिसके कारण उनका पता लगाना और आकाश में उनकी स्थिति निर्धारित करना मुश्किल होता है।
- इसे पहली बार 2007 में खोजा गया था।
- उनकी उत्पत्ति अज्ञात और उपस्थिति अत्यधिक अप्रत्याशित है।

चाइम (CHIME) के बारे में

- यह एक नया रेडियो टेलीस्कोप है जिसमें कोई गतिमान भाग नहीं होता है।
- इसे उच्च मानचित्रण गति के लिए अनुकूलित किया गया है।
- यह डोमिनियन रेडियो एस्ट्रोफिजिकल ऑब्जर्वेटरी, कनाडा में स्थित है।

FRBs के अध्ययन का महत्व

- इन परिघटनाओं का उपयोग ब्रह्मांड के बारे में लंबे समय से चले आ रहे कुछ सवालों के जवाब देने के लिए किया जाता है।
- इसका उपयोग ब्रह्मांड में पदार्थ की त्रि-आयामी संरचना को समझने के लिए किया जाता है।

पैसिफाइ (PASIPHAE) : अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना

बारे में

- 'पोलर-एरियाज़ स्टेलर-इमेजिंग इन पोलेराइज़ेशन हाई-एक्यूरेसी एक्सपेरीमेंट' अर्थात 'पैसिफाइ' एक अंतर्राष्ट्रीय सहयोगी आकाश सर्वेक्षण परियोजना है।
- इस प्रोजेक्ट के तहत, वैज्ञानिकों का लक्ष्य लाखों तारों से निकलने वाले प्रकाश में होने वाले ध्रुवीकरण या ध्रुवण (Polarisation) का अध्ययन करना है।
- इस परियोजना को संयुक्त राज्य अमेरिका, नॉर्वे, दक्षिण अफ्रीका और निजी फाउंडेशनों के विश्व के अग्रणी संस्थानों द्वारा वित्त पोषित किया गया है।
- इन तारों की दूरी GAIA उपग्रह (यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के) के मापन से प्राप्त की जाएगी।
- इन आंकड़ों का संयोजन करके, खगोलविद WALOP (वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलारिमीटर) नामक एक अत्याधुनिक पोलरिमीटर उपकरण के द्वारा विस्तृत आकाश क्षेत्रों के अंतर-तारकीय माध्यम की पहली चुंबकीय क्षेत्र टोमोग्राफी मैपिंग करेंगे।

वालोप (WALOP) क्या है?

- वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलारिमीटर (WALOP) एक उपकरण है, जिसे दो छोटे ऑप्टिकल टेलीस्कोप पर लगाया जाता है, जिसका उपयोग उच्च गेलेक्टिक अक्षांशों के साथ तारों से निकलने वाले ध्रुवीकृत प्रकाश संकेतों का पता लगाने के लिए किया जाएगा।
- क्रीत (ग्रीस) स्थित 1.3 मीटर स्किनकास ऑब्ज़र्वेटरी और साउथ अफ्रीकन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्ज़र्वेटरी के 1 मीटर टेलीस्कोप पर प्रत्येक में एक 'वाइड एरिया लीनियर ऑप्टिकल पोलारिमीटर' (WALOP) स्थापित किया जाएगा।
- 200 किलो वजनी वालोप उत्तरी और दक्षिणी आसमान में एक साथ मौजूद सैकड़ों तारों को देखने में सक्षम होगा।

PASIPHAE क्यों महत्वपूर्ण है?

- लगभग 14 अरब साल पूर्व अपने जन्म के बाद से, ब्रह्मांड लगातार विस्तार कर रहा है, जो कि कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड (CMB) विकिरण की उपस्थिति से सिद्ध हो चुका है।
- अपने जन्म के तुरंत बाद, ब्रह्मांड एक छोटी मुद्रास्फीति के चरण से गुजरने, जिसके दौरान यह धीमा होने और वर्तमान दर तक पहुंचने से पहले बहुत उच्च दर से विस्तारित हुआ।
- हालांकि, अभी तक प्रारंभिक ब्रह्मांड से जुड़े मुद्रास्फीति के केवल सिद्धांत और अप्रत्यक्ष प्रमाण ही रहे हैं।

- ब्रह्मांड की उत्पत्ति के आसपास के रहस्यों को PASIPHAE द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि की सहायता से सुलझाया जा सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- इन-स्पेस ऑफ इंडिया
- संयुक्त राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष संधि

सिंथेटिक बायोलॉजी और जैव सुरक्षा

संदर्भ: सिंथेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नैनो टेक्नोलॉजी जैसी घातीय प्रौद्योगिकियों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के सिद्धांत और व्यवहार को बदलने के लिए बाध्य है। COVID-19 ने अपरिहार्य को तेज कर दिया है।

- **अधूरी समझ :** पिछले दो दशकों में सिंथेटिक बायोलॉजी के तेजी से उदय और इसके अभी भी समझे जाने वाले निहितार्थों पर सुरक्षा अध्ययनों या नीति समुदायों से पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है।
- **जानबूझकर दुरुपयोग:** जबकि प्रौद्योगिकी अभी भी आसानी से सुलभ नहीं है, वह दिन दूर नहीं जब ऐसी प्रौद्योगिकियों तक पहुंचना मुश्किल नहीं होगा। विशेष रूप से महामारी के मद्देनजर, जैव सुरक्षा प्रणालियों की सावधानीपूर्वक समीक्षा करने की आवश्यकता है, जहां ऐसी प्रौद्योगिकियां उपयोग में हैं।
- **जैव हथियार:** प्रयोगशाला में कृत्रिम रूप से बनाए गए अत्यधिक संक्रामक रोगजनकों का उपयोग करके एक सुनियोजित हमला विनाशकारी हो सकता है। यह सुरक्षा प्रतिष्ठान से संबंधित होना चाहिए।
- **नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं जाता:** राष्ट्रीय सुरक्षा और सिंथेटिक बायोलॉजी के बीच संबंध को मुख्यधारा की राष्ट्रीय सुरक्षा बहस में एक एजेंडा आइटम बनना बाकी है। इसकी तुलना परमाणु हथियारों, सुविधाओं और सामग्री पर ध्यान देने के साथ करें।
- **अपर्याप्त अंतर्राष्ट्रीय विनियमन**
    - परमाणु डोमेन के विपरीत, सिंथेटिक बायोलॉजी अनुप्रयोगों में बढ़ती सैन्य रुचि और उनके संभावित दुरुपयोग के बावजूद जीव विज्ञान या सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्रों को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विनियमित नहीं किया जाता है।
- भारत विशिष्ट रूप से तैयार नहीं: खराब रोग निगरानी, जैव सुरक्षा मुद्दों से निपटने वाले विभिन्न सरकारी विभागों के बीच अपर्याप्त समन्वय, छिद्रयुक्त
- सीमाओं और गैर-प्रशिक्षित सीमा नियंत्रण संस्थानों और स्वास्थ्य प्रणाली की दयनीय स्थिति को देखते हुए, भारत रोगजनकों या खतरनाक जैविक जीवों के हमले से बचाव के लिए तैयार नहीं है।

आगे की राह

- नवंबर 2021 में, BTWC समीक्षा सम्मेलन क्षेत्र में प्रगति का जायजा लेना चाहिए, जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान और जैव-हथियार अनुसंधान के बीच की पतली रेखा को पता करके निगरानी और सत्यापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपायों पर विचार करना चाहिए।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- जैविक खतरे
- यूनिवर्सल बायो-डिटरेंस

मानव जीनोम का 100% अनुक्रमित

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस III - विज्ञान और तकनीक; जैव प्रौद्योगिकी

सुर्खियों में-

- टेलोमेरे-टू-टेलोमेयर (T2T) कंसोर्टियम, एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग के शोधकर्ताओं ने "पहले सही मायने में पूर्ण मानव संदर्भ जीनोम" का अनुक्रम किया है।

जीनोम अनुक्रमण और जीनोम के बारे में

- जीनोम अनुक्रमण का अर्थ है किसी व्यक्ति में आधार जोड़े के सटीक क्रम को समझना।
- जीनोम एक जीव का डीएनए का पूरा सेट है।
- मानव जीनोम में लगभग 3 अरब आधार जोड़े होते हैं।

जीनोम अनुक्रमण के लाभ

- दुर्लभ बीमारियों के जीनोमिक कारणों की पहचान करने में सहायता।
- वायरस कैसे फैलता है इसकी समझ में सुधार करना।
- आनुवंशिक उत्परिवर्तन की पहचान करना

जीनोम अनुक्रमण के लिए की गई विभिन्न पहल

- **स्वदेशी कार्यक्रम:** भारत से विविध जातीय समूहों का प्रतिनिधित्व करने वाले 1000 भारतीय व्यक्तियों के पूरे जीनोम अनुक्रमों को शुरू करने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा वित्त पोषित।
- जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जीनोम इंडिया परियोजना जिसका उद्देश्य पूरे भारत के नागरिकों से 10,000 आनुवंशिक नमूने एकत्र करना है।
- **मानव जीनोम परियोजना:** संपूर्ण मानव जीनोम के डीएनए अनुक्रम को निर्धारित करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय शोध। यह 1999 में शुरू हुआ और 2003 में पूरा हुआ।

महाराष्ट्र में नए डॉपलर रडार: IMD

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - प्रौद्योगिकी का स्वदेशीकरण

सुर्खियों में-

- हाल ही में, भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने घोषणा की कि वह 2021 में मुंबई सहित महाराष्ट्र में सात नए डॉपलर रडार स्थापित करेगा।
    - जनवरी 2021 में केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने हिमालय पर मौसम परिवर्तन की सूक्ष्मता से निगरानी करने हेतु स्वदेशी रूप से निर्मित दस में से दो एक्स-बैंड डॉप्लर वेदर रडार (Doppler Weather Radars- DWR) को चालू किया।

डॉपलर रडार के बारे में

- यह एक विशेष रडार है जो एक दूसरे से कुछ दूरी पर स्थित वस्तुओं के वेग से संबंधित आँकड़ों को एकत्रित करने के लिये डॉप्लर प्रभाव का उपयोग करता है।
    - डॉप्लर प्रभाव: किसी तरंग स्रोत तथा प्रेक्षक के मध्य सापेक्षिक गति के कारण प्रेक्षक को तरंग की आवृत्ति बदली हुई प्रतीत होती है। तरंग की आवृत्ति में इस आभासी परिवर्तन को डॉप्लर प्रभाव कहते हैं।
    - यह एक वांछित लक्ष्य (वस्तु) को माइक्रोवेव सिग्नल के माध्यम से लक्षित करता है और विश्लेषण करता है कि लक्षित वस्तु की गति ने वापस आने वाले सिग्नलों की आवृत्ति को कैसे बदल दिया है।
- डॉपलर सिद्धांत के आधार पर रडार को एक पैराबॉलिक डिश एंटीना और फोम सैंडविच गोलाकार रेडोम का उपयोग करके लंबी दूरी के मौसम पूर्वानुमान और निगरानी में सटीकता में सुधार करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
- DWR में वर्षा की तीव्रता, वायु प्रवणता और वेग को मापने के उपकरण लगे होते हैं जो चक्रवात के केंद्र और धूल के बवंडर की दिशा के बारे में सूचित करते हैं।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के बारे में

- यह 1875 में स्थापित पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक एजेंसी है।
- यह मौसम संबंधी प्रेक्षणों, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान के लिए जिम्मेदार प्रमुख एजेंसी है।

रोबो सेपियन्स: काम का भविष्य

संदर्भ: मैकिन्से द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि अंततः यह उन नौकरियों के बजाय गतिविधियाँ हैं जिन्हें स्वचालित किया जा रहा है जहाँ $2tn मजदूरी है या यूएस में 45% कार्य गतिविधियां पहले से ही मौजूदा तकनीकों के साथ स्वचालित हो सकती हैं।

रोबोट/ऑटोमेशन के उद्भव से संबंधित चिंताएँ

- **रचनात्मक कौशल पर प्रीमियम:** व्यावसायिक समूहों के भीतर नौकरियों की मांग में वृद्धि होगी, जिसमें दोहराव, कम निपुणता कौशल के विपरीत सामाजिक बुद्धिमत्ता, रचनात्मकता और जटिल समस्या समाधान की आवश्यकता होती है।
- **नौकरी का नुकसान:** अगले 20 वर्षों में कंप्यूटरीकरण से 47% तक अमेरिकी नौकरियां खतरे में पड़ सकती हैं। वहीं इमर्जिंग मार्केट्स में यह आंकड़ा 85 फीसदी तक पहुंच सकता है।
- **भारत आईटी क्षेत्र की नौकरियों पर प्रभाव:** भारत स्थित आईटी आउटसोर्सर, जिन्होंने 1991 के सुधारों के बाद विकास का नेतृत्व किया, रोबोट प्रक्रिया स्वचालन के कारण 2022 तक वैश्विक स्तर पर 'कम कुशल' भूमिकाओं में 3 मिलियन आरपीए अपस्किलिंग 30% की कमी की योजना बना रहे हैं। यह कम वेतन लागत में $ 100 बिलियन का प्रतिनिधित्व करता है।
- **कामगार विवाद:** मानव के लिए काम की प्रकृति में परिवर्तन हो रहा है उदाहरण के लिए हाल के दशक में 9 से 5 रोजगार के बजाय गिग नौकरियों में वृद्धि देखी गई। रोबोटों का उदय मानव नौकरियों की प्रकृति को बदलने के लिए भी बाध्य है जो बीमार/ओवरटाइम वेतन, बीमा, श्रमिकों के अधिकारों आदि के आसपास नियामक विवादों को जन्म दे सकता है।
- **श्रम और प्रौद्योगिकी के बीच वैश्विक संबंध:** यह डिस्कनेक्ट 20वीं सदी की विक्टोरियन युग की शिक्षा पद्धतियों के कारण है, जो तेजी से बदलते 21वीं सदी के कार्यस्थल के अनुरूप नहीं हैं।
- नई नौकरियों में संक्रमण के लिए इस दशक में लगभग 100 मिलियन यूरोपीय लोगों को नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है। भविष्य के कौशल स्पष्ट रूप से कुछ हद तक तकनीक-केंद्रित होंगे लेकिन सॉफ्ट स्किल्स की भी आवश्यकता होगी।
- **सरकारों पर फिर से कौशल का बोझ:** इस दशक में लगभग 100 मिलियन यूरोपीय लोगों को नए कौशल हासिल करने की आवश्यकता हो सकती है।
- पुनर्प्रशिक्षण का एक क्षेत्र जीवाश्म से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक हो सकता है, जहां अमेरिका में, 90,000 कोयला श्रमिकों को सौर ऊर्जा में काम करने के लिए फिर से प्रशिक्षित करने में सिर्फ 180 मिलियन डॉलर खर्च हो सकते हैं।

निष्कर्ष

- आजीवन सीखने, कॉर्पोरेट प्रशिक्षण और विकास, व्यावसायिक शिक्षा, और बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन पाठ्यक्रम (MOOCs) भी भविष्य में रोजगार की संभावनाओं के लिए महत्वपूर्ण उपकरण होंगे।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस
- ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी और मतदान

अन्य सेवा प्रदाताओं (OSPs) के लिए दिशानिर्देश

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III- दूरसंचार

सुर्खियों में-

- हाल ही में, दूरसंचार विभाग (DoT) ने अन्य सेवा प्रदाताओं (OSPs) के लिए मानदंडों को अधिक उदार बनाया है।

नई नीति की महत्वपूर्ण विशेषताएं

- घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय OSP के बीच के अंतर को हटा दिया गया है। सामान्य दूरसंचार संसाधनों वाला एक BPO केंद्र अब भारत में पूरे विश्व के ग्राहकों को सेवा प्रदान करने में सक्षम होगा।
- अब, सभी प्रकार के OSP केंद्रों के बीच इंटरकनेक्टिविटी की अनुमति है।
- OSP का इलेक्ट्रॉनिक निजी स्वचालित शाखा एक्सचेंज (EPABX) अब दुनिया में कहीं भी स्थित हो सकता है।
- OSP की अवधि के आधार पर दूरसंचार विभाग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त कर दिया।

अन्य प्रावधान

- OSP को किसी भी पंजीकरण की आवश्यकता से छूट।
    - कोई बैंक गारंटी नहीं दी जानी है।
    - वर्क फ्रॉम होम और वर्क फ्रॉम एनीवेयर की भी अनुमति है।
    - उल्लंघन के जुर्माने को पूरी तरह से हटा दिया गया।

लाभ

- इस कदम से BPO क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने के साथ-साथ रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- नए दिशानिर्देश व्यापार करने में आसानी से भारत के आकर्षण को बढ़ाएंगे,

बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (BPO) के बारे में

- BPO एक ऐसा व्यावसाय है जिसमें एक संगठन एक बाह्य सेवा प्रदाता के साथ एक आवश्यक व्यावसायिक कार्य करने के लिये अनुबंध करता है।
- OSPs या अन्य सेवा प्रदाता ऐसी कंपनियाँ या फर्म होती हैं जो विभिन्न कंपनियों, बैंकों या अस्पताल शृंखलाओं के लिये क्रमशः टेलीमार्केटिंग, टेलीबैंकिंग या टेलीमेडिसिन जैसी माध्यमिक या तृतीयक सेवाएँ प्रदान करती हैं।

2020 में अक्षय विद्युत उत्पादन लागत: IRENA

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध और जीएस-III - नवीकरणीय संसाधन

सुर्खियों में-

- हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी (IRENA) ने '2020 में अक्षय ऊर्जा उत्पादन लागत' रिपोर्ट जारी की।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- कुल वैश्विक ऊर्जा क्षमता के 38% की अब नई उपयोगिता-स्तरीय फोटोवोल्टिक और तटवर्ती पवन ऊर्जा की तुलना में अधिक परिचालन लागत है।
- पिछले साल जोड़े गए कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के लगभग 162 गीगावॉट या 62 फीसदी की लागत सबसे सस्ते जीवाश्म ईंधन विकल्प की तुलना में कम थी।
- **वृद्धि का कारण था**
    - प्रौद्योगिकियों में प्रगति,
    - घटक लागतों में लगातार गिरावट,
    - लागत-प्रतिस्पर्धी आपूर्ति वितरण चैनल,
    - उपयोग करके सीखना
    - वाणिज्यिक पैमाने पर उपलब्धता।

अक्षय ऊर्जा के लिए भारतीय पहल

- हाइड्रोजन ऊर्जा मिशन।
- जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन (JNNSM)।

- अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन।
- पीएम- कुसुम।
- राष्ट्रीय पवन-सौर हाइब्रिड नीति।
- रूफटॉप सोलर योजना।

अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी के बारे में

- यह एक अंतर सरकारी संगठन है, जिसे आधिकारिक तौर पर जनवरी 2009 में बॉन, जर्मनी में स्थापित किया गया था।
- वर्तमान में इसके 164 सदस्य हैं, भारत IRENA का 77वां संस्थापक सदस्य है।
- **मुख्यालय:** अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात।
- **प्रमुख कार्य:**
    - यह देशों को एक स्थायी ऊर्जा भविष्य के लिए उनके संक्रमण में समर्थन करता है।
    - यह अक्षय ऊर्जा के सभी रूपों को व्यापक रूप से अपनाने और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देता है।

विश्व का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित रबड़: असम

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस-III - विज्ञान और तकनीक

सुर्खियों में-

- असम में, रबर बोर्ड द्वारा गुवाहाटी के पास सरुतारी में बोर्ड के फार्म पर दुनिया का पहला आनुवंशिक रूप से संशोधित (GM) रबर का पौधा लगाया गया है। GM रबर का पौधा भारतीय रबड़ अनुसंधान संस्थान (RRII), पुथुपल्ली, कोट्टायम, केरल में विकसित किया गया था।

GM रबर के बारे में

- आनुवंशिक संशोधन (GM) प्रौद्योगिकी में प्रयोगशाला तकनीकों का उपयोग कर प्रजातियों के बीच विशिष्ट लक्षणों के लिये जीन को स्थानांतरित किया जाता है।
- इस रबड़ में मैंगनीज युक्त सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज़ (MnSOD) जीन को अंतर्वेशित कराया गया है जिसके चलते यह उत्तर-पूर्व में शीतऋतु में पड़ने वाली कड़ाके की ठंड का मुकाबला करने में सक्षम होगी।

ऐसा क्यों किया जाता है?

- प्राकृतिक रबड़ उष्ण आर्द्र अमेज़न वनों की मूल प्रजाति है और पूर्वोत्तर की शीत परिस्थितियों के लिये स्वाभाविक रूप से अनुकूल नहीं है, जो भारत में रबड़ के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है।
    - शीतकाल के दौरान मृदा के लगातार शुष्क बने रहने के कारण रबर के पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यही कारण है कि इस क्षेत्र में रबड़ के पौधों के परिपक्व होने की अवधि लंबी होती है।

प्राकृतिक रबर के बारे में

- रबर हेविया ब्रासिलिएन्सिस (Hevea Brasiliensis) नामक वृक्ष के लेटेक्स से बनाया जाता है।
- यह एक भूमध्यरेखीय फसल है, लेकिन विशेष परिस्थितियों में इसे उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में भी उगाया जाता है।
- **तापमान:** नम और आर्द्र जलवायु के साथ 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर।
- **वर्षा:** 200 सेमी से अधिक।
- **मिट्टी का प्रकार:** अच्छी जल निकासी वाली समृद्ध जलोढ़ मिट्टी।
- इस रोपण फसल के लिए कुशल श्रम की सस्ती और पर्याप्त आपूर्ति की आवश्यकता है।
- भारत वर्तमान में उच्चतम उत्पादकता (वर्ष 2017-18 में 694,000 टन) के साथ विश्व में प्राकृतिक रबड़ का छठा सबसे बड़ा उत्पादक है।

- **शीर्ष रबड़ उत्पादक राज्य:** केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक।
- **सरकारी पहल:**
    - रबड़ प्लांटेशन डेवलपमेंट स्कीम और रबड़ ग्रुप प्लांटिंग स्कीम रबड़ के लिये सरकार के नेतृत्व वाली पहल के उदाहरण हैं। रबर, कॉफी, चाय, इलायची, ताड़ के वृक्ष और जैतून के वृक्षारोपण में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति है।
- **विश्व स्तर पर प्रमुख उत्पादक:** थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, चीन और भारत।
- **प्रमुख उपभोक्ता:** चीन, भारत, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया।

आपदा प्रबंधन

ग्लोबल वार्मिंग के कारण लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास समुद्र जल स्तर में वृद्धि

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - पर्यावरण; संरक्षण;जलवायु परिवर्तन

सुर्खियों में-

- हाल ही में एक अध्ययन में अनुमान लगाया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव के कारण लक्षद्वीप द्वीप समूह के आसपास समुद्र का स्तर बढ़ जाएगा।
- यह पहली बार है कि अरब सागर में लक्षद्वीप द्वीपसमूह के द्वीपसमूह पर बाढ़ के संभावित क्षेत्रों का आकलन करने के लिए जलवायु मॉडल अनुमानों का उपयोग किया गया था।

अध्ययन के मुख्य तथ्य

- यह हवाई अड्डे और आवासीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा जो वर्तमान समुद्र तट के काफी पास हैं।
- सभी उत्सर्जन परिदृश्यों के तहत एंड्रोथ द्वीप पर समुद्र के स्तर में वृद्धि के प्रभावों का सबसे कम प्रभाव देखा गया है।

तटीय बाढ़ का प्रभाव

- इसका व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव हो सकता है।
- समुद्र के स्तर में वृद्धि के कारण अनुमानित बाढ़ द्वीपवासियों को प्रभावित कर सकती है क्योंकि आवासीय क्षेत्र वर्तमान समुद्र तट के काफी नजदीक हैं।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- योजना संबंधी दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उपयुक्त तटीय सुरक्षा उपायों और सर्वोत्तम प्रथाओं का होना आवश्यक है।

महत्वपूर्ण मूल्यवर्धन

समुद्र के स्तर में वृद्धि (SLR)

- SLR जलवायु परिवर्तन, विशेष रूप से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के कारण विश्व के महासागरों के स्तर में हुई वृद्धि है।
- **SLR तीन प्राथमिक कारकों से होता है:**
    - थर्मल विस्तार
    - पिघलते ग्लेशियर
    - ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका की बर्फ की चादरों का नुकसान।
- **SLR के परिणाम:**
    - तटीय बाढ़
    - तटीय जैव विविधता का खंडन
    - खतरनाक तूफान सर्जेस
    - पार्श्व और अंतर्देशीय प्रवास
    - अवसंरचना पर प्रभाव
    - अंतर्देशीय जीवन के लिए खतरा

भारत के प्रयास

- तटीय विनियमन क्षेत्र
- **जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना**
    - इसे 2008 में प्रधान मंत्री की जलवायु परिवर्तन परिषद द्वारा शुरू किया गया था।
    - इसका उद्देश्य जनता के प्रतिनिधियों, सरकार की विभिन्न एजेंसियों, वैज्ञानिकों, उद्योग और समुदायों के बीच जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरे और इसका सामना करने के कदमों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

यूएस हीट वेव

संदर्भ: हाल ही में, यूएस वेदर सर्विस ने वाशिंगटन राज्य और उत्तर पूर्व के अधिकांश हिस्सों के लिए अत्यधिक गर्मी की चेतावनी जारी की है।

- देश के अधिकांश हिस्सों में, "हीट वेव" लेबल को गर्म अवधि पर लागू करने से पहले दो या अधिक दिनों के लिए तापमान ऐतिहासिक औसत से ऊपर होना चाहिए।
- लेकिन परिभाषा क्षेत्र के अनुसार भिन्न हो सकती है; पूर्वोत्तर संयुक्त राज्य अमेरिका में, इसे 90 या उससे ऊपर के सीधे तीन दिनों के रूप में परिभाषित किया गया है।

गर्मी की लहर का क्या कारण है?

- गर्मी की लहरें तब शुरू होती हैं जब वायुमंडल में उच्च दबाव अंदर जाता है और गर्म हवा को जमीन की ओर धकेलता है। संपीड़ित होने पर वह हवा और गर्म हो जाती है और हम बहुत अधिक गर्म महसूस करने लगते हैं।
- जमीन पर नीचे दबने वाला उच्च दबाव प्रणाली लंबवत रूप से फैलती है, जिससे अन्य मौसम प्रणालियों को पाठ्यक्रम बदलने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यह हवा और बादलों के आवरण को भी कम करता है, जिससे हवा अधिक कठोर हो जाती है।
- यही कारण है कि एक गर्मी की लहर कई दिनों या उससे अधिक समय तक एक क्षेत्र में खड़ी रहती है।

एक हीट डोम क्या है?

- जैसे-जैसे जमीन गर्म होती है, वह नमी खो देती है, जिससे उसे और भी गर्म करना आसान हो जाता है। और सूखाग्रस्त पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में, उच्च दबाव प्रणाली को फंसाने के लिए बहुत अधिक गर्मी है।

उत्तरी अमेरिका में सामान्य से अधिक गर्म क्यों है?

- हम लंबे समय से जानते हैं कि 1900 के बाद से दुनिया 1 डिग्री सेल्सियस (लगभग 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट) से अधिक गर्म हो गई है, और हाल के दशकों में वार्मिंग की गति तेज हो गई है।
- गर्म आधार रेखा चरम-मौसम की घटनाओं में योगदान करती है और अत्यधिक गर्मी की अवधि को अधिक बार, लंबी और अधिक तीव्र बनाने में मदद करती है।
- शहरी क्षेत्रों में पक्की और ठोस सतहों का आवर्धित प्रभाव और वृक्षों के आवरण की कमी।
- शहरी गर्मी द्वीप प्रभाव परिवेश के तापमान को उनकी तुलना में 3 से 4 डिग्री अधिक महसूस करा सकते हैं।

हीट वेव्स के स्वास्थ्य प्रभाव

- हीट वेव्स के स्वास्थ्य प्रभावों में आमतौर पर निर्जलीकरण, हीट क्रैम्प्स, हीट थकावट /या हीट स्ट्रोक शामिल होते हैं।
- यह गर्मी में ऐंठन, थकान, कमजोरी, चक्कर आना, सिरदर्द, मतली, उल्टी, मांसपेशियों में ऐंठन और पसीना आने का कारण भी बनता है।
- अत्यधिक तापमान और परिणामी वायुमंडलीय स्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे शारीरिक तनाव का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मृत्यु हो जाती है।

आगे की राह

- जबकि जलवायु परिवर्तन का संलग्न मौसम की घटनाओं के साथ एक मजबूत संबंध है, यह संलग्न मौसम की घटनाओं का कारण नहीं है। जैसे-जैसे जलवायु परिवर्तन तेज होता है, गर्मी की लहरों के एपिसोड आम होते जा रहे हैं। इसलिए, यदि वैश्विक समुदाय भविष्य में कम उत्सर्जन परिदृश्य को अपनाता है और उसका पालन करता है, तो हीटवेव की तीव्रता और आवृत्ति को कम किया जा सकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगल की आग
- अमेज़न वर्षावन की आग

रक्षा/ आंतरिक सुरक्षा

परियोजना P 75 (I) के तहत पारंपरिक पनडुब्बियों का निर्माण स्वीकृत

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) ने प्रोजेक्ट-75 इंडिया के अंतर्गत छह पारंपरिक पनडुब्बियों (Conventional Submarines) के निर्माण के लिये प्रस्ताव हेतु अनुरोध (RFP) जारी करने को मंज़ूरी दे दी है।

यह परियोजना किस बारे में है?

- इस परियोजना में 43,000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से अत्याधुनिक वायु स्वतंत्र प्रणोदन प्रणाली से लैस छह पारंपरिक पनडुब्बियों के स्वदेशी निर्माण की परिकल्पना की गई है।
- SP मॉडल के तहत संसाधित होने वाला यह पहला मामला है।
- रक्षा खरीद प्रक्रिया (DPP) के SP मॉडल का उद्देश्य घरेलू रक्षा औद्योगिक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण और भारतीय उद्योग की भूमिका को बढ़ावा देना है।
- यह सबसे बड़ी 'मेक इन इंडिया' परियोजनाओं में से एक होगी।

सामरिक भागीदारी (SP) मॉडल क्या है?

- SP मॉडल कुछ भारतीय निजी कंपनियों को सामरिक भागीदारों के रूप में चिन्हित करेगा जो रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए कुछ चयनित विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEMs) के साथ भागीदारी करेंगे।
- SP और उनके विदेशी OEMs भागीदारों का चयन एक साथ शुरू की जाने वाली प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया पर आधारित होगा।
- रक्षा मंत्रालय (MoD) कुछ तकनीकी, वित्तीय और बुनियादी ढांचे से संबंधित मापदंडों के आधार पर प्रत्येक खंड में भारतीय कंपनियों की एक सूची की पहचान करेगा।

रक्षा क्षेत्र में हालिया सुधार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - सुरक्षा

सुर्खियों में-

- हाल ही में, रक्षा मंत्री ने 2020 में रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा किए गए प्रमुख सुधारों पर प्रकाश डालते हुए '2020 में 20 सुधार' शीर्षक से एक ई-पुस्तिका का विमोचन किया।
- **संरचनात्मक सुधार:** चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (CDS) का पद सशस्त्र बलों के बीच दक्षता और समन्वय बढ़ाने और दोहराव को कम करने के लिए बनाया गया था, जबकि सैन्य मामलों के विभाग (DMA) की स्थापना नागरिक-सैन्य एकीकरण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए की गई थी।
- **स्वदेशीकरण को बढ़ावा:** रक्षा क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' को बढ़ावा देने के लिये अगस्त 2020 में 101 रक्षा मदों की सूची अधिसूचित की गई थी, जबकि सितंबर 2020 में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 का अनावरण किया गया था। 2020-21 में स्वदेश निर्मित रक्षा उपकरणों के लिये 52,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था।
- **वित्त पोषण:** पिछले वर्ष की तुलना में 2020-21 में बजट में 10% की वृद्धि हुई थी।
- **नवाचार को बढ़ावा देना:** युवाओं द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिये वर्ष 2020 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) की पाँच युवा वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं को शुरू किया गया।
- **डिजिटाइज़िंग ट्रिब्यूनल:** सशस्त्र बल न्यायाधिकरण ने अगस्त 2020 में पहली बार डिजिटल सुनवाई शुरू की।
- **सामरिक संपर्क:** लेह-मनाली राजमार्ग पर रोहतांग में 10,000 फीट से अधिक ऊँचाई पर विश्व की सबसे लंबी सुरंग 'अटल सुरंग' का उद्घाटन किया गया।

- **सशस्त्र बलों में स्त्री शक्ति:** भारतीय सेना के दस शाखाओं में शॉर्ट सर्विस कमीशन (Short Service Commission-SSC) महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान कर दिया गया, जबकि भारतीय नौसेना में पहली बार महिला पायलटों की शुरुआत की गई।
- शैक्षणिक सत्र 2020-21 से सभी सैनिक स्कूल छात्राओं के लिये खोल दिये गए।
- **NCC:** राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC) की पहुंच को दूरस्थ स्थानों तक पहुंचाना एक बड़ी घोषणा थी।

रक्षा उत्कृष्टता के लिए नवाचार

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- हाल ही में रक्षा मंत्री ने अगले पाँच वर्षों के लिये रक्षा नवाचार संगठन (Defence Innovation Organisation- DIO) के तहत रक्षा उत्कृष्टता के लिये नवाचार (Innovations for Defence Excellence- iDEX) चुनौती हेतु 498.8 करोड़ रुपए के बजटीय समर्थन को मंज़ूरी दी है।

iDEX के बारे में

- इसे अप्रैल 2018 में प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया।
- इसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करना तथा रक्षा और एयरोस्पेस में नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है।
- यह MSMEs, स्टार्ट-अप, व्यक्तिगत नवप्रवर्तनकर्ताओं, अनुसंधान एवं विकास संस्थानों और शिक्षाविदों सहित उद्योगों को संलग्न करता है।
- **वित्त पोषित और प्रबंधित: DIO**
    - यह DIO की कार्यकारी शाखा के रूप में भी कार्य करता है।
    - DIO कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत पंजीकृत एक 'लाभ के लिए नहीं' कंपनी है।
    - **संस्थापक सदस्य:** हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) - रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (DPSUs)।
- यह आकर्षक उद्योगों को अनुसंधान और विकास करने के लिए वित्त पोषण और अन्य सहायता प्रदान करेगा।
- iDEX चुनौतियों के विजेताओं को हैंड होल्डिंग, तकनीकी सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए iDEX ने देश में अग्रणी इन्क्यूबेटरों के साथ भागीदारी की है।

परमाणु शस्त्रागार का वैश्विक विस्तार: SIPRI रिपोर्ट

भाग-जीएस प्रीलिम्स और जीएस-II- अंतर्राष्ट्रीय संबंध

सुर्खियों में-

- SIPRI इयरबुक 2021 में प्रकाशित एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, विश्व स्तर पर तैयार और तैनात परमाणु हथियारों की संख्या में वृद्धि हुई है।
    - SIPRI इयरबुक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (Stockholm International Peace Research Institute- SIPRI) द्वारा जारी की जाती है जो अंतर्राष्ट्रीय आयुध और संघर्ष पर शोध करता है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें

- वैश्विक सैन्य भंडार में आयुधों की कुल संख्या अब बढ़ती हुई प्रतीत होती है।
- चीन की स्थिति एक महत्त्वपूर्ण आधुनिकीकरण और परमाणु हथियार सूची के विस्तार के बीच स्थित है।
- नौ परमाणु हथियार संपन्न राज्य - यू.एस., रूस, यू.के., फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इज़राइल और उत्तर कोरिया।
    - 2021 की शुरुआत में इन देशों के पास अनुमानित 13,080 परमाणु हथियार थे।

    - रूस और यू.एस. के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं।
- पांच सबसे बड़े हथियार आयातक: सऊदी अरब, भारत, मिस्र, ऑस्ट्रेलिया और चीन।
    - कुल हथियारों के आयात में इनका हिस्सा कुल मिलाकर 36% था।

युद्ध इतिहास के अवर्गीकरण संबंधी नीति

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- II - नीतियां और हस्तक्षेप और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- केंद्रीय रक्षा मंत्री ने रक्षा मंत्रालय (MoD) द्वारा युद्ध और संचालन इतिहास के संग्रह, अवर्गीकरण, संकलन और प्रकाशन पर एक नीति को मंजूरी दी है।
    - सीखे गए सबक का विश्लेषण करने और भविष्य की गलतियों को रोकने के लिए के. सुब्रह्मण्यम और एन.एन. वोहरा समिति की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति (Kargil Review Committee) द्वारा अवर्गीकरण पर स्पष्ट नीति के साथ युद्ध इतिहास लिखने के प्रस्ताव की सिफारिश की गई थी।
- युद्ध के इतिहास का समय पर प्रकाशन लोगों को घटनाओं का सटीक लेखा-जोखा देगा, अकादमिक शोध में मदद करेगा और निराधार अफवाहों का सामना करेगा।

महत्वपूर्ण तथ्य

- संयुक्त सचिव, रक्षा मंत्रालय की अध्यक्षता में युद्ध और संचालन इतिहास के संकलन के लिए एक समिति का गठन किया जाएगा।
- 25 वर्ष से अधिक पुराने अभिलेखों का अभिलेखीय विशेषज्ञों द्वारा मूल्यांकन किया जाना चाहिये और युद्ध/ऑपरेशन इतिहास संकलित होने के बाद उन्हें भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार में स्थानांतरित कर दिया जाना चाहिये।
- वर्ष 1962 के युद्ध जैसे पुराने युद्धों और ऑपरेशन्स से संबंधित दस्तावेज़ों का अवर्गीकरण (Declassification) स्वचालित नहीं होता है, बल्कि नई नीति के तहत गठित समिति द्वारा मामले की संवेदनशीलता के आधार निर्णय लिया जाएगा।

OFB निगमीकरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) के निगमीकरण की योजना को मंजूरी दी।
- OFB के 41 कारखाने हैं जो रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) की तर्ज पर सात पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाली कॉर्पोरेट संस्थाओं में विभाजित होंगे।
- एक बार लागू होने के बाद, OFB का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा।
- कर्मचारियों की सेवा शर्तों में कोई बदलाव नहीं होगा।

अनुमोदन के लाभ

- रक्षा निर्माण में देश को आत्मनिर्भर बनाएं
- आयुध कारखानों को उत्पादक और लाभदायक संपत्तियों में बदलना
- उत्पाद श्रृंखला में गहन विशेषज्ञता
- बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा
- बेहतर गुणवत्ता
- अक्षम आपूर्ति श्रृंखलाओं को समाप्त करने जैसी विभिन्न मौजूदा कमियों को दूर करने में मदद करें

साइबर धोखाधड़ी के लिए हेल्पलाइन शुरू

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - साइबर सुरक्षा

सुर्खियों में-

- गृह मंत्रालय ने साइबर धोखाधड़ी के कारण होने वाले वित्तीय नुकसान को रोकने के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन 155260 और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म का संचालन किया है।
    - साइबर धोखाधड़ी एक ऐसा अपराध है जो कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन संग्रहीत किसी अन्य व्यक्ति की व्यक्तिगत और वित्तीय जानकारी को भ्रष्ट करने के इरादे से किया जाता है।
- राष्ट्रीय हेल्पलाइन और रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म साइबर धोखाधड़ी में ठगे गए व्यक्तियों को ऐसे मामलों की रिपोर्ट करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है ताकि उनकी मेहनत की कमाई को नुकसान से बचाया जा सके।
- साथ ही, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक के कार्यालय द्वारा एक राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा रणनीति 2020 तैयार की जा रही है।

पहल के बारे में

- भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, सभी प्रमुख बैंकों, भुगतान बैंकों, वॉलेट और ऑनलाइन व्यापारियों के समन्वय से हेल्पलाइन को शुरु किया गया है।
- इसे I4C द्वारा कानून प्रवर्तन एजेंसियों और बैंकों और वित्तीय मध्यस्थों को एकीकृत करने के लिए विकसित की गई है।
- यह सुविधा बैंकों और पुलिस दोनों को सशक्त बनाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C)

- I4C की स्थापना योजना को अक्टूबर 2018 में मंजूरी दी गई थी।
- यह सभी प्रकार के साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटता है।
- **इसके सात घटक हैं:**
    - नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट
    - राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल
    - राष्ट्रीय साइबर अपराध प्रशिक्षण केंद्र
    - साइबर अपराध पारिस्थितिकी तंत्र प्रबंधन इकाई
    - राष्ट्रीय साइबर अपराध अनुसंधान और नवाचार केंद्र
    - राष्ट्रीय साइबर अपराध फोरेंसिक प्रयोगशाला पारिस्थितिकी तंत्र
    - संयुक्त साइबर अपराध जांच दल प्लेटफॉर्म।
- यह अत्याधुनिक केंद्र दिल्ली में स्थित है।

साइबर अपराध से निपटने के लिए अन्य पहलें

- नागरिकों के डेटा को सुरक्षित करने के लिए व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2018 का मसौदा तैयार करें।
- साइबर स्वच्छता केंद्र
- भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल (CERT-IN)

क्रिवाक स्टील्थ फ्रिगेट्स

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस -III - साइबर सुरक्षा

सुर्खियों में-

- हाल ही में, नौसेना स्टाफ के उप-प्रमुख ने क्रिवाक या तलवार वर्ग के दूसरे युद्धपोत के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया है।
    - पहले युद्धपोत का निर्माण कार्य जनवरी 2021 में शुरू किया गया था। इसे वर्ष 2026 में डिलीवर किया जाना है, जबकि दूसरे युद्धपोत को इसके छह महीने बाद डिलीवर किया जाएगा।

क्रिवाकी के बारे में

- 'मेक इन इंडिया' के तहत गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (GSL) द्वारा रूस से प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ क्रिवाक श्रेणी के स्टील्थ जहाजों का निर्माण किया जा रहा है।
    - जहाजों के इंजनों की आपूर्ति यूक्रेन द्वारा की जाती है।
    - अक्टूबर 2016 में, भारत और रूस ने चार क्रिवाक या तलवार स्टील्थ फ्रिगेट्स के लिए एक अंतर-सरकारी समझौते (IGA) पर हस्ताक्षर किए।
    - पहले दो युद्धपोत रूस के कैलिनिनग्राद में यंतर शिपयार्ड में बनाए जाएंगे, जबकि अन्य दो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में बनाए जाएंगे।
- नए क्रिवाक फ्रिगेट में वही इंजन और आर्मामेंट कॉन्फिगरेशन मौजूद हैं जो यंतर शिपयार्ड में निर्मित तीन युद्धपोतों - आईएनएस तेग, तरकश और त्रिकंद में शामिल हैं।
- ये ब्रह्मोस एंटी-शिप और लैंड अटैक मिसाइलों से लैस होंगे।
- **उपयोग:**
    - दुश्मन की पनडुब्बियों और बड़े सतह के जहाजों को खोजने और नष्ट करने जैसे विभिन्न प्रकार के नौसैनिक मिशनों को पूरा करें।

सेना ने 1,750 फ्यूचरिस्टिक इन्फैंट्री लड़ाकू वाहनों के लिए निविदा जारी की

भाग- जीएस प्रीलिम्स और जीएस- III - रक्षा और सुरक्षा

सुर्खियों में-

- भारतीय सेना ने सेवा में रूसी मूल के पैदल सेना के वाहनों को बदलने के लिए 1,770 उन्नत मुख्य युद्धक टैंकों को शामिल करने के लिए प्रस्तावित मेगा 'मेक इन इंडिया' परियोजना के लिए अनुरोध आरएफआई (Request For Information) जारी किया है।
    - नए पैदल सेना वाहन की खरीद के लिए सेना का यह तीसरा प्रयास है।
- इस महीने की शुरुआत में, 2030 से नियोजित प्रेरण के साथ अगली पीढ़ी के मुख्य युद्धक टैंक की खरीद के लिए 1770 फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल (FRCV) की खरीद के लिए एक आरएफआई भी जारी किया गया था।

RFI के बारे में

- सेना द्वारा तीन चरण का एक प्रेरण मॉडल प्रस्तावित किया गया है और भारतीय विक्रेता विदेशी मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के साथ अनुबंध के दो साल के भीतर प्रति वर्ष 75-100 वाहनों की दर से FICV की आपूर्ति करने के लिए सहयोग कर सकते हैं,
- **RFI के अनुसार, FICV को निम्नलिखित के लिए नियोजित किया जाएगा: क्रॉस-कंट्री ऑपरेशन्स में:**
    - पश्चिमी सीमाओं और उच्च ऊंचाई के साथ मैदानी और रेगिस्तानी इलाके, 5,000 वर्ग मीटर तक
    - पूर्वी लद्दाख में उत्तरी सीमाओं के साथ पर्वतीय भूभाग,
    - मध्य भारत
    - उत्तरी सिक्किम
- वे 1980 के दशक के पुराने रूसी मूल के BMP-2 की जगह लेंगे।
- FICV द्वारा किए जाने वाले मुख्य परिचालन कार्यों में नष्ट करना शामिल है:

- दुश्मन टैंक
- बख्तरबंद कार्मिक वाहक
- लड़ाकू वाहन
- कम उड़ान वाले हेलीकाप्टर
- अन्य जमीन पर आधारित हथियार प्लेटफॉर्म और स्थिति।

- FRCV प्लेटफॉर्म को रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया 2020 के 'रणनीतिक भागीदारी' मार्ग के तहत खरीदने की योजना है।
- FRCV को मध्यम वजन के टैंक के रूप में परिकल्पित किया गया है और यह सेना के MBT के रूप में अगले 40-50 वर्षों तक सेवा में रहेगा।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स

संदर्भ: चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत ने सशस्त्र बलों के उप प्रमुखों और कई मंत्रालयों के सरकारी प्रतिनिधियों के साथ बैठक की और एकीकृत थिएटर कमांड के मॉडल का प्रस्ताव रखा, यह दोनों सेवाओं के भीतर और बाहर, क्योंकि इसमें अर्धसैनिक बल भी शामिल हैं।

हमारे सशस्त्र बलों की वर्तमान संरचना

- अभी तक, तीनों सेनाओं के पास थल सेना, नौसेना और वायु सेना के बीच 17 कमांड हैं।
- भले ही ये कमांड एक ही क्षेत्र में काम करते हों, फिर भी ये एक साथ स्थित नहीं होते हैं, और जरूरी नहीं कि उनके परिचालन जिम्मेदारी के क्षेत्र समान हों।

सेना	सात आदेश	उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिण-पश्चिमी और सेना प्रशिक्षण कमान (ARTRAC)।
नौसेना	सात आदेश	उत्तरी, पूर्वी, दक्षिणी, दक्षिण-पश्चिमी, मध्य, ट्रेनिंग और मेंटेनेंस कमांड।
वायु सेना	तीन आदेश	पश्चिमी, पूर्वी-दक्षिणी, जिनमें से दक्षिणी काफी हद तक प्रशिक्षण के बारे में है।
	अंडमान और निकोबार कमान	• यह त्रि-सेवा कमांड है। • इसकी अध्यक्षता तीनों सेनाओं के अधिकारियों द्वारा रोटेशन द्वारा की जाती है।
	सामरिक बल कमान,	• यह त्रि-सेवा कमांड है। • यह भारत की परमाणु संपत्ति के लिए जिम्मेदार है।

इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्या होते हैं?

- सरल शब्दों में, यह एक एकीकृत कमान है जिसके तहत खतरे की धारणा के आधार पर थल सेना, नौसेना और वायु सेना के सभी संसाधनों को एकत्रित किया जाता है।
- कमांड भौगोलिक हो सकते हैं - जैसे किसी विशेष देश के साथ सीमा को देखना - या विषयगत, सभी समुद्री खतरों के लिए एक कमांड की तरह।
- थिएटर कमांड बलों के बीच संयुक्तता को बढ़ाता है और संसाधनों के दोहराव को भी कम करता है।
- दुनिया के कई देशों में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन सहित थिएटर कमांड हैं। भारत में अंडमान और निकोबार कमांड थिएटर कमांड का एक उदाहरण है।

क्या थिएटर कमांड एक नया विचार है?

- भारत में एक एकीकृत त्रि-सेवा कमान बनाने का विचार नया नहीं है - कारगिल संघर्ष के बाद विभिन्न स्तरों पर इसकी सिफारिश की गई थी।

- जनवरी 2020 में जनरल रावत को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किए जाने के बाद, उन्होंने बलों के उप प्रमुखों के साथ विचार-विमर्श किया कि ये आदेश कैसा दिख सकता है।
- 2020 की शुरुआत में, जनरल रावत ने सुझाव दिया था कि इनमें से पहला कमांड, एयर डिफेंस कमांड, 2020 के अंत तक आ सकता है। हालांकि, कोविड -19 महामारी सहित कई कारकों के कारण इस प्रक्रिया में देरी हुई है।

क्या प्रस्ताव विचाराधीन है?

- चार से पांच एकीकृत त्रि-सेवा थिएटर कमांड वाले एक मॉडल पर चर्चा की जा रही है, जिसमें प्रत्येक कमांड का नेतृत्व तीन-सितारा अधिकारी करता है।
- यह अधिकारी, थिएटर कमांडर, चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी (COSC) को रिपोर्ट करेगा, जिसमें तीन सेना प्रमुख शामिल हैं, और इसका नेतृत्व CDS द्वारा स्थायी अध्यक्ष के रूप में किया जाता है।
- यह एक बड़ा बदलाव लाता है - सेना प्रमुखों का वर्तमान में अपने बलों पर सभी परिचालन नियंत्रण है; संचालन शक्तियां अब COSC के पास चली जाएंगी।
- इनमें से प्रत्येक कमांड के पास तीनों बलों की आवश्यक संपत्ति होगी। उन सभी संपत्तियों पर परिचालन नियंत्रण, राष्ट्र की परवाह किए बिना, उस थिएटर के कमांडर के पास रहेगा।

प्रस्तावित आदेश हैं :

- मैरीटाइम थिएटर कमांड, जो पूर्वी और पश्चिमी दोनों समुद्री तटों पर देश की सभी समुद्री सुरक्षा जरूरतों का देखभाल करेगा और इसमें सेना की हवाई हमले की संपत्ति और तीनों बल शामिल होंगे।
- वायु रक्षा कमान, जो देश भर में और बाहर हवाई रक्षा के साथ अनिवार्य होगी। लड़ाकू विमानों के पास टोही और निगरानी संपत्ति भी होगी।
- दो या तीन भूमि आधारित आदेश प्रस्तावित हैं। यदि दो कमांड हैं, तो चीन और पाकिस्तान के साथ भारत की सीमाओं के लिए एक-एक होगी।
- उस क्षेत्र में देश के अद्वितीय क्षेत्र और सुरक्षा जरूरतों के मद्देनजर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत की सीमाओं को देखते हुए एक और कमान रखने का भी प्रस्ताव है।
- **फंक्शनल ट्राई-सर्विसेज कमांड्स:** इन थिएटर कमांड्स के अलावा, निम्नलिखित फंक्शनल कमांड्स पर भी विचार किया जाता है:
    - लॉजिस्टिक्स कमांड, जिसमें एक व्यक्ति के तहत सभी सेवाओं का सैन्य-तंत्र होगा।
    - प्रशिक्षण और सिद्धांत आदेश, ताकि सभी सेवाएं एक सामान्य सिद्धांत के तहत काम करें और कुछ बुनियादी सामान्य प्रशिक्षण हो।

यदि परिचालन में नहीं है तो सेवा की क्या भूमिका होगी?

- अभी तक, सेवाओं को किसी विशेष ऑपरेशन के संचालन के लिए अपनी संपत्ति का अनुरोध करने के लिए आवश्यकता और अत्यावश्यकता के समय एक-दूसरे से बात करनी पड़ती है।
- थिएटर कमांडर की उपस्थिति से सेवा प्रमुखों के पास अपनी संपत्ति पर परिचालन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं होगा।
- इसका मतलब यह नहीं है कि प्रमुखों की भूमिकाएं मानी नहीं जाएंगी। अब उनके पास अपने संबंधित शक्ति को बढ़ाने, प्रशिक्षित करने और बनाए रखने के मुख्य कार्य होंगे।
- साथ ही, चूंकि प्रत्येक प्रमुख COSC का सदस्य होगा और अपने डोमेन का विशेषज्ञ होगा, सभी परिचालन निर्णयों के लिए उसके इनपुट आवश्यक होंगे।

क्या हर कोई प्रस्तावित विचार से खुश है?

- जबकि थल सेना और नौसेना प्रस्ताव के साथ हैं, वायु सेना को कुछ आपत्तियां हैं।
    - वायु सेना नहीं चाहती कि प्रमुख वायु संपत्ति का परिचालन नियंत्रण खो दे।
    - दूसरा, वायु सेना इस बात से चिंतित है कि उसकी सारी संपत्ति इन एकीकृत थिएटरों में विभाजित हो सकती है।

- रक्षा व्यवस्था में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन होने से पहले ऐसी सभी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

बिंदुओं को कनेक्ट करना

- चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ
- रक्षा आत्मनिर्भरता
- भारत के रक्षा व्यापार में चुनौतियाँ
- रक्षा सिद्धांत पर पुनर्विचार
- रक्षा क्षेत्र में हाल के सुधार

विविध

समाचार	विवरणमें
1. WHO के नए सिस्टम में 'डेल्टा' कहे जाने वाला भारत में मिला कोरोना वायरस वेरियंट	• विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने उभरते हुए कोरोना वायरस प्रकारों को लेबल करने के लिए नामों के एक समूह की सिफारिश की है जिन्हें वैश्विक चिंता के रूप में माना जाता है। • भारतीय संस्करण जिसे B.1.617.2 के नाम से जाना जाता था, उसी को 'डेल्टा' कहा जाएगा। • मौजूदा वैज्ञानिक नामकरण प्रणाली भी जारी रहेगी। • विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मामलें के चार रूपों (VOC) की पहचान की गई है: B.1.1.7, B.1.351, P2 और B.1.617.2। • उनके सार्वजनिक लेबल क्रमशः होंगे: अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा
2. विश्व पर्यावरण दिवस	• विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, 2021 को मनाया गया। • इस दिन का उद्देश्य: हमारे पर्यावरण की रक्षा के लिए दुनिया भर में जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करना। • 2021 की थीम: ईको सिस्टम रिस्टोरेशन यानी पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर ध्यान देने के साथ (प्रत्येक महाद्वीप और महासागर में पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण को रोकने, और उलटने के लिए)। • प्रत्येक विश्व पर्यावरण दिवस का एक अलग मेजबान देश होता है, जहां आधिकारिक समारोह होते हैं। • पाकिस्तान वर्ष 2021 के लिये वैश्विक मेज़बान होगा। • भारत के प्रधान मंत्री ने "2020-2025 में भारत में इथेनॉल सम्मिश्रण के लिए रोड मैप पर विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट" जारी की। • सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है।

	• पूरे देश में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिये पुणे में E-100 पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है।
3. ऑपरेशन पैंजिया (Pangea) XIV : इंटरपोल	• हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन (इंटरपोल) ने अपने ऑपरेशन पैंजिया XIV के माध्यम से नकली दवाओं और उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को लक्षित किया। • ऑपरेशन पैंजिया, नकली और अवैध स्वास्थ्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री को बाधित करने के लिए इंटरपोल का एक सुस्थापित अंतरराष्ट्रीय प्रयास है। • पैंजिया अनियमित वेबसाइटों से दवाएं खरीदने से जुड़े जोखिमों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का काम करता है। • वर्ष 2008 में प्रथम ऑपरेशन पैंजिया संचालित किया गया था।
4. एनविज़न मिशन	• यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (European Space Agency- ESA) ने घोषणा की कि उसने एनविज़न को अपने अगले ऑर्बिटर के रूप में चुना है जो 2030 के दशक में किसी समय शुक्र ग्रह (Venus) की यात्रा करेगा। • इसे एरियन 6 रॉकेट द्वारा लॉन्च किया जाएगा। इस अंतरिक्षयान को शुक्र तक पहुँचने में लगभग 15 महीने लगेंगे और कक्षा की परिक्रमा पूरी करने में 16 महीने और लगेंगे। • अंतरिक्ष यान ग्रह के वायुमंडल और सतह का अध्ययन करने, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों की निगरानी करना एवं ग्रह की सतही संरचना का विश्लेषण करने के लिए कई प्रकार के उपकरणों को ले जाएगा। • नासा द्वारा प्रदान किया गया एक रडार सतह की छवि बनाने और उसका नक्शा बनाने में मदद करेगा। • ESA के मिशन का मूल उद्देश्य यह पता लगाना है कि पृथ्वी और शुक्र एक दूसरे से इतने अलग कैसे विकसित हुए कि वे मोटे तौर पर एक ही आकार और संरचना के हैं। • हाल ही में, नासा ने शुक्र ग्रह के लिए दो मिशन - डेविन्सी+ और वेरिटास का चयन किया है।
5. जियो पारसी योजना	• इस योजना के परिणामस्वरूप पारसी समुदाय में जन्मों की संख्या में वृद्धि हुई है। • इसे 2013 में लॉन्च किया गया था। • **उद्देश्य:** भारत में पारसी समुदाय की जनसंख्या में गिरावट को रोकने के लिए • **द्वारा विकसित:** अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय और पारज़ोर फाउंडेशन (Parzor Foundation) • **इसमें तीन घटक शामिल हैं:** सहायक प्रजनन उपचार के लिए चिकित्सा सहायता, समुदाय की वकालत और स्वास्थ्य ।
6. राजा परबा (Raja Parba)	• इसे मिथुन संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। • यह ओडिशा में नारीत्व का उत्सव मनाने वाला तीन दिवसीय त्योहार है। • ऐसा माना जाता है कि, इस अवधि के दौरान, धरती माता को मासिक धर्म होता है और मानसून आते ही भविष्य की कृषि गतिविधियों के लिए खुद को तैयार करती है। • लोग भूदेवी की पूजा करते हैं जो भगवान जगन्नाथ की पत्नी हैं। • महिलाओं को घर के काम से छुट्टी दी जाती है और लोग धरती पर नंगे पांव चलने से बचते हैं।

7. इंडो-थाई कॉर्पाटी	• हाल ही में भारतीय नौसेना और रॉयल थाई नौसेना के बीच भारत-थाईलैंड समन्वय गश्त (इंडो-थाई कॉर्पेट) का 31वां संस्करण मलक्का जलडमरूमध्य के पास अंडमान समुद्र में आयोजित किया गया। • **लक्ष्य:** • वाणिज्यिक नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए हिंद महासागर के हिस्से को सुरक्षित रखना। • समुद्र के कानूनों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए। • **भारत और थाईलैंड के बीच अन्य सैन्य अभ्यास:** • व्यायाम मैत्री (सेना)। • व्यायाम सियाम भारत (वायु सेना)
8. चीन का शेनझोउ-12 मानवयुक्त मिशन	• हाल ही में एक चीनी अंतरिक्ष यान "शेनझोउ-12", जिसमें तीन-व्यक्ति चालक दल थे, चीन के नए अंतरिक्ष स्टेशन मॉड्यूल तियानहे-1 के साथ जोड़ा गया। • यह तियानझोउ-2 कार्गो अंतरिक्ष यान के प्रक्षेपण के बाद आया है, जिसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की थी। • पूर्व सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद चीन तीसरा देश है जिसने अपने दम पर मानवयुक्त मिशन को अंजाम दिया। • यह लंबी अवधि तक अंतरिक्ष यात्रियों के रहने और स्वास्थ्य देखभाल, रीसाइक्लिंग, जीवन समर्थन प्रणाली, अंतरिक्ष सामग्री की आपूर्ति, अतिरिक्त गतिविधियों का संचालन और कक्षा में रखरखाव से संबंधित परीक्षण प्रौद्योगिकियों में मदद करेगा।
9. सिकल सेल एनीमिया	• जनजातीय मामलों के मंत्री ने 'सिकल सेल रोग' पर दूसरे राष्ट्रीय सिकल सेल सम्मेलन का उद्घाटन किया। • यह कॉन्क्लेव प्रतिवर्ष 19 जून 2021 को मनाए जाने वाले विश्व सिकल सेल दिवस को चिह्नित करने के लिए आयोजित किया जाता है। • इस रोग की विशेषता लाल रक्त कोशिका के आकार में एक चिकने, डोनट के आकार से C-आकार के फर्म टूल की तरह होती है। • इन कोशिकाओं में प्लास्टिसिटी की कमी होती है और ये छोटी रक्त वाहिकाओं को अवरुद्ध कर सकती हैं, जिससे रक्त प्रवाह बाधित होता है। यह स्थिति लाल रक्त कोशिका के अस्तित्व को कम कर देती है, और बाद में एनीमिया, जिसे अक्सर सिकल सेल एनीमिया कहा जाता है। • इससे स्थायी तीव्र दर्द सिंड्रोम, गंभीर जीवाणु संक्रमण और परिगलन (मृत ऊतक) हो जाता है। एनीमिया एक चिकित्सा स्थिति है जिसमें लाल रक्त कोशिका की गिनती या हीमोग्लोबिन सामान्य से कम होता है। • **लक्षण:** थकान, सांस लेने में तकलीफ, बालों का झड़ना आदि। • **उपचार:** इसे सरल प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधित किया जा सकता है, जिनमें शामिल हैं: • उच्च तरल पदार्थ का सेवन

	• स्वस्थ आहार • फोलिक एसिड/आयरन अनुपूरण • दर्द की दवाई • संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए टीकाकरण और एंटीबायोटिक्स • कई अन्य चिकित्सीय उपाय। • सिकल सेल रोग (SCD), जो सबसे प्रचलित विरासत में मिला रक्त विकार है, भारत में कई आदिवासी आबादी समूहों में व्यापक है। • भारत में यह रोग मुख्य रूप से झारखंड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिमी ओडिशा, पूर्वी गुजरात और उत्तरी तमिलनाडु और केरल में नीलगिरि पहाड़ियों के इलाकों में प्रचलित है।
10. ग्रीष्म संक्रांति: 21 जून	• 21 जून उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन है, तकनीकी रूप से इस दिन को ग्रीष्म संक्रांति कहा जाता है। • यह एक प्राकृतिक घटना है जो प्रतिवर्ष दो बार होती है, एक बार गर्मियों में और फिर सर्दियों के दौरान, पृथ्वी के प्रत्येक गोलार्ध में ग्रीष्म और शीतकालीन संक्रांति। • उत्तरी गोलार्द्ध में यह वर्ष का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है। • इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे नजदीक होते हैं और सूर्य कर्क रेखा (23.5° उत्तर) पर ऊपर की ओर चमकता है। • संक्रांति के दौरान पृथ्वी की धुरी जिसके चारों ओर ग्रह एक चक्कर पूरा करता है। इस तरह झुका हुआ है कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ है और दक्षिणी ध्रुव इससे दूर है। • आमतौर पर यह काल्पनिक धुरी ऊपर से नीचे तक पृथ्वी के मध्य से होकर गुजरती है और हमेशा सूर्य के संबंध में 23.5 डिग्री झुकी होती है। • आर्कटिक सर्कल में, संक्रांति के दौरान सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। • 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में भी मनाया जाता है।
11. लैंड फॉर लाइफ अवार्ड: यूएन	• हाल ही में राजस्थान के जलवायु कार्यकर्ता श्याम सुंदर ज्ञानी को अपनी 'पारिवारिक वानिकी' (Familiar Forestry), एक पर्यावरण संरक्षण अवधारणा, के लिए इस वर्ष का संयुक्त राष्ट्र का प्रतिष्ठित 'लैंड फॉर लाइफ अवार्ड' (Land For Life Award) प्रदान किया गया है। • 'पारिवारिक वानिकी' (Familial Forestry) का तात्पर्य, वृक्षों और पर्यावरण की देखभाल को परिवार में सौंप देना है, जिससे वृक्ष, परिवार की चेतना का हिस्सा बन जाते हैं। • संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन (UNCCD), भूमि के संतुलन की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को पहचानने के लिए हर दो साल में लैंड फॉर लाइफ अवार्ड का आयोजन करता है। • यह पुरस्कार संतुलन में भूमि की दिशा में प्रयासों में उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देता है। • इस पुरुस्कार को वर्ष पुरस्कार 2011 में कोरिया गणराज्य में पार्टियों के UNCCD सम्मेलन (COP)10 में चांगवोन पहल के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। • चांगवोन पहल का उद्देश्य रणनीति (2008-18 के लिए) और (COP) 10 निर्णयों के अनुसार

	की जा रही गतिविधियों को पूरक बनाना है।
12. राजस्थान में चौथा टाइगर रिजर्व	• हाल ही में बूंदी रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) की तकनीकी समिति से राजस्थान का चौथा बाघ अभयारण्य बनने की अनुमति मिली है। **राजस्थान के अन्य तीन टाइगर रिजर्व:** • सवाई माधोपुर में रणथंभौर टाइगर रिजर्व (RTR) • अलवर में सरिस्का टाइगर रिजर्व (एसटीआर) • कोटा में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व (MHTR) **बाघ की सुरक्षा स्थिति** • भारतीय वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972: अनुसूची I • IUCN रेड लिस्ट: लुप्तप्राय। • CITES: परिशिष्ट I। • टाइगर टास्क फोर्स की सिफारिशों के बाद 2005 में NTCA शुरू किया गया था। • यह पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का एक सांविधिक निकाय है, जिसकी एक व्यापक पर्यवेक्षी/समन्वय भूमिका है, जो वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 में प्रदान किए गए कार्यों का निष्पादन करता है।

13. डेल्टा प्लस वैरिएंट	• केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेल्टा प्लस वैरिएंट (B.1.617.2.1) को चिंता के एक प्रकार के रूप में वर्गीकृत किया है।
	  ○ डेल्टा की तरह इसमें RNA वायरस के स्पाइक प्रोटीन क्षेत्र में उत्परिवर्तन होता है जिससे यह अधिक संक्रमणीय हो जाता है।
	• WHO किसी वैरिएंट को चिंता के रूप में तब वर्गीकृत करता है जब वह इससे जुड़ा होता है:
	  ○ संप्रेषणीयता में वृद्धि
	  ○ विषाणु में वृद्धि या क्लीनिकल रोग प्रस्तुति में परिवर्तन
	  ○ सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों की प्रभावशीलता में कमी या निदान, टीके और चिकित्सीय की उपलब्धता में कमी।

14. गुजरात अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मध्यस्थता केंद्र (GIMAC)	• हाल ही में गिफ्ट (गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी) सिटी में गुजरात मैरीटाइम यूनिवर्सिटी और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के बीच एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किये गए हैं। • यह देश में अपनी तरह का पहला केंद्र होगा जो समुद्री और शिपिंग क्षेत्र से संबंधित विवादों के साथ मध्यस्थता की कार्यवाही का प्रबंधन करेगा। • GIMAC एक समुद्री क्लस्टर का हिस्सा होगा जिसे गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) गांधीनगर में गिफ्ट सिटी में स्थापित कर रहा है। • **लाभ:** ○ तेजी से विवाद समाधान को सुगम बनाना।

	○ अंतरराष्ट्रीय समुद्री समुदाय के बीच गिफ्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन (SEZ) के आकर्षण को बढ़ाना। ○ व्यापार करने की सुगमता में वृद्धि करना। ○ न्यायालयों पर बोझ कम करना।
15. बैहेतन बाँध	• हाल ही में चीन ने विश्व के दूसरे सबसे बड़े जलविद्युत बांध, बैहेतन बांध का संचालन शुरू किया है। ○ थ्री गोरजेस डैम (Three Gorges Dam) दुनिया का सबसे बड़ा जलविद्युत बांध है और यह चीन की यांग्त्ज़ी नदी के किनारे है। • यह जिंशा नदी पर है, जो यांग्त्ज़ी (एशिया की सबसे लंबी नदी) की एक सहायक नदी है। • इसे 16,000 मेगावाट की कुल स्थापित क्षमता के साथ बनाया गया है। • यह अंततः एक दिन में इतनी बिजली पैदा करने में सक्षम होगा, जो तकरीबन 500000 लोगों की एक वर्ष की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने के लिये पर्याप्त होगी। • यह अधिक जलविद्युत क्षमता का निर्माण करके जीवाश्म ईंधन की बढ़ती मांग को रोकने के चीनी प्रयासों का हिस्सा है। • **चिंताएँ:** ○ एक विशाल बांध नदी द्वारा ढोई गई भारी मात्रा में गाद को रोक सकता है जो इससे नदी के निचले इलाकों में खेती प्रभावित हो सकती है। ○ भारत भी मानसून के दौरान पानी छोड़े जाने को लेकर चिंतित है। ○ पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में इसके विनाशकारी परिणाम हो सकते हैं। ○ सैकड़ों हजारों स्थानीय समुदायों का ज्यादा स्थानांतरण।

अपने ज्ञान का परीक्षण करें

मॉडल प्रश्न: (उत्तर अंत में दिए गए हैं)

Q.1 भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े कौन जारी करता है?

a) NSSO b) CSO
c) नीति आयोग d) निम्नलिखित में से कोई नहीं

Q.2 निम्नलिखित में से कौन बागवानी फसलों के अंतर्गत नहीं आता है?

a) सब्जियों की जड़ें
b) सुगंधित पौधे
c) पॉटेड सजावटी पौधे
d) मक्का

Q.3 AmbiTag के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. खराब होने वाले उत्पादों के परिवहन के दौरान वास्तविक समय परिवेश का तापमान।
2. इसे हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया था।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.4 लिटोरिया मीरा निम्न में से किसकी एक प्रजाति है जो न्यू-गिनी के वर्षावनों में रहती है?

a) मेंढक b) सांप

c) कछुआ d) छिपकली

Q.5 निम्नलिखित में से किसने एक योजना शुरू की है जो भारत सरकार के "एक राष्ट्र एक मानक" दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए "एसडीओ की मान्यता" प्रदान करती है।

a) नीति आयोग

b) स्वास्थ्य मंत्रालय

c) भारतीय मानक ब्यूरो

d) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड

Q.6 सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन (SATAT) पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह संपीडित बायो-गैस उत्पादन संयंत्रों की स्थापना के उद्देश्य से एक पहल है।

2. पहल पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई।

उपरोक्त में से कौन सा सही है या सही है?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.7 भारत में पाए जाने वाले नए कोरोनावायरस वेरिएंट को WHO सिस्टम में क्या कहा गया?

a) अल्फा b) बीटा

c) गामा d) डेल्टा

Q.8 निम्नलिखित में से कौन शंघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है?

a) चीन b) ताजिकिस्तान

c) भारत d) जापान

Q.9 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के लिए शुरू की गई एक पहल है।

2. यह 200 दिनों के वेतन रोजगार की गारंटी देता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 2

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.10 'ग्लोबल कोच प्रोग्राम' पहल निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू की गई है?

a) विश्व स्वास्थ्य संगठन b) एमनेस्टी इंटरनेशनल

c) विश्व बैंक d) यूनिसेफ

Q.11 स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (CEM) औद्योगिक डीप डीकार्बोनाइजेशन इनिशिएटिव निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया?

a) यूएसए और जापान

b) चीन और श्रीलंका

c) फ्रांस और रूस

d) भारत और यूके

Q.12 राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (NIRD & PR) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संगठन है।

2. यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज में उत्कृष्टता का एक प्रमुख राष्ट्रीय केंद्र है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1

b) केवल 3

c) 1 और 2 दोनों

d) न तो 1 और न ही 2

Q.13 'देविका नदी' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य/केंद्र शासित प्रदेश से निकलती है?

a) नासिक b) कोच्चि

c) उत्तराखंड d) जम्मू और कश्मीर

Q.14 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. भारत सरकार ने 2025 तक पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिश्रण के लक्ष्य को पूरा करने का संकल्प लिया है।
2. दिल्ली में E-100 पायलट प्रोजेक्ट हाल ही में पूरे भारत में इथेनॉल के उत्पादन और वितरण के लिए शुरू किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.15 एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. APEC एक क्षेत्रीय आर्थिक मंच है।
2. भारत APEC के सदस्यों में से एक है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.16 खाद्य मूल्य सूचकांक निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है?

A) विश्व बैंक
B) खाद्य और कृषि संगठन
c) विश्व आर्थिक मंच
d) आर्थिक सहयोग और विकास का संगठन

Q.17 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें 'लोगों, प्रकृति और जलवायु के लिए पारिस्थितिकी तंत्र बहाली' रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष:

1. यह जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन द्वारा प्रकाशित किया गया।
2. एक तिहाई वाणिज्यिक मछली प्रजातियों का अत्यधिक दोहन किया जाता है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
ग) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.18 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. पिछले वर्ष की तुलना में रक्षा क्षेत्र के लिए 2020-21 में 10% बजट वृद्धि हुई है।
2. 'अटल सुरंग' का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया गया।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.19 गोबर-धन (गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो-एग्रो रिसोर्सेज) योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे कृषि मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया।
2. इसका उद्देश्य बायोडिग्रेडेबल कचरे को संपीड़ित बायोगैस (सीबीजी) में परिवर्तित करके किसानों की आय में वृद्धि करना है।

उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?

a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.20 'हिंदू कुश' हिमालयी क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश में विस्तृत नहीं है?

a) चीन
b) भारत
c) वियतनाम
d) बांग्लादेश

Q.21 ऑपरेशन पैंजिया, निम्नलिखित में से किसे बाधित करने के लिए इंटरपोल का एक सुस्थापित अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है?

a) बाल तस्करी
b) नकली और अवैध स्वास्थ्य उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री
c) साइबर-धमकी
d) आतंकवादी गतिविधियां

Q.22 ट्रेन टक्कर बचाव प्रणाली (TCAS) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।

1. इसे भारत में स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है।
2. यह मौजूदा बुनियादी ढांचे का उपयोग करके अधिक ट्रेनों को समायोजित करने के लिए सुरक्षा में सुधार और लाइन क्षमता बढ़ाने में मदद करेगा।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.23 निम्नलिखित में से किस राज्य ने शहरी क्षेत्रों में 50 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों को विरासत वृक्ष करार देकर उनकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए एक कार्य योजना पारित की है?
a) मणिपुर b) महाराष्ट्र
c) मध्य प्रदेश d) मेघालय

Q.24 'उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण' (AISHE) 2019-20 रिपोर्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. महिला नामांकन में कुल मिलाकर 18% से अधिक की वृद्धि हुई है।
2. राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों में छात्राओं की हिस्सेदारी सबसे कम है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.25 'एनविज़न मिशन' यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ESA) का निम्नलिखित में से किसके लिए मिशन है?
a) बृहस्पति b) चंद्रमा
c) शुक्र d) आर्कटिक ध्रुव

Q. 26 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. CACP उर्वरक मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है।
2. तोरिया और छिलके वाले नारियल के MSPs रेपसीड/सरसों और खोपरा के MSPs के आधार पर तय किए जाते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.27 'जियो पारसी योजना' निम्नलिखित में से किसके द्वारा विकसित की गई है?
a) अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय
b) पारज़ोर फाउंडेशन
c) नीति आयोग
d) दोनों (a) और (b)

Q.28 'FAME योजना' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 का एक हिस्सा है।
2. इसका उद्देश्य इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहन प्रौद्योगिकी के निर्माण को बढ़ावा देना और उसका सतत विकास सुनिश्चित करना है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.29 'गहिरमाथा समुद्री अभयारण्य' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है?
a) पश्चिम बंगाल b) ओडिशा
c) महाराष्ट्र d) केरल

Q.30 भारत द्वारा जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पहल की गई है?
1. स्वदेशी कार्यक्रम
2. मानव जीनोम परियोजना
3. जीनोम इंडिया परियोजना

सही कोड चुनें:
a) केवल 1 और 2
b) केवल 1 और 3
c) केवल 2 और 3
d) 1, 2 और 3

Q.31 'राजा परबा' भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का त्योहार है?
a) ओडिशा b) तमिलनाडु
c) असम d) पंजाब

Q.32 निम्नलिखित में से किस नदी को "बिहार का शोक" कहा जाता है?
a) गंगा b) यमुना
c) ब्रह्मपुत्रd) कोसी

Q.33 'अभ्यास मैत्री' निम्नलिखित में से किस देश के बीच आयोजित किया जाता है?
a) भारत और नेपाल
b) भारत और चीन
c) भारत और वियतनाम
d) भारत और थाईलैंड

Q.34 भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है?
a) अनुसूचित जनजाति
b) दलबदल के आधार पर सांसदों और विधायकों की अयोग्यता
c) पंचायतें
d) मान्यता प्राप्त राजभाषाएं

Q.35 अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) निम्नलिखित में से किस देश द्वारा शुरू किया गया?
a) भारत और फ्रांस
b) भारत और चीन
c) भारत और यूएसए
d) भारत और रूस

Q.36 ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर (ECEC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह सिक्किम से तमिलनाडु तक फैला है।
2. ECEC के विकास में ADB भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है।
निम्नलिखित में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो और न ही 2

Q.37 निम्नलिखित में से कौन 'डीप ओशन मिशन' (DOM) के लिए नोडल मंत्रालय होगा?
a) पर्यावरण मंत्रालय
b) रक्षा मंत्रालय
c) विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
d) पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MoES)

Q.38 सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस शहर में एक जहाज़ बनाने का स्थान था?
a) लोथल b) हड़प्पा
c) मोहनजोदड़ो d) धोलावीरा

Q.39 भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह केवल वित्तीय साइबर अपराध से संबंधित है।
2. इसका केंद्र नई दिल्ली में स्थित है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.40 'सिकल सेल एनीमिया' के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. रोग की विशेषता लाल रक्त कोशिका के आकार में एक चिकने, डोनट-आकार से C-आकार में संशोधन द्वारा होती है।
2. सिकल सेल रोग (SCD), जो सबसे प्रचलित विरासत में मिला रक्त विकार है, भारत में कई आदिवासी आबादी समूहों में व्यापक है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1

b) केवल 2
C) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.41 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. GM फसलों के अनुमोदन के लिए नियामक ढांचा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आता है।
2. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत जेनेटिक इंजीनियरिंग मूल्यांकन समिति सर्वोच्च निकाय है जो भारत में GM फसलों की व्यावसायिक रिलीज की अनुमति देती है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.42 ग्रीष्म संक्रांति में भूमध्य रेखा के दक्षिण में मौसम होता है?
a) गर्मी b) सर्दी
c) शरद ऋतु d) वसंत

Q.43 हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौते (IOSEA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत हिंद महासागर समुद्री कछुआ समझौते (IOSEA) का हस्ताक्षरकर्ता नहीं है।
2. यह एक ढांचा तैयार करता है जिसके माध्यम से हिंद महासागर और दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के राज्य मिलकर समुद्री कछुओं की घटती आबादी के संरक्षण और भरपाई के लिए मिलकर काम करते हैं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.44 संयुक्त राष्ट्र का 'लैंड फॉर लाइफ अवार्ड' निम्नलिखित में से किसके द्वारा आयोजित किया जाता है?
a) UNICEF b) WHO
c) UNFCCC d) UNCCD

Q.45 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA), 2013 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. 75% ग्रामीण आबादी और 50% तक शहरी आबादी इसके अंतर्गत आती है।
2. गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बारह महीने बाद तक भोजन और मातृत्व लाभ 6,000 रुपये से कम नहीं।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.46 परिसीमन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
2. यह भारत के चुनाव आयोग के सहयोग से काम करता है।
उपरोक्त में से कौन सा सही है/या सही हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.47 प्रवाल भित्तियाँ कैसे बनती हैं?
a) ज्वालामुखियों के कठोर लावा से
b) समुद्र तल से ऊपर उठे मजबूत चट्टानों से
c) कठोर समुद्री नमक से
d) छोटे जीवों जिसे पॉलीप्स कहते हैं

Q.48 निम्नलिखित में से कौन हाल ही में राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व बना है?
a) भद्रा वन्यजीव अभयारण्य
b) चिनार वन्यजीव अभयारण्य
c) कच्छ रेगिस्तान वन्यजीव अभयारण्य
d) रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य

Q.49 WHO किसी वैरिएंट को एक चिंता के रूप में वर्गीकृत करता है जब वह इससे जुड़ा होता है:
1. संप्रेषणीयता में वृद्धि

2. विषाणु में वृद्धि या क्लीनिकल रोग प्रस्तुति में परिवर्तन
3. सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों की प्रभावशीलता में कमी
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 और 2
b) केवल 2 और 3
c) केवल 1, 2 और 3
d) केवल 3

Q.50 निम्नलिखित में से कौन भारतीय अंटार्कटिक कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है?
a) दक्षिण ज्ञानगोत्री b) हिमाद्री
c) मैत्री d) भारती

Q. 51 निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. BPO एक व्यावसायिक अभ्यास है जिसमें एक संगठन एक बाहरी सेवा प्रदाता के साथ आवश्यक व्यावसायिक कार्य करने के लिए अनुबंध करता है।
2. OSPs या अन्य सेवा प्रदाता कंपनियां या फर्म हैं जो विभिन्न कंपनियों के लिए टेलीमार्केटिंग, टेलीबैंकिंग या टेलीमेडिसिन जैसी माध्यमिक या तृतीयक सेवाएं प्रदान करती हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.52 धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. मनी लॉन्ड्रिंग कम से कम 3 साल और अधिकतम 7 साल के कठोर कारावास और जुर्माना के साथ दंडनीय है।
2. संपत्ति को "अपराध की आय" माना जाता है और इसे 180 दिनों के लिए अस्थायी रूप से संलग्न किया जा सकता है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.53 अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
a) संयुक्त अरब अमीरात b) फ्रांस
c) बेल्जियम d) गुरुग्राम

Q.54 LiDAR के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. यह एक सुदूर संवेदन विधि है जो रेंज और परिवर्तनशील दूरियों को मापने के लिए स्पंदित लेजर के रूप में प्रकाश का उपयोग करती है।
2. ये प्रकाश स्पंद पृथ्वी के आकार और इसकी सतह की विशेषताओं के बारे में सटीक, त्रि-आयामी जानकारी उत्पन्न करते हैं।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.55 ड्रग्स एंड क्राइम पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (UNODC) के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इसकी विश्व ड्रग रिपोर्ट 2021 में-
1. नशीली दवाओं के उपयोग के कारण होने वाली बीमारी के सबसे बड़े बोझ के लिए ओपिओइड का खाता जारी है।
2. कोरोनावायरस महामारी के दौरान फार्मास्युटिकल दवाओं के गैर-चिकित्सीय उपयोग में भी वृद्धि देखी गई।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.56 निम्न में से कौन स्पर्म व्हेल की IUCN रेड लिस्ट स्थिति है?
a) कमजोर b) लुप्तप्राय
c) कम से कम चिंताd) विलुप्त

Q.57 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. INS कदंबा कर्नाटक में कारवार के पास स्थित एक भारतीय नौसेना बेस है।
2. INS कदंबा वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1 b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों d) न तो 1 और न ही 2

Q.58 अग्नि-P(प्राइम) के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-

1. 'अग्नि प्राइम' 'अग्नि-1' मिसाइल का उन्नत संस्करण है।
2. यह कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 1000 किमी से 1500 किमी होगी।
उपरोक्त में से कौन-सा/से सही है/हैं?
a) केवल 1
b) केवल 2
c) 1 और 2 दोनों
d) न तो 1 और न ही 2

Q.59 निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महालेखाकार के कार्यालय से संबंधित है?

a) अनुच्छेद 67 b) अनुच्छेद 76
c) अनुच्छेद 86 d) अनुच्छेद 96

Q.60 निम्नलिखित में से कौन पदोन्नति में आरक्षण से संबंधित नहीं है?

a) नागराज निर्णय b) इंदिरा साहनी मामला
c) जरनैल सिंह केस d) केशवानंद भारती

Q.61 अनुच्छेद-370 के निरस्त होने के कारण निम्नलिखित में से क्या हुआ?

a) मौलिक कर्तव्यों को लागू करने योग्य बनाया गया
b) जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण
c) तेलंगाना राज्य का निर्माण
d) 8वीं अनुसूची से कुछ भाषाओं का विलोपन

जून 2021 महीने के करेंट अफेयर्स MCQs की उत्तरकुंजी

1 B	2 D	3 A	4 A

5	C	22	C	39	B	56	A
6	C	23	B	40	C	57	C
7	D	24	C	41	C	58	C
8	D	25	C	42	B	59	B
9	D	26	B	43	B	60	D
10	C	27	D	44	D	61	B
11	D	28	C	45	A		
12	C	29	B	46	C		
13	D	30	B	47	D		
14	A	31	A	48	D		
15	A	32	D	49	C		
16	B	33	D	50	B		
17	B	34	D	51	C		
18	C	35	A	52	C		
19	A	36	B	53	A		
20	C	37	D	54	C		
21	B	38	A	55	C		